राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

कैबिनेट में सात मिनट में हो गया था कश्मीर पर फैसला

>> 5

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 61

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 10 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

कश्मीर के नए सच को स्वीकार करे पाकिस्तान

सलाह ▶ विदेश मंत्रालय ने कहा, रिश्ते तोड़ने वाले कदमों पर करे पुनर्विचार

कहा, दुनिया के सामने कश्मीर की गंभीर स्थिति पेश करने के लिए फैला रहा झूठ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर को लेकर दुनिया भर में अनर्गल प्रलाप में लगे पाकिस्तान को भारत ने फिर लताड़ लगाई है। भारत ने साफ कहा, पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर की नई सच्चाई को स्वीकार करे और झूठ फैलाना बंद करे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास की जो संभावना बनी है उससे पड़ोसी देश डर गया है। उसे लगने लगा है कि वह अब कश्मीर में आतंकवाद का खेल नहीं खेल सकेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में अनुच्छेद 370 हटाने की वजहें स्पष्ट कर दी थीं। यह कदम राज्य में विकास को गति देने वाला और आम जनता के आर्थिक हितों को बेहतर करने वाला साबित होगा। इसी से घबराकर पाक बेसिर पैर के कदम उठा रहा है।

रवीश कुमार फाइल फोटो

घाटी में हालात नियंत्रण में

रवीश कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोगों को पर्याप्त खाद्य उत्पादों आदि की आपूर्ति हो सके। अस्पताल भी सामान्य तौर पर चल रहे हैं। पाकिस्तान को इस बात की सच्चाई समझनी चाहिए और भारत के साथ रिश्तों को तोड़ने वाले जो कदम उठा रहा है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

थार एक्सप्रेस बंद करना बौखलाहट : रवीश ने कहा, पाक ने बौखलाहट में ही दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन थार एक्सप्रेस को भी बंद करने का एलान किया है। एक दिन पहले समझौता एक्सप्रेस बंद करने की घोषणा की थी। जबकि, भारतीय रेल अधिकारियों ने कहा था कि समझौता एक्सप्रेस बंद नहीं की गई है। उसके पहले दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को पूरी तरह से रोकने समेत कई दूसरे फैसले भी किए थे। थार एक्सप्रेस जोधपुर से पाकिस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक शहर कराची के बीच सप्ताह में एक बार चलाई जाती है। वर्ष 2006 में तकरीबन 41 वर्षों तक बंद रहने के बाद इस रूट पर ट्रेन परिचालन शुरू हुआ था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के इन कदमों को एकतरफा बताया और कहा कि उसकी मंशा दुनिया के सामने कश्मीर की गंभीर स्थिति पेश करने की है जो हकीकत से काफी दूर है।

370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला: रवीश कुमार ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। पाक जान गया है कि कश्मीर में विकास होगा तो वह आतंकवाद के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं कर सकेगा।

सुरक्षा बलों की तैनाती अस्थायी : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रवीश कुमार ने कहा कि जहां तक जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का मामला है यह अस्थाई तौर पर उठाया गया कदम है। स्थिति सामान्य होने के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती कम की जाएगी।

शिमला समझौते से हो कश्मीर मुद्दे का हल : चीन

बीजिंग, प्रेट्र : कश्मीर पर मदद की उम्मीद में शुक्रवार को चीन पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की लेकिन निराशा ही मिली। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह भारत-पाक दोनों को मित्रवत पड़ोसी मानता है और चाहता है कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और शिमला समझौते के तहत कश्मीर मसले को सुलझाएं।

जयशंकर कल जाएंगे चीन

नई दिल्ली : भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को चीन जा रहे हैं। जयशंकर की यात्रा का एजेंडा बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर जयशंकर की यात्रा के दौरान कश्मीर का मुद्दा भी उठेगा लेकिन यह मुख्य तौर पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सितंबर, 2019 में होने वाली भारत यात्रा की तैयारियों को लेकर है।

पटेल जयंती पर केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जम्मू-कश्मीर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर को गठन होगा। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि राज्य का विभाजन 31 अक्टूबर से अमल में आएगा। यह तिथि इसलिए खास है क्योंकि यह अखंड भारत का सपना देखने वाले लौहपुरुष वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बतौर गृह मंत्री पटेल ने देशभर की रियासतों को जोड़ने का काम किया था, लेकिन जम्मू-कश्मीर ही एकमात्र राज्य था जो शामिल होते हुए भी स्वायत्त रहा। जम्मू-कश्मीर का मसला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू देख रहे थे। संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान पटेल और नेहरू की भूमिका पर जोरदार बहस हुई थी।

अब इमरान ने भारत पर युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लगाए आरोप पेज>>5

एक नई आजादी...

मजदूरी संहिता कानून से न्यूनतम मजदूरी के साथ पुरुषों के समान महिलाओं को मजदूरी देना सुनिश्चित होगा। पेज 3

जय हिंद

मैंने आजादी की दुल्हन को सिंदूर तक दे दिया...

भागलपुर : आइये, 1942 का रुख करते हैं। आजादी की दुल्हन को संवारने में सर्वस्व न्योछावर कर देने वाली सुदामा देवी की बूढ़ी आंखों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सिंदूर तक दे दिया।

• पेज 13

ताकत वतन की हमसे है...

सरोकार

शिक्षा, प्रण और प्रेरणा के बूते गरीबी को दी निर्णायक मात

जेएनएन : गरीबी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार दो गरीब परिवारों के संघर्ष की प्रेरक कहानी। जहां निर्धन माता-पिता ने सोच और श्रम के बूते अपने बच्चों को शिक्षा की सिद्धी दी और पीढ़ियों को समृद्धि का अक्षय उपहार। (पेज-13)

अयोध्या मामले की होगी रोजाना सुनवाई

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की जल्द सुनवाई पूरी होकर नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद जगी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह मामले पर रोजाना सुनवाई करेगा जैसा कि उसने पहले आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से सप्ताह में पांचों दिन सुनवाई का विरोध करते हुए कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। यह शायद पहला मौका होगा जबकि संविधान पीठ किसी मामले की सुनवाई सप्ताह के पांचों दिन कर रही है। सामान्य तौर पर संविधान पीठ नियमित सुनवाई के लिए तय सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही सुनवाई करती है।

अयोध्या मामले पर अब मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। सोमवार को बकरीद की छुट्टी के कारण कोर्ट बंद रहेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है। कोर्ट की तरफ से स्थिति साफ होने से स्पष्ट हो गया है कि अयोध्या पर सुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक पांचों दिन होगी। अगर ऐसा होता है तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत होने (17 नवंबर) तक कोर्ट के पास सुनवाई के लिए कुल 57 दिन होंगे। ऐसे में उम्मीद है कि तब तक सुनवाई पूरी होकर फैसला आ जाएगा।

अदालत में चौथा दिन

- मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति की स्पष्ट
- गोगोई के सेवानिवृत्त होने तक कोर्ट के पास सुनवाई के लिए कुल 57 दिन

शुक्रवार को जैसे ही चौथे दिन की सुनवाई के लिए कोर्ट बैठा, मुस्लिम पक्ष (एम. सिद्दिकी और ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड) के वकील राजीव धवन ने कोर्ट से सप्ताह में पांचों कार्यदिवस पर सुनवाई होने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह सुनवाई चली तो 'अमानवीय' होगा और वह इस मामले में बहस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें दिन भर सुनवाई के बाद अगले दिन की तैयारी करनी होगी, रिसर्च करना होगा। फैसला पढ़ना होगा। धवन ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि पीठ के न्यायाधीशों में जस्टिस चंद्रचूड़ को छोड़ कर किसी ने रिसर्च नहीं की होगी। हाईकोर्ट का पूरा फैसला नहीं पढ़ा होगा। धवन की दलील पर हिंदू पक्ष रामलला के वकील के. परासरन ने कहा कि कोई पक्ष कोर्ट से यह नहीं कह सकता कि उसे कैसे सुनवाई करनी चाहिए। यह न्याय का मंदिर है। वह यहां प्रतिदिन आते हैं, यह सरस्वती की पूजा है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी। जब आपका नंबर आए और आपको बीच में विश्राम लेने की जरूरत लगे तो आप बता दीजियेगा। कोर्ट ने इस मामले को छह अगस्त से नियमित सुनवाई पर लगाने का आदेश देते वक्त ही कहा था कि मामले पर रोजाना सुनवाई की जाएगी।

आकार प्रकार में नहीं कण-कण में हैं भगवान

नई दिल्ली : रामलला की ओर से शुक्रवार को जन्मस्थान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए कहा गया कि उसके वही अधिकार हैं जो किसी मनुष्य के होते हैं। वरिष्ठ वकील के. परासरन ने कहा, भगवान कण-कण में हैं। उनका कोई एक निर्धारित आकार-प्रकार नहीं हो सकता। वे मूर्ति में भी हैं और निराकार भी। (पेज-6)

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली एम्स में भर्ती

नई दिल्ली, एजेंसियां : पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली (66) को शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे घबराहट और बेचैनी की शिकायत के बाद दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों व नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना।

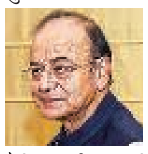

सूत्रों ने बताया कि उन्हें एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है जिसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट शामिल हैं। जेटली के परिवार के सदस्य अस्पताल में उनके साथ हैं। इस साल मई में भी उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। पेशे से वकील अरुण जेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। कई बार वह सरकार के लिए प्रमुख ट्रब्रुलशूटर के रूप में उभरे। खराब स्वास्थ्य की वजह से इस साल उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था।

विधायक सेंगर पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में आरोप तय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- उन्नाव दुष्कर्म कांड में तीस हजारी कोर्ट ने शशि सिंह पर भी तय किए आरोप

तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर शुक्रवार को पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए। वहीं, सह आरोपति शशि सिंह पर साजिश रचने और अपहरण के आरोप तय किए गए। सेंगर और शशि ने खुद को निर्दोष बताया है। अदालत ने गवाही के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त सुबूत हैं। अदालत ने विधायक सेंगर के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) की धारा 3 व 4 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (दुष्कर्म) की धाराओं के तहत आरोप तय किए। सेंगर पर पहला आरोप है कि उसने जून 2017 को नौकरी दिलाने के नाम पर सहयोगी शशि के साथ मिलकर साजिश रची और परिजनों की सहमति के बिना 16-17 साल की किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने का अपराध किया। दूसरा आरोप तय हुआ कि किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। अदालत ने पीड़ित किशोरी व उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप तय किया। पॉक्सो की धारा-3 एवं धारा-4 के तहत किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप तय किया गया। इसके बाद अदालत ने सेंगर से पूछा कि क्या वह गलती स्वीकार करते हैं?

कुलदीप ने इन्कार करते हुए कहा, वह मुकदमे का सामना करेंगे। वहीं, गुरुवार को सीबीआइ ने कोर्ट में कहा था कि पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के मामले में गलत फंसाया गया था। आरोपितों ने पुलिस से मिलीभगत कर हथियार की बरामदगी करवाई थी। पुलिसकर्मियों और आरोपितों के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत का डाटा भी उपलब्ध है। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य आरोपित हैं।

18 गवाहों को मुहैया कराई गई सुरक्षा पेज>>6

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

आज होगा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष का फैसला

नई दिल्ली : कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी या राहुल गांधी के उत्तराधिकारी की तलाश जारी रहेगी शनिवार को इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस कम से कम गांधी परिवार से बाहर का अपना नया अंतरिम अध्यक्ष तो चुन ही लेगी। इस मामले में मुकुल वासनिक का नाम सबसे आगे चल रहा है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

आइआरसीटीसी ई-टिकट पर लगाएगी सर्विस चार्ज

नई दिल्ली : आइआरसीटीसी के माध्यम से खरीदा गया ई-टिकट महंगा हो जाएगा। दरअसल, रेलवे ने तीन साल बाद फिर से ई-टिकटों पर सर्विस चार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। तीन साल पहले मोदी सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे हटा लिया गया था।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

बिल्डर के दिवालिया होने पर नहीं डूबेगी खरीदारों की रकम

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन वाले कानून को सही ठहराते हुए फ्लैट खरीदारों को वित्तीय कर्जदाता का मिला दर्जा बरकरार रखा है। इसका अर्थ है कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करती या होती है, तो संपत्ति की नीलामी से हासिल रकम में घर खरीददारों को भी हिस्सा मिलेगा।

दिल्ली में गवाहों के लिए ढाल बनेगी केजरीवाल सरकार

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

- दिल्ली में जल्द लागू होगी 'गवाह संरक्षण नीति 2019'
- गवाह पर हमला करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान

दिल्ली में गवाहों और उनके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार गवाहों की हिफाजत के लिए सख्त नीति बना रही है, जिसमें उन्हें सुरक्षा देने के साथ ही हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी होगा। इस नीति को गवाह संरक्षण नीति 2019 नाम दिया गया है।

राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गवाहों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे माहौल में गवाह के पलट जाने की संभावना रहती है। गवाहों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू के खिलाफ गवाही देने वाले महेंद्र चावला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला संज्ञान में लिया था। महेंद्र चावला ने आसाराम से जान का खतरा होने की बात कही थी। इस पर वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से गवाहों की सुरक्षा के लिए नीति बनाने को कहा था। इस पर काम चल रहा था, लेकिन उन्नाव की घटना के बाद दिल्ली सरकार और गंभीर हो गई है। कार पर ट्रक से हमले में एक अहम गवाह की मौत हो गई और दुष्कर्म पीड़िता व उसका वकील गंभीर से घायल हैं।

दिल्ली सरकार गवाह संरक्षण नीति 2019 पर काम कर रही है। इसमें गवाह की पहचान को सुरक्षित रखना और उसे नई पहचान देने सहित गवाहों के संरक्षण के लिए कई प्रावधान हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों से कहा है कि नीति को इस तरह तैयार की जाए कि दिल्ली में कोई भी अपराधी गवाहों को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सके।

दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय को बेस्ट क्रिटिक का राष्ट्रीय पुरस्कार

जेएनएन, नई दिल्ली : राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय को बेस्ट क्रिटिक का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके तहत अनंत विजय को राष्ट्रपति स्वर्ण कमल प्रदान करेंगे। फिल्मों पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के पुरस्कार की घोषणा जूरी के अध्यक्ष उत्पल बोरपुजारी ने की। अनंत विजय दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में हर रविवार को स्तंभ लिखते हैं। इन लेखों के लिए ही उन्हें अवार्ड के लिए चुना गया। जमालपुर (बिहार) के अनंत विजय दो दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अब तक उनकी 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 'बॉलीवुड सेल्फी' और 'मार्क्सवाद का अर्धसत्य' को खासी प्रसिद्धि मिली है।

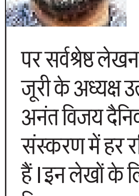

आयुष्मान-विक्की बेस्ट एक्टर पेज>>7

आखिरकार नाडा की छतरी के नीचे आने को तैयार हुआ बीसीसीआइ

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- सरकार के लगातार दबाव बनाने के बाद झुका दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड
- क्रिकेट बोर्ड को आरटीआइ के दायरे में लाने का रास्ता खुला

लंबे समय तक मना करने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) आखिरकार शुक्रवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था (नाडा) के अंतर्गत आने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ ही बीसीसीआइ को राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ) और आरटीआइ के दायरे में लाने की नींव भी पड़ गई। जल्द ही खेल मंत्रालय इसके लिए भी बीसीसीआइ पर दबाव बनाएगा।

खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया, नाडा के डीजी नवीन अग्रवाल बीसीसीआइ सीईओ राहुल जौहरी और बीसीसीआइ के जीएम (क्रिकेट ऑपरेशंस) सबा करीम ने शुक्रवार को राजधानी में मुलाकात की। जुलानिया ने कहा कि बोर्ड ने लिखित में मान लिया है कि वह नाडा की डोपिंग रोधी पॉलिसी का पालन करने को तैयार हैं। अब नाडा सभी क्रिकेटरों का डोप टेस्ट ले सकती है। हालांकि बीसीसीआइ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति (सीओए) का इस समझौते पत्र पर अभी हस्ताक्षर करना बाकी है। वहीं बीसीसीआइ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह सीओए के निर्देश में काम कर रहे दो अधिकारियों ने किया है। वे दोनों नीतिगत फैसला नही कर सकते हैं।

हमने बोर्ड को संतुष्ट किया : जुलानिया ने कहा, बीसीसीआइ ने हमारे सामने तीन मुद्दे डोप टेस्टिंग किट, पैथोलोजिस्ट की क्षमता और सैंपल संग्रह उठाए। हमने उन्हें संतुष्ट किया कि जो भी सुविधाएं वह चाहते हैं, हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त भुगतान करना होगा क्योंकि सभी सुविधाएं हर एनएसएफ के लिए एक समान होगी। बीसीसीआइ दूसरों से अलग नहीं है। जौहरी ने कहा कि बीसीसीआइ कानून का पालन करने के लिए तैयार है।

क्रिकेटर चिंतित : बीसीसीआइ पहले नाडा के अंतर्गत आने से बच रहा था। वह खुद को एक स्वतंत्र संस्था मानता था। अभी तक बोर्ड और खिलाड़ियों की चिंता 'व्हेयर एबॉउट' धारा रही है जिसके तहत खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में नहीं खेलने के बावजूद यह बताना होता है कि उस दौरान वह कहां रहेंगे जिससे डोपिंग रोधक एजेंसी उनका टेस्ट ले सके। सभी भारतीय क्रिकेटर मानते हैं कि इससे उनकी निजता में खलल पड़ता है। वेस्टइंडीज में मौजूद भारतीय क्रिकेटर नए घटनाक्रम से चिंतित हैं।

अभी तक ये होता था : अभी तक स्वीडन की अंतरराष्ट्रीय डोप टेस्टिंग मैनेजमेंट संस्था (आइडीटीएम) भारतीय क्रिकेटरों का नमूना इकट्ठा करके राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग प्रयोगशाला में जमा करती थी लेकिन अब यह काम नाडा करेगी। (पेज-12 भी देखें)

सुधरते हालात

निषेधाज्ञा के बावजूद कई जगहों पर खुले बाजार, शांतिपूर्वक संपन्न हुई नमाज-ए-जुमा, सोपोर में छिटपुट हिंसा को छोड़ कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं, कश्मीरी जनता कर रही ईद की तैयारी

ये है नए हिंदुस्तान का नया कश्मीर... न पथराव-न हिंसा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

न पथराव-न हिंसा। न आतंकी संगठनों के झंडे और न ही पाकिस्तान और आजादी समर्थकों की नारेबाजी। विभिन्न जगहों पर खुली दुकानें और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की ओर बढ़ते कदम। शरारती तत्वों और अलगाववादी समर्थकों का तो मानो नामोनिशान ही नहीं। ये है नए हिंदुस्तान का नया कश्मीर। घाटी में शुक्रवार को नमाज-ए-जुमा का दिन अमूमन हिंसक प्रदर्शनों की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन सोपोर समेत कुछ जगहों पर हुई छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो कश्मीर में माहौल पूरी तरह शांत रहा। कश्मीरी अवाम सोमवार को ईद मनाने को लेकर पूरी तरह तैयार दिखी।

शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन भी जवाहर सुरंग से लेकर उत्तरी कश्मीर के टंगडार तक प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए निषेधाज्ञा को जारी रखा था। स्कूल कॉलेज, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं भी बंद थी। हर चौक और बाजार में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ दिनभर तैनात रहे, लेकिन वह सड़क पर निकल रहे लोगों, ठेला लेकर निकल रहे फेरी वालों, दुकानदारों या वाहनों को नहीं रोक रहे थे। ऐसे में डल झील के पास ही नहीं राजबाग, जवाहर नगर, इंदिरानगर में कुछ-कुछ दुकानें खुली। डाउन-टाउन में नौहट्टा, राजौरीकदल और नक्शबंद साहब के इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य हिस्सों में भीतरी गलियों में भी कुछ दुकानें खुली हुई थी। सोमवार को ईद के दिन कुर्बानी के लिए जानवरों के खरीदार भी घरों से बाहर निकले और विभिन्न बाजारों और मंडियों में पहुंचे।

जम्मू में धारा 144 हटने के बाद खुले बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। बाजार में पहुंचे लोगों ने जमकर खरीदारी की। उन्हें अब ईद का इंतजार है। जागरण

डाउन-टाउन की गलियों में घूमते नजर आए डोभाल : दो दिन पहले ही दिल्ली लौटे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शुक्रवार सुबह फिर श्रीनगर पहुंचे। पत्थरबाजों और अलगाववादियों का गढ़ कहलाने वाले श्रीनगर के डाउन-टाउन के भीतरी इलाकों में डोभाल घूमते और स्थानीय लोगों के साथ विशेषकर नौजवानों से बात करते नजर आए। इरशाद अहमद नामक एक युवक ने कहा कि मैंने आज डोभाल साहब को पहली बार देखा है। मैंने उन्हें कहा कि यह बंद और निषेधाज्ञा 70 साल से चली आ रही खानदानी सियासत की गुलामी से बेहतर है।

चिंतित सभी थे पर हालात रहे सामान्य : कश्मीर में बीती रात हालात को लेकर सुरक्षा संबंधी मामलों की बैठक में सभी शुक्रवार के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि नमाज-ए-जुमा का दिन सामान्य दिनों से बहुत संवेदनशील माना जाता रहा है। अधिकतर देश विरोधी प्रदर्शन इसी दिन होते हैं, लेकिन हैरान करने वाले डाउन-टाउन के हालात थे, जहां जामिया मस्जिद और उसके साथ सटे इलाकों में एक भी नारा नहीं गूंजा। टीआरसी मैदान के बाहर फुटपाथ पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान सजाकर बैठे मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि यहां सुरक्षा भी है और पाबंदी भी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं रोका। यूसुफ साफ तौर पर कहते हैं, अब छोड़ो 370 की बातें, सोमवार को ईद होगी और हम सभी ईद मनाना चाहते हैं।

विदेश जाने से रोके गए एनडीटीवी के प्रणय राय और उनकी पत्नी

- भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ द्वारा जारी एलओसी पर की गई कार्रवाई
- मुंबई एयरपोर्ट का मामला, कंपनी बोली कार्रवाई मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन

मुंबई, प्रेट्र : कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जांच का सामना कर रहे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को विदेश जाने से शुक्रवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। सीबीआइ द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उधर, मीडिया कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि भ्रष्टाचार के एक फर्जी और निराधार मामले में दोनों को विदेश जाने से रोका गया। इस मामले की जांच दो साल पहले सीबीआइ ने शुरू की थी।

नई दिल्ली स्थित सीबीआइ अधिकारियों ने कहा कि आइसीआइसीआइ बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में जून में दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इसी के आधार पर ही दोनों को देश छोड़ने से रोका गया है। अधिकारियों ने बताया कि लुकआउट सर्कुलर का उद्देश्य किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकना होता है, उसे हिरासत में लेना नहीं। कंपनी ने बयान में यह तो नहीं बताया कि दोनों कहां जा रहे थे, लेकिन यह जरूर कहा कि दोनों के पास 16 अगस्त को भारत वापस लौटने का भी टिकट था।

कंपनी ने कहा कि आज की कार्रवाई और मीडिया मालिकों पर छापे मारने की कार्रवाई इस ओर इशारा करती है कि या तो आप मेरे सामने दंडवत हो जाएं अन्यथा कार्रवाई झेलने को तैयार रहें। कंपनी ने कहा कि यह पूरी तरह मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। दोनों संस्थापकों को पत्रकार बताते हुए कंपनी ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने की किसी कोशिश के आगे नहीं झुकेगी। बता दें कि दिवालिया विमानन कंपनी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने से रोकने के बाद किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को विदेश जाने से रोकने का यह दूसरा मामला है।

13 अगस्त को दिल्ली परिवहन निगम ने बसों के रूट बदले हैं फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते। बस सेवा की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-23317600 व 011-41400400 और टोल फ्री नंबर 1800118181 पर संपर्क किया जा सकता है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 10 अगस्त 2019

दिल्ली जल संरक्षण मॉडल बनेगा मिसाल

शुभारंभ ▶ यमुना के तराई क्षेत्र में जलाशय बनाने की योजना का शिलान्यास

बाढ़ के पानी का संग्रह करने के लिए 25 से 30 एकड़ में जलाशय निर्माण का काम शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अलीपुर इलाके के सुंगरपुर में यमुना के तराई क्षेत्र में जलाशय बनाने की योजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास के साथ ही यमुना के तराई क्षेत्र में बाढ़ के पानी का संग्रह करने के लिए 25 से 30 एकड़ में जलाशय निर्माण का काम शुरू हो गया। सुंगरपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना शुरू की गई है। अगले साल योजना को व्यापक रूप से लागू किया जाएगा।

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह एक अभिनव प्रयोग है और वह चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यह दुनिया भर में दिल्ली मॉडल के रूप में अपनाया जाए।

उन्होंने कहा कि विश्व में उपलब्ध पानी के सामने हर छठा आदमी भारतीय है, जबकि उपलब्ध जल स्रोतों से मिलने वाले पानी का महज चार फीसद हिस्सा ही भारत को मिलता है। उन्होंने जल संरक्षण की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि जल संसाधन के लिहाज से भारत आज दुनिया में अस्वच्छ जल वाले देश के रूप में उभरा है। प्राकृतिक स्रोतों से उपलब्ध पानी के महज आठ फीसद हिस्से को ही हम रोक पाते हैं। ऐसे में हमें जमीन के अंदर जाने वाले बारिश के पानी की मात्रा को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन यह तभी संभव है जब जल संरक्षण जन आंदोलन बने। इसके लिए किसानों व उद्योग को आपस में जुड़ना होगा।

उन्होंने यमुना के तराई क्षेत्र में बाढ़ के पानी को संग्रह करने की यह योजना शुरू कराने को लेकर दिल्ली सरकार को बधाई दी और कहा कि इससे जल संकट से उबरने में मदद मिलेगी।

समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसी योजना सरकार के स्तर पर देश में पहली बार शुरू की गई है। भूजल स्तर लगातार घट रहा है। ऐसे में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह देश-दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जलाशय जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे बनाए जा रहे हैं, जहां पानी संग्रह किया जाएगा। जलाशय बनाने के लिए एक से डेढ़ मीटर गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि यमुना का बहता हुआ पानी चार से पांच घंटे के लिए रुक सके और जमीन के अंदर जा सके। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम संग्रहित जल के जमीन के अंदर जाने की गति को मापेंगे।

उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे व्यापक रूप देते हुए जन आंदोलन बनाया जाएगा। इससे दिल्ली ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने योजना को शुरू करने में केंद्र सरकार के योगदान के लिए आभार जताया जिसके चलते महज दो माह के अंदर ही इसे धरातल पर उतार दिया गया।

सुंगरपुर में यमुना नदी के बाढ़ के पानी के संग्रह के लिए जलाशय के विकास कार्य का शिलान्यास करने के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शेखावत ने इस अभियान को एक अभिनव प्रयोग बताया। जागरण

विस अध्यक्ष के फैसले पर दो सप्ताह में जवाब दें मिश्रा : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को दो सप्ताह के अंदर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के निष्कर्ष पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। विधानसभा सदस्यता रद करने के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कपिल मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने अगली सुनवाई चार सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान कपिल मिश्रा के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता पर लगे आरोपों व निष्कर्ष पर विवाद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ही छोड़ दी है। कपिल मिश्रा ने याचिका में विधानसभा स्पीकर के फैसले को अवैध, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण बताया है। याचिका के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर दलबदल कानून के तहत कपिल मिश्रा को 31 जुलाई को अयोग्य ठहरा दिया था। स्पीकर ने अपने फैसले में कहा था कि मिश्रा ने लोकसभा चुनाव में भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया था। मिश्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया।

मोदी के तीन मंत्री दिल्ली में खत्म करेंगे सत्ता का वनवास

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

विजय रथ पर सवार भाजपा अब दिल्ली फतह पर निकल पड़ी है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीन मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन नियुक्तियों में अनुभव व चुनावी समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही प्रदेश संगठन के कार्यकर्ताओं में फरवरी के बजाय हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड के साथ ही यहां भी अक्टूबर या नवंबर में चुनाव कराए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं।

प्रकाश जावड़ेकर के पास लंबा संगठनात्मक अनुभव है। वह राजस्थान में विधानसभा व लोकसभा चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं। इससे पहले वह कर्नाटक के प्रभारी थे। दिल्ली की सियासत में उन्हें पहली बार कोई जिम्मेदारी मिली है। भाजपा नेता व कार्यकर्ता इसे संगठन के लिए फायदेमंद मानते हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली की सियासत में सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होने की वजह से वह पार्टी में गुटबाजी को रोकने में सफल रहेंगे।

वहीं, हरदीप सिंह पुरी को सह प्रभारी बनाकर पार्टी ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्य सरकार की चुनावी राह मुश्किल करने की कोशिश की है। वह सीलिंग, अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने व मेट्रो जैसे दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों से सीधे जुड़े रहने के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मुखर रहे हैं। पुरी ने समय-समय पर न सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के आरोपों का जोरदार ढंग से जवाब दिया है, बल्कि दिल्ली सरकार को कई मौकों पर असहज करने से पीछे नहीं रहे हैं।

शहरी विकास मंत्री होने के नाते वह सीलिंग से परेशान दिल्लीवासियों को राहत देने के साथ ही इस समस्या के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार भी ठहराते रहे हैं। दिल्ली में विशेष कानून के तहत दिसंबर, 2020 तक हुए निर्माण को तोड़फोड़ से बचाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को भी इन्होंने आगे बढ़ाया है। इसी तरह से मेट्रो किराया में बढ़ोतरी के लिए जब केजरीवाल सरकार व आप के नेता केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रहे थे, तो पुरी ने जोरदार पलटवार किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार की किराया बढ़ाने में भूमिका रही है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए अब वह इसका विरोध कर रही है। इसी तरह से नित्यानंद राय के संगठनात्मक अनुभव का लाभ मिलने के साथ ही पूर्वांचल के मतदाताओं को जोड़ने में आसानी होगी। मनोज तिवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूर्वांचल के लोगों का रुझान बढ़ा है। अब राय की उपस्थिति से बिहार के लोगों के बीच भाजपा का जनाधार बढ़ेगा। मंत्री बनने से पहले वह बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे।

प्रकाश जावड़ेकर। फाइल

हरदीप सिंह पुरी। फाइल

नित्यानंद राय। फाइल

पार्टी अध्यक्ष से मिलकर बनाएंगे विस्तृत रणनीति : जावड़ेकर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के चुनाव प्रभारी बनने से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी को गति मिलेगी। जल्द ही वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व सह प्रभारियों के साथ चुनाव प्रचार की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 'मैं पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है, हम सभी उसे निभाते हैं। हमारे पास पहले कर्नाटक की जिम्मेदारी थी। उसके बाद राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी रही। अब दिल्ली का दायित्व मिला है। जल्द ही पार्टी के अध्यक्ष व अन्य संबंधित लोगों के साथ मिलकर विस्तृत रूप रेखा तैयार की जाएगी।' उन्होंने बताया कि इस समय वह दिल्ली से बाहर हैं। वहीं, हरदीप पुरी का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया जाना गर्व की बात है। उन्होंने ट्वीट किया कि 'प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में नित्यानंद राय के साथ दिल्ली विस चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाए जाने पर मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभारी हूं।' भाजपा नेताओं ने भी पार्टी नेतृत्व के इस फैसले का स्वागत किया है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि इससे दिल्ली में आप की सरकार को हटाने में मदद मिलेगी।

न्यूज गैलरी

आइपीएस व दानिप्स अफसरों को मिली नई तैनाती

नई दिल्ली : आइपीएस सहित 10 दानिप्स अधिकारियों की तैनाती दिल्ली पुलिस के अलग-अलग विभागों में की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुक्रवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, अंडमान-निकोबार से ट्रांसफर होकर आईं 1996 बैच की सीनियर आइपीएस अधिकारी शालिनी सिंह को वेस्टर्न रेंज का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया है। वहीं, अंडमान से ही आए विमल आनंद को हेडक्वॉर्टर में, चंडीगढ़ से आए ओम प्रकाश मिश्रा को आर्थिक अपराध शाखा में, जबकि मिजोरम से लौटे एमएन तिवारी को ऑपरेशंस ब्रांच में एडिशनल सीपी के पद पर तैनात किया गया है। इनके साथ ही डेप्युटेशन से लौटे पुष्पेंद्र कुमार और अरुणाचल प्रदेश से आए रोहित मीणा को डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर, रीक्रूटमेंट सेल में तैनात डीसीपी विक्रम पोरवाल को मेट्रो पुलिस का डीसीपी बनाया गया है। नई दिल्ली जिले के एडिशनल डीसीपी-1 रहे डॉ. ईश सिंघल अब इसी जिले के डीसीपी होंगे। वहीं अंडमान से आए दीपक यादव को नई दिल्ली जिले में और अरुणाचल प्रदेश से आए जितेंद्र कुमार रोहिणी जिले में एडिशनल डीसीपी-1 का कामकाज देखेंगे। (जासं)

बस बहुत हुआ, पुलिस कुछ नहीं कर रही : हाई कोर्ट

नई दिल्ली : अमन विहार इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। यही नहीं बच्चों की सुरक्षा के प्रति इस लापरवाही पर सख्त लहजे में कहा कि बहुत हुआ, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अब छह माह के भीतर अमन विहार ही नहीं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पश्चिम दिल्ली के अमन विहार इलाके में बच्चों व लोगों के गायब होने के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाने की की दिशा में काम नहीं किया है। (जासं)

नकली वेबसाइट के जरिये ठगने वाले तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली : पश्चिमी जिला पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो नकली वेबसाइट बनाकर ठगी करता था। गिरोह ने एक कॉल सेंटर खोल रखा था। पुलिस ने गिरोह के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, पांच मोबाइल व बैंक खाते से जुड़ी जानकारियां बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने भारत सरकार की आनलाइन ई वीजा के लिए बनी वेबसाइट से मिलती-जुलती वेबसाइट तैयार कर ली थी। (जासं)

शाहबेरी में सील होंगी खाली पड़ीं इमारतें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ मंत्री समिति ने शाहबेरी के फ्लैट खरीदारों के साथ की वार्ता

▶ रविवार को बाइक रैली निकालेंगे फ्लैट खरीदार

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शाहबेरी के फ्लैट खरीदारों की समस्या हल करने के लिए शुक्रवार को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना व आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ग्रेटर नोएडा पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने फ्लैट खरीदारों और अधिकारियों के बीच अहम बैठक कर सीधे संवाद कायम किया। दो घंटे की जद्दोजहद के बाद भी स्थायी हल नहीं निकल सका। खरीदारों ने बैठक समाप्त होने के बाद असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि उनकी समस्या के समाधान के लिए ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। उनका धरना जारी रहेगा। रविवार को वह शाहबेरी से ग्रेटर नोएडा कार्यालय तक बाइक रैली निकाल कर विरोध जताएंगे। वहीं, प्राधिकरण ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि कुछ बिंदुओं पर अभी सहमति नहीं बनी है। स्थायी समाधान के लिए आगे भी संवाद का रास्ता अपनाते हुए हल तलाशा जाएगा। फिलहाल प्राधिकरण खाली इमारतों को सील करेगा।

प्राधिकरण शाहबेरी की इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराएगा। इस ऑडिट में जो इमारतें सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर मिलेंगी, उनके बारे में आगे रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में दोनों मंत्रियों ने फ्लैट खरीदारों की समस्या को गंभीरता से सुना। औद्योगिक विकास मंत्री ने खरीदारों से कहा कि प्रदेश सरकार के लिए सभी नागरिकों की सुरक्षा अहम है। बैठक में सहमति बनी की क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए पुलिस चौकी की सक्रियता को बढ़ाया जाएगा। बिल्डरों ने जिन लोगों की कमाई को हड़पा है, प्रशासन व प्राधिकरण की टीम संयुक्त सर्वे कर उन्हें चिह्नित करेगी और उनके खिलाफ एफआइआर, गैंगस्टर व एनएसए की कार्रवाई होगी। उनकी संपत्ति चिह्नित कर जब्त की जाएगी। बिल्डर से रकम की रिकवरी के लिए प्राधिकरण ने उन्हें कानूनी मदद का आश्वासन दिया। प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी संपत्ति लेने से पहले उसकी जांच कर लें। बिना नक्शा पास कराए निर्माण अवैध है। सूचना देने के लिए प्राधिकरण ने सेंटर स्थापित किया है। बैठक में खरीदारों ने कहा कि सुरक्षा ऑडिट में जो इमारतें मजबूत पाई जाएं, उन्हें नियमित किया जाए। कमजोर इमारतों में रहने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था या उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। खरीदारों ने दावा किया कि मंत्री समिति की ओर से उनकी मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। समिति ने कहा कि बिल्डर से रकम वापस लेने के लिए वह कोर्ट में जाएं। प्राधिकरण उन्हें कानूनी सहायता देने को तैयार हैं।

ग्रेनो प्राधिकरण में बैठक करते (बाएं से) उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, सांसद डॉ. महेश शर्मा और अन्य। फोटो : सौजन्य प्राधिकरण

जनप्रतिनिधियों ने खरीदारों के पक्ष में उठाई बात : बैठक में सांसद महेश शर्मा ने खरीदारों का समर्थन करते हुए कहा कि शाहबेरी में अवैध इमारतों के निर्माण के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार है। इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीकरा उन लोगों पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए, जिन्होंने जीवन भर की कमाई को घर खरीदने में लगा दिया। उन्होंने शाहबेरी की इमारतों को नियमित करने का आग्रह किया। दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह व भाजपा के वरिष्ठ नेता तेजा गुर्जर ने भी पुरजोर तरीके से फ्लैट खरीदारों की बात मंत्रियों और अधिकारियों के सामने उठाई।

शाहबेरी में भी गोपनीय तरीके से गए मंत्री : औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना व आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह अधिकारियों के साथ गोपनीय तरीके से शाहबेरी गए। उन्होंने अवैध इमारतों का नजदीकी से जायजा लिया। हालांकि इस बात की भनक लोगों को नहीं लग सकी।

आला अफसर भी रहे बैठक में मौजूद : बैठक में दोनों मंत्रियों के अलावा सासंद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आरके सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह, एसीईओ केके गुप्ता आदि मौजूद रहे।

नीरज बवानिया गिरोह के नौ बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कंझावला थाना पुलिस ने कुख्यात नीरज बवानिया गिरोह के नौ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वे रोहिणी में पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रच रहे थे। उनके पास से पांच पिस्टल, 29 कारतूस, तीन फरसा व तीन महंगी कारें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान नवीन उर्फ विक्की, नीरज, अरविंद, नरेश, करन, सूबेग सिंह, दिनेश सोनी, महेश डागर व अमित के रूप में हुई है। नवीन जेल वैन हत्याकांड सहित 11 संगीन मामलों में आरोपित है। वह मंगोलपुरी में वर्ष 2015 में जेल वैन हत्याकांड में जमानत पर बाहर आने के बाद से फरार चल रहा था। अरविंद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बीएससी है। उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है

रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त एसडी मिश्रा ने बताया कि सात अगस्त की शाम कंझावला थाने के सिपाही हवा सिंह जौंती गांव में गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि दो कारों में सवार कुछ लोग वर्षों से खाली पड़े विवादित मकान के परिसर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों पर शक हुआ तो उन्होंने तुरंत मामले की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना के आधार पर बेगमपुर के एसीपी रमेश कुमार की देखरेख में कंझावला थाने के पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। टीम ने वहां छापेमारी की तो तीन कारों में नौ लोग मिले। उनके पास से पिस्टल, कारतूस फरसे मिले। पूछताछ में पता चला कि सभी नीरज बवानिया गिरोह के बदमाश हैं। बदमाशों के खिलाफ कंझावला थाने में आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया।

गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि उन्हें जेल में बंद उनका सरगना नीरज बवानिया वारदात करने के लिए दिशा-निर्देश देता है। उनकी साजिश रोहिणी इलाके में पेट्रोल पंप लूटने की थी। लूटपाट के मकसद से वे एकत्रित हुए थे। पुलिस के अनुसार नवीन को नीरज जेल से निर्देश देता था।

एप के जरिये मांगते थे रंगदारी : पुलिस को इन बदमाशों के पास से मोबाइल फोन तो मिले, लेकिन उनमें सिम कार्ड नहीं थे। लोकेशन व कॉल डिटेल को छिपाने के लिए कारोबारियों, उद्यमियों, प्रॉपर्टी डीलर से एप के जरिये कॉल कर रंगदारी मांगते थे। आपस में बातचीत भी एप के जरिये ही करते थे।

विमान में बम धमाके की कॉल से आइजीआइ पर अफरातफरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई अलर्ट के बीच एक शख्स की ओर से किए फोन से गुरुवार को आइजीआइ एयरपोर्ट पर अफरातफरी मच गई। डायल के कॉल सेंटर पर आए फोन में बताया गया था कि एक महिला दुबई या सऊदी अरब जा रहे विमान में बम धमाका करने वाली है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दुबई और रियाद जाने वाले विमानों की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई बम नहीं मिला। सघन जांच के बाद झूठी कॉल साबित होने पर विमानों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। फोन पर झूठी सूचना देने वाले शख्स की तलाश की जा रही है।

आइजीआइ एयरपोर्ट के अधिकारी के मुताबिक गुरुवार रात करीब पौने नौ बजे नसरुद्दीन ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के गुरुग्राम स्थित कंट्रोल रूम में फोन किया था। उसने बताया था कि वह चेन्नई से बोल रहा है। हरे रंग के वस्त्र पहने एक महिला चेन्नई से साढ़े चार बजे दिल्ली पहुंची है। उसका नाम रफिना या जबिना है। उसने दुबई या सऊदी अरब जाने वाले विमान में बम लगाया है। बम आधे घंटे के अंदर फट जाएगा। इसकी सूचना तुरंत कॉल सेंटर के कर्मचारियों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति और स्वतंत्रता दिवस को लेकर एयरपोर्ट पर पहले से ही हाई अलर्ट है।

गाड़ी हटाने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बवाना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात दबंगों ने गाड़ी हटाने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अनिल (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, मारपीट, बंधक बनाने, धमकी देने आदि धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

जानकारी के अनुसार, अनिल अपने परिवार के साथ बवाना के पूठखुर्द गांव में रहते थे। उनके पिता महेंद्र सिंह के पास ईको वैन है। अनिल सुबह अखबार बांटने का काम करते थे और दिन में भाड़े पर वैन चलाते थे। परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात करीब सवा 12 बजे गांव के ही दो युवक स्कॉर्पियो से उनके घर के आगे पहुंचे और कार रोक दी। इसके बाद काफी देर तक कार की हॉर्न बजाते रहे। हॉर्न की आवाज सुनकर अनिल व उनके पिता घर से बाहर आए तो दोनों युवक उन्हें ईको वैन हटाने को कहते हुए गालियां देने लगे।

परिजनों के अनुसार, वैन से रास्ता बाधित नहीं था। ऐसे में दोनों पिता-पुत्र ने उन युवकों का विरोध किया तो उन्होंने अपने दो अन्य दोस्तों को बुला लिया। चारों ने अनिल को पकड़ लिया और लात-घूसों से उनको पीटने लगे। आरोपित अनिल को तब तक पीटते रहे, जब तक वह बेहोश नहीं हो गए। इसके बाद चारों युवक धमकी देते हुए वहां से चले गए।

तीन अस्पतालों का लगाया चक्कर : हमले में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में मामले की सूचना पुलिस को देकर परिजन उन्हें लेकर सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए आंबेडकर अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन जब उन्हें वहां लेकर गए तो डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उन्हें सरोज अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। वहां रात करीब सवा दो बजे इलाज के दौरान अनिल की मौत हो गई।

परिजनों ने किया प्रदर्शन : घटना के विरोध में शुक्रवार को परिजनों ने गांव के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपित दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने में टालमटोल कर रही है। उनके मुताबिक घटना के समय आरोपित सरेआम पिस्टल लहरा रहे थे। लेकिन पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में संबंधित धाराएं नहीं लगाई हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के उचित कार्रवाई के भरोसे के बाद जाम हटाया गया।

शराब की बोतल पर बने बारकोड से पकड़ा गया हत्यारोपित

जासं, नई दिल्ली : वसंत कुंज साउथ थानाक्षेत्र में आइएलबीएस अस्पताल के पीछे खाली प्लाट में नेपाली युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए डीसीपी साउथ-वेस्ट देवेंद्र आर्या ने बताया कि गिरफ्तार हत्यारोपित हरबीर सिंह पाल किशनगढ़ में किराये पर रहता है और गैस एजेंसी में सिलेंडर सप्लाई करता था। जांच टीम ने मौके से मिली शराब की खाली बोतल पर लिखे बारकोड को आसपास के शराब के ठेकों पर चेक कराया तो एक ठेके की सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि किशन कार्की व हरबीर साथ में शराब व बीयर लेने ठेके पर आए थे। भुगतान हरबीर ने किया। सादे कपड़ों में शराब के ठेकों के पास पुलिस टीम लगा दी गई। गुरुवार को हरबीर वसंत कुंज साउथ स्थित एक ठेके पर शराब लेने पहुंचा तो उसे दबोच लिया। हरबीर ने पुलिस को बताया कि किशन ने उससे शराब पिलाने की गुजारिश की। उसने एक बीयर व शराब खरीदी ली। फिर दोनों ने बाइक पर आइएलबीएस के पीछे खाली पड़े प्लॉट में जाकर शराब पी। इस दौरान हरबीर ने किशन को बताया कि उसके पास सिलेंडर सप्लाई से मिले करीब 1.70 लाख रुपये हैं। इस पर किशन को लालच आ गया और वह हरवीर को जाने नहीं दे रहा था। जिद करते हुए किशन ने हरबीर को थप्पड़ मार दिया। इस पर नशे में धुत हरबीर ने पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर किशन के सिर पर दे मारा। इससे किशन की मौके पर ही मौत हो गई।

योजना

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने फेज चार की परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू करने के लिए जारी किया दूसरा टेंडर

मजलिस पार्क-मौजपुर मेट्रो ट्रैक पर बनेगा डबल डेकर कॉरिडोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच फेज चार की मेट्रो परियोजनाओं के बजट को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने फेज चार की परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू करने के लिए शुक्रवार को दूसरा टेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत एक हजार 30 करोड़ रुपये की लागत से मजलिस पाक-मौजपुर मेट्रो लाइन के एलिवेटेड कॉरिडोर और उसके आठ स्टेशनों का निर्माण होगा।

खास बात यह कि इस मेट्रो लाइन पर दिल्ली का पहला डबल डेकर कॉरिडोर बनेगा। जिसके ऊपर के कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन रफ्तार भरेगी और उसके नीचे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का फ्लाईओवर होगा, जिस पर वाहन दौड़ेंगे। टेंडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ढाई से तीन साल में यह कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर की कुल लंबाई 12.54 किलोमीटर होगी। डीएमआरसी का कहना है कि इस कॉरिडोर पर भजनपुरा से यमुना विहार के बीच डबल डेकर कॉरिडोर बनेगा। इस डबल डेकर कॉरिडोर की लंबाई 1.40 किलोमीटर होगी। ऊपर का कॉरिडोर 18.5 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा, जिस पर मेट्रो चलेगी। इसके नीचे 9.5 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाईओवर होगा, जिस पर वाहन चलेंगे। इसके अलावा फेज चार के तुगलकाबाद-एयरोसिटी मेट्रो लाइन पर अंबेडकर नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच 2.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर कॉरिडोर बनेगा। मौजूदा समय में दिल्ली में इस तरह का डबल डेकर कॉरिडोर नहीं है।

यमुना पर बनेगा मेट्रो का पांचवां पुल : मौजूदा समय में यमुना पर मेट्रो के चार पुल हैं। पांचवां पुल मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडार पर सूरघाट से सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन के बीच बनेगा। इस पुल के बनने से सोनिया विहार के इलाके में मेट्रो से आवागमन की सुविधा होगी। कॉरिडोर पर आठ स्टेशन होंगे। इनमें यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, सोनिया विहार, सूरघाट, जगतपुर गांव, झडोदा माजारा और बुराड़ी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि फेज चार में छह नए कॉरिडोर का निर्माण होना है। इनकी कुल लंबाई 103.94 किलोमीटर होगी। डीएमआरसी ने पिछले माह पहला टेंडर जारी किया था। इसके तहत जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर के 12.3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होना है।

एलिवेटेड कॉरिडोर पर एक हजार 30 करोड़ रुपये की लागत आएगी। (फाइल फोटो)

दिल्ली में बनेगा मेट्रो का रिंग नेटवर्क

मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर पिंक लाइन की विस्तार परियोजना है। वर्तमान समय में पिंक लाइन पर मजिलस पार्क से मयूर विहार पॉकेट एक मेट्रो स्टेशन व त्रिलोकपुरी-मौजपुर-शिव विहार के बीच मेट्रो का परिचालन हो रहा है। मयूर विहार से त्रिलोकपुरी के बीच का हिस्सा अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। तब मजिलस पार्क से शिव विहार के बीच सीधे आवागमन की सुविधा हो जाएगी। फेज चार में मजलिस पार्क से मौजपुरी के बीच नए कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली में मेट्रो का रिंग नेटवर्क तैयार हो जाएगा।

मरीज के शरीर में प्रदूषण के दुष्प्रभाव की जांच करेगा एम्स

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कैंसर, अस्थमा व कई तरह की जन्मजात बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि एक कारण वायु प्रदूषण व दूषित जल का इस्तेमाल बताया जाता रहा है। इसके मद्देनजर एम्स ने देश में पहली बार क्लीनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब शुरू की है। पांच अगस्त से इस लैब में मरीजों की जांच शुरू हो चुकी है। संस्थान का दावा है कि इस तरह की सुविधा अब तक देश के किसी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। संस्थान के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की देखरेख में यह लैब शुरू की गई है। अब तक 40 से ज्यादा मरीजों की जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। संस्थान के डॉक्टर कहते हैं कि पानी में कई तरह की भारी धातु मौजूद रहती हैं। ऐसे में यदि मरीज के शरीर में किसी भारी धातु की मौजूदगी पाई गई तो मरीज और उनके तीमारदारों को ऐसे पानी का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया जाएगा।

एनाटोमी विभाग के प्रोफेसर डॉ. ए शरीफ ने कहा कि पानी में भारी धातु व विभिन्न रसायनों की मौजूदगी से लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आर्सेनिक, कैडमियम, फ्लोराइड, शीशा, मर्करी, यूरेनियम इत्यादि के कण शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लीनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब में यूरिन, ब्लड या शरीर के किसी भी हिस्से से टिश्यू लेकर उसमें हानिकारक कणों की पहचान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण दुनिया भर में करीब 90 लाख लोगों मौत होती है। इनमें से 92 फीसद लोगों की मौतें विकासशील देशों में होती हैं, जिनमें भारत में भी शामिल है।

भारत में प्रदूषण बड़ी समस्या है। कैंसर, बच्चों में हृदय की जन्मजात बीमारियां सहित कई तरह के ऐसे रोग बढ़ रहे हैं, जिनका अब तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। ऐसे में नई तकनीक का इस्तेमाल जांच के अलावा शोध में भी किया जाएगा।

एक करोड़ किसान पाएंगे पेंशन योजना का लाभ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्र सरकार की योजना में पंजीकरण कराने का काम शुरू
- रजिस्ट्रेशन शुल्क 30 रुपये का भुगतान सरकार करेगी

किसानों की सामाजिक सुरक्षा के तहत घोषित प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में शुक्रवार से पंजीकरण चालू कर दिया गया। इसकी शुरुआत करते हुए केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चालू वर्ष में कुल एक करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 18 साल से 40 साल के किसानों की कुल संख्या लगभग साढ़े पांच करोड़ है। तोमर यहां योजना की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

किसानों की पेंशन योजना में प्रीमियर की दर का 50 फीसद सरकार देगी। किसान के 60 साल होने पर उसे 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका 50 फीसद यानी डेढ़ हजार रुपये की पेंशन उसकी पत्नी को दी जाएगी। किसानों को इस बात का पूरा हक होगा कि वे जब चाहें इसे बीच में ही छोड़कर अपना पूरा पैसा मय ब्याज के प्राप्त कर सकते हैं। योजना का पूरा संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम करेगा।

नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना पर प्रेसवार्ता करते केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (बाएं)। प्रेट्र

केंद्रीय आम बजट में किसानों के लिए पेंशन योजना चालू करने की घोषणा की थी। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि नई सरकार के एक सौ दिनों के एजेंडा में इसे शामिल किया गया है, जिसे पूरा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि इसकी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पंजीकरण की शुरुआत के साथ ही देशभर से किसानों के रजिस्ट्रेशन कराने की खबरें मिलने लगीं।

केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने देश के सभी राज्यों के कृषि सचिवों से शाम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विचार-विमर्श करने के साथ योजना को रफ्तार देने का अनुरोध किया। राज्यों से कहा गया कि किसानों की सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तोमर ने कहा कि किसानों के हित वाली यह योजना जम्मू-कश्मीर समेत देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगी। उन्होंने माना कि कठोर परिश्रम के बावजूद किसानों को बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनजर सरकार ने कई अहम कदम उठाये हैं, जिससे उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। इसमें पेंशन योजना भी खास है। इस योजना का लाभ लघु व सीमांत किसानों को मिल सकेगा, जो पूर्णतः स्वैच्छिक है। रजिस्ट्रेशन स्थानीय कामन सर्विस सेंटर पर किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रति किसान 30 रुपये का शुल्क सरकार वहन करेगी। इस शुल्क का भुगतान किसानों को नहीं करना होगा।

देश में कहीं से भी अपने कार्ड से उठा सकेंगे राशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और गुजरात-महाराष्ट्र के बीच शुरू हुई परियोजना
- एक जून 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगी यह योजना
- ज्यादातर सूबों में डिजिटल हो चुके हैं कार्ड, 85.41 फीसद आधार से जुड़ चुके

रामविलास पासवान फाइल फोटो

देश की सार्वजनिक राशन प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी क्रम में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की योजना शुक्रवार को शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा 'वर्ष 2020 के जून तक देश के सभी राज्यों में यह योजना लागू हो जाएगी।' उन्होंने इसके पहले चरण में शुक्रवार को चार राज्यों के दो समूहों में अंतरराज्यीय राशन कार्ड के उपयोग की शुरुआत को हरी झंडी दी। पासवान ने आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और गुजरात-महाराष्ट्र के बीच अंतराज्यीय राशन कार्ड के उपयोग की ऑनलाइन प्रस्तुति देखी। सफलतापूर्वक शुरू हुई प्रणाली को उन्होंने ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। ज्यादातर राज्यों में राशन कार्ड डिजिटल हो चुके हैं। ज्यादातर राज्यों में बायोमीट्रिक प्रणाली मजबूत कर ली गई है। 85.41 फीसद राशन कार्ड आधार नंबर से जोड़ दिए गए हैं। बाकी बचे राज्यों को इसमें तेजी लाने को कहा गया है। देश के सात राज्यों हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा में प्रयोग के तौर पर काम चल रहा है। फिलहाल इन राज्यों में एक जिले से दूसरे जिले के बीच राशन कार्ड पर अनाज वितरण का काम सफलतापूर्वक चल रहा है। पासवान ने कहा कि एक जून 2020 तक वन नेशन, वन राशन कार्ड को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास अनाज भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। उसके गोदामों में कम से कम तीन महीने का राशन हमेशा बना रहता है। उन्होंने बताया कि एफसीआइ के सारे गोदाम ऑनलाइन हो चुके हैं। अनाज की आपूर्ति को हमेशा ट्रैक किया जा सकता है। फिलहाल देश में 81 करोड़ की आबादी को पांच लाख राशन दुकानों से अनाज की आपूर्ति की जाती है। इस पर सालाना कुल 1.4 लाख करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी खर्च होती है। राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को अति रियायती दरों पर गेहूं और चावल के साथ मोटे अनाज का वितरण किया जाता है। यहां दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल और एक रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाता है।

प्रणब मुखर्जी को देश सेवा के लिए 'भारत रत्न' उचित सम्मान : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया 'भारत रत्न' उनकी देश सेवा के लिए उचित सम्मान है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'भारत को और अधिक विकसित बनाने की दिशा में हर संभव कोशिश करने के लिए आपको धन्यवाद... आपको भारत रत्न पाते हुए देखना सम्मान की बात है। यह देशहित में किए गए आपके हर संभव काम का उचित सम्मान है।' ज्ञात हो, मुखर्जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को 'भारत रत्न' प्रदान किया था। यह सम्मान विख्यात असमिया गायक भूपेन हजारिका व आरएसएस नेता नानाजी देशमुख को भी प्रदान किया गया।

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, 'हजारिका सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए सांस्कृति दूत हैं। उनका श्रेष्ठ कार्य लोगों की आत्मा और भावनाओं में समा जाते हैं। भारत रत्न (मरणोपरांत) भारतीय संस्कृति और संगीत में दिए गए उनके योगदान की अभिव्यक्ति है।'

पीएम ने ट्वीट किया, 'भारत महान नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने भारतीय गांव की प्रगति और ग्रामीण आबादी को सशक्त करने के लिए कई कार्य किए। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत रत्न (मरणोपरांत) से नवाजा गया।'

उत्तराधिकारी की खोज ▶ आज होगा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष का फैसला

मुकुल वासनिक का नाम सबसे आगे

मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दलित समुदाय के कई नेता भी दौड़ में शामिल

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी या राहुल गांधी के उत्तराधिकारी की तलाश अभी और लंबी होगी, शनिवार को इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। पिछले ढाई महीने से नए नेतृत्व का चेहरा तय करने पर जारी सियासी चुनौती को अनुच्छेद 370 पर पार्टी में मचे घमासान ने और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के सबसे संकटपूर्ण दौर में फिलहाल गांधी परिवार का नेतृत्व होते हुए भी जब पार्टी नेता खुलेआम पार्टी लाइन से असहमति जता रहे हैं, तब गांधी परिवार से बाहर के नए नेतृत्व के लिए भविष्य की चुनौती कितनी गंभीर होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल, चुनौतियों के इस चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता निकालने की पहली कोशिश में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस कम से कम गांधी परिवार से बाहर का अपना नया अंतरिम अध्यक्ष तो शनिवार को चुन ही लेगी।

पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक अंतरिम अध्यक्ष की रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की पीढ़ी में मल्लिकार्जुन

मुकुल वासनिक फाइल फोटो

खड़गे की दावेदारी भी गंभीर है। वासनिक और पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे खड़गे के अलावा पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के नाम भी संभावितों में हैं। खास बात यह है कि ये सभी नेता दलित समुदाय से हैं। जबकि युवा दावेदारों में राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुच्छेद 370 पर पार्टी लाइन की मुखालफत कर खुद को दौड़ से बाहर कर लिया है।

राहुल गांधी का इस्तीफा होगा मंजूर : कांग्रेस कार्यसमिति की यह बैठक पार्टी के नए अध्यक्ष का फैसला करने के लिए ही विशेष रूप से बुलाई गई है। इसलिए पार्टी संविधान के अनुसार कार्यसमिति सबसे पहले राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार करेगी और इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार, पार्टी में व्यापक अंदरूनी राय यही है कि नए पूर्णकालिक अध्यक्ष पर कोई फैसला नहीं हो पाता है तो कार्यसमिति को अस्थायी या अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद 25 मई को हार की समीक्षा के लिए आयोजित कार्यसमिति की बैठक में ही राहुल ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब इसे नामंजूर कर दिया गया था।

विशेष पैनल गठन का विकल्प : गांधी परिवार से बाहर के चेहरे पर पार्टी नेताओं के बीच सहमति बनाने की चुनौती को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कार्यसमिति फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष का ही चुनाव करेगी। संकेत यह भी हैं कि चार से छह नेताओं का एक विशेष पैनल बनाने का फैसला भी लिया जा सकता है। इस पैनल को पार्टी में चर्चा करके अंतरिम अध्यक्ष के नाम का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नेताओं के बीच घमासान ज्यादा नहीं हुआ और शनिवार को कार्यसमिति में अंतरिम अध्यक्ष का चयन हो जाता है तो पैनल को अगले छह-आठ महीने में संगठन चुनाव कराने की रूपरेखा तय करने का जिम्मा सौंपा जा सकता है। पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन चुनाव के जरिये कराकर गांधी परिवार से बाहर के नेतृत्व की पार्टी में स्वीकारोक्ति मौजूदा हालात में पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद होगी।

दो दशक बाद गैर गांधी के हाथ होगी कांग्रेस की कमान

नई दिल्ली : सीताराम केसरी को हटाए जाने के बाद मार्च 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली थी। दिसंबर 2017 तक करीब 20 वर्षों तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही, जबकि राहुल गांधी का कार्यकाल 20 माह का ही रहा है। अगर गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया तो दो दशक बाद किसी गैर गांधी के हाथ में फिर कांग्रेस की कमान होगी। दरअसल, पार्टी के हाशिए पर चले जाने के बाद भी गांधी परिवार से बाहर के नेतृत्व को कबूल करने को लेकर नेताओं में सहजता नहीं दिख रही। इसीलिए पहले राहुल पर इस्तीफा वापसी का दबाव डाला गया। वह नहीं माने और इस्तीफे की चिट्ठी सार्वजनिक कर दी तो कई नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाने की वकालत शुरू कर दी। हालांकि गांधी परिवार से बाहर के चेहरे को ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने के राहुल के अडिग रुख के मद्देनजर प्रियंका फिलहाल दौड़ में नहीं हैं। ऐसे में तय है कि गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता ही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा।

जावड़ेकर दिल्ली और तोमर हरियाणा के होंगे चुनाव प्रभारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को आकार देना शुरू कर दिया है। इस क्रम में पार्टी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली, नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा, पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र, उपाध्यक्ष ओपी माथुर को झारखंड का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के आखिर में, जबकि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में फिलहाल भाजपा की सरकार है।

पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार, नित्यानंद राय और हरदीप सिंह पुरी दिल्ली में जावड़ेकर की मदद करेंगे। दिल्ली में भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से सिर्फ तीन सीटें जीती थी। अपनी नियुक्ति पर जावड़ेकर ने कहा, वह पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाएंगे। पार्टी अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं से मंत्रणा के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए योजना तैयार करेंगे। जावड़ेकर इससे पूर्व राजस्थान में विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों के प्रभारी थे।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य व कर्नाटक के नेता लक्ष्मण सावदी महाराष्ट्र के सह प्रभारी होंगे। हरियाणा से जाट नेता भूपेंद्र सिंह वहां के प्रभारी तोमर की सहायता करेंगे। झारखंड में माथुर की सहायता के लिए भाजपा नेता एवं बिहार की राजग सरकार में मंत्री नंद किशोर यादव सह प्रभारी बनाए गए हैं।

रास में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे भुबनेश्वर कलिता भाजपा में शामिल

भुबनेश्वर कलिता (बाएं) ने दिल्ली में पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे भुबनेश्वर कलिता शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। जम्मू-कश्मीर संबंधी सरकार के फैसले पर कांग्रेसी रुख के विरोध में उन्होंने इसी हफ्ते राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

भाजपा मुख्यालय में रेल मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में कलिता ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कलिता का इस्तीफा उसी दिन मंजूर कर लिया गया था जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने का संकल्प और जम्मू-कश्मीर को विभाजित करने का बिल पेश किया था। राज्यसभा में कलिता का कार्यकाल नौ अप्रैल, 2020 तक था।

सरकार रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के पक्ष में : राजनाथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, वर्ष 2018-19 में रक्षा उत्पादन ने 80,000 करोड़ रुपये का आंकडा छुआ
- बोले, रक्षा कंपनियों के पास घरेलू और विदेशी बाजार में असीमित अवसर

रक्षा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की इच्छा जताई है। रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ राउंड टेबल बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) एवं आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) को सुदृढ़ करने की इच्छुक है।

रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से 'रक्षा उद्योग में मेक इन इंडिया' थीम पर आयोजित राउंड टेबल वार्ता में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय रक्षा उत्पादन ने वर्ष 2018-19 में 80,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ है, जिसमें 16,000 करोड़ रुपये का योगदान निजी क्षेत्र का है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को प्रबल रूप देने के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल को सरकार ने अपनाया है, जिनके माध्यम से भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए एक साझेदार का चयन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति को उदार बनाया गया है। राजनाथ सिंह ने निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रक्षा कंपनियों के पास निर्यात के अलावा घरेलू बाजार में उल्लेखनीय योगदान करने के भी असीम अवसर मौजूद हैं।

ऑफसेट प्रोसेसिंग का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रालय ने एक संपूर्ण ऑफसेट प्रोसेसिंग पोर्टल की स्थापना की है जिसके जरिए 1.5 अरब डॉलर (10.5 हजार करोड़ रुपये) मूल्य के प्रस्तावों की प्रोसेसिंग

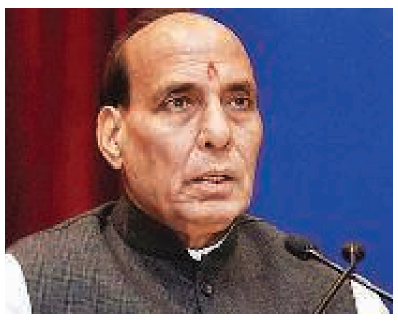

राजनाथ सिंह फाइल फोटो

की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रवेश संबंधी बाधाएं कम कर दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप जारी किए गए रक्षा लाइसेंसों की संख्या वर्ष 2014 के 215 से दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर वर्ष 2019 में 440 हो गई है।

राजनाथ सिंह ने उद्योग जगत से मित्र देशों को निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्यात प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और वर्ष 2016 में रक्षा खरीद प्रक्रिया को संशोधित किया गया, ताकि स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।

मजदूर नहीं रहेंगे मजबूर

मजदूरी संहिता विधेयक 30 जुलाई को लोकसभा से और 2 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया है। इस कानून के तहत पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी के साथ महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही न्यूनतम और समय पर मजदूरी देने को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इस कानून से पचास करोड़ कामगार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। ऐसे कई प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। इस कानून में मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; भुगतान का अधिनियम, 1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976) कानूनों का विलय किया गया है।

दावा करने की समय सीमा भी बढ़ेगी

कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम वेतन का दावा करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। न्यूनतम वेतन, बोनस, समान पारिश्रमिक आदि के लिए दावा पेश करने की प्रक्रिया भी एक समान की गई है। यानी अगर किसी को भी वेतन विसंगति को लेकर शिकायत है तो वह आसानी से दावा कर सकता है।

खत्म हुआ लैंगिक भेदभाव

इस कानून के तहत महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी का प्रावधान कर लैंगिक भेदभाव खत्म किया गया है।

रात में भी काम कर सकेंगी महिला कर्मचारी

इस नये कानून के तहत महिला कर्मचारियों को शाम सात बजे के बाद और सुबह छह बजे से पहले काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन कर्मचारियों की सहमति, सुरक्षा, अवकाश और काम के घंटे की शर्तें यथावत रहेंगी। इसमें फैक्टरी, अनुबंधित श्रमिक, बीड़ी एवं सिगार प्रतिष्ठानों के लिए एक कॉमन लाइसेंस होगा। अनुबंधित श्रमिक रखने के लिए पूरे देश का एक लाइसेंस पांच साल के लिए जारी होगा।

तीन और संहिताओं के आने हैं बिल

सरकार द्वारा 40 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिताओं में बदलने की कड़ी में ये पहली संहिता है, जिसने संसद की सीढ़ी पार कर ली है। अभी तीन संहिताओं के बिल और लाए जाने हैं।

समिति का होगा गठन

न्यूनतम वेतन की आधारभूत दर का निर्धारण ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों वाली त्रिपक्षीय समिति करेगी। जरूरी होने पर समिति को तकनीकी समिति के गठन का भी अधिकार होगा।

एक नई आजादी...

अन्य प्रावधान

- पुराने कानून के तहत 24 हजार रुपये पाने वाले कामगारों की ही जरूरी कटौती और वेतन देने की समय सीमा तय थी। लेकिन नये कानून तहत सभी कामगारों को यह सुविधा मिलेगी।
- गड़बड़ियों को रोकने के लिए इंस्पेक्टर सह अनुदेशक रखे जाएंगे। पहले इस काम को लेबर इंस्पेक्टर देखते थे।
- कानून के मुताबिक, न्यूनतम मजदूरी को केवल कौशल और भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कारकों से जोड़ा जाएगा। बाकी कारकों को हटा दिया गया है। देश भर में वर्तमान में मौजूद 2500 न्यूनतम मजदूरी दरों को घटाकर 300 करने की है।
- हर पांच साल में न्यूनतम वेतन दरों की समीक्षा होगी।

दायरे से बाहर है मनरेगा

यह कानून सरकारी कर्मचारियों और मनरेगा श्रमिकों को छोड़कर संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू होगा।

राष्ट्रपति ने यूएपीए बिल के संशोधनों को मंजूरी दी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 में उन व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के साथ ही उनपर यात्रा प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हैं, जिन्हें आतंकवादी घोषित किया जा चुका हैं।गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने गुरुवार की रात विधेयक को अपनी मंजूरी दी। लोकसभा ने 24 जुलाई को इस संशोधन विधेयक को पारित किया था जबकि राज्यसभा ने दो अगस्त को इसे पारित किया था। अधिकारियों ने बताया कि भारत के सबसे वांछित लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पहले ऐसे दो व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें इस विधेयक के तहत आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इन संशोधनों की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के महानिदेशक को ऐसे आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क करने का अधिकार होगा।

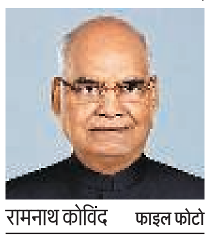

रामनाथ कोविंद फाइल फोटो

बता दें कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल केवल आतंकवाद से निपटने के लिए किया जाएगा। शाह ने कहा था कि आतंकवादी कृत्य संगठनों द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। संगठनों को केवल आंतकी संगठन घोषित करने से आतंकवाद नहीं रुकेगा, क्योंकि संगठन को चलाने वाले आतंकी होते हैं। अगर संगठन पर कार्रवाई की जाती है तो उससे जुड़े व्यक्ति दूसरे नाम से संगठन बनाकर आतंकी गतिविधियां संचालित करने लगते हैं।

रफ्तार बरकरार

राज्यों की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार बरकरार, 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में आंध्र दूसरे व बिहार तीसरे स्थान पर, पंजाब और यूपी निचले पायदान पर

विकास दर में बंगाल अव्वल, गोवा फिसड्डी

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

घरेलू और वैश्विक कारणों के चलते देश की विकास दर भले ही पांच साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई हो लेकिन राज्यों की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार बरकरार है। वित्त वर्ष 2018-19 में चार राज्यों के जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) की सालाना वृद्धि दर दस फीसद से ऊपर रही है। अब तक पिछड़ते रहे बंगाल ने वित्त वर्ष 2018-19 में 12.58 प्रतिशत विकास दर हासिल की है जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है। वहीं गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश विकास दर के मामले में पिछड़ते हुए निचले पायदान पर रहे हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विकास दर के आंकड़े संबंधित प्रदेश सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय से जुटाकर अपनी वेबसाइट पर जारी किये हैं। हालांकि 11 राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा तथा दो केंद्र शासित क्षेत्रों-अंडमान निकोबार व चंडीगढ़ की विकास दर के आंकड़े एक अगस्त 2019 तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जिन प्रदेशों की विकास दर के आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना की विकास दर दस फीसद से अधिक रही है। पश्चिम बंगाल की विकास दर 12.58 प्रतिशत रही है जो सब राज्यों में सर्वाधिक है। हाल के वर्षों में संभवत यह पहला साल है जब बंगाल की विकास दर दहाई के अंक में पहुंची है। वित्त वर्ष 2017-18 में बंगाल की विकास दर 8.88 प्रतिशत थी। बंगाल की विकास दर में उछाल से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत मिलेगी क्योंकि दो साल बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं।

विकास दर के मामले में बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 11.02 प्रतिशत रही है। वित्त वर्ष 2017-18 में भी आंध्र प्रदेश की विकास दर का आंकड़ा लगभग इतना ही था। इसी तरह तीसरे नंबर पर रहे बिहार ने भी 10.53 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। वित्त वर्ष 2017-18 में भी बिहार की विकास दर दहाई के अंक में थी। दूसरी ओर, वित्त वर्ष 2018-19 में सबसे कम विकास दर गोवा (0.47 प्रतिशत), पंजाब (5.91 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (6.08 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (6.46 प्रतिशत) की रही है जो देश की आर्थिक वृद्धि दर से भी कम है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2018-19 में देश की विकास दर 6.8 प्रतिशत रही जो कि बीते पांच साल में न्यूनतम है। चालू वित्त वर्ष में भी इसके 7 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।

राज्य	विकास दर (प्रतिशत में)
पश्चिम बंगाल	12.58
आंध्र प्रदेश	11.02
बिहार	10.53
तेलंगाना	10.50
कर्नाटक	9.53
पुडुचेरी	8.68
दिल्ली	8.61
ओडिशा	8.26
हरियाणा	8.19
तमिलनाडु	8.17
हिमाचल प्रदेश	7.34
राजस्थान	7.33
सिक्किम	7.05
मध्य प्रदेश	7.04
झारखंड	6.99
उत्तराखंड	6.87
उत्तर प्रदेश	6.46
छत्तीसगढ़	6.08
पंजाब	5.91
गोवा	0.47

17-18 अगस्त को भूटान जाएंगे पीएम

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18 अगस्त को भूटान की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वह भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय विकास साझेदारी को मजबूत बनाने और पनबिजली क्षेत्र में सहयोग समेत कई मसलों पर बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री 17 अगस्त को भूटान पहुंचेंगे और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। उसी दिन वह अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस यात्रा की विशेषता मांगदेछू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन होगी। यात्रा के दौरान मोदी भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी को भी संबोधित करेंगे। भूटान नरेश और महारानी प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर के भोज का भी आयोजन करेंगे। मालूम हो कि भारत के साथ विकास साझेदारी भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों का बड़ा पहलू है। भारत ने पिछले साल दिसंबर में भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई थी। इसकी पहली किस्त जारी भी कर दी गई है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

64 शहरों में 5,595 ई बस चलाने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में भारी उद्योग मंत्रालय दिल्ली, राज्यों की राजधानियों और मेट्रो शहरों में ई बसों को पहुंचाने पर काम कर रहा है। इससे साल में 120 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 10 अगस्त 2019

370 पर पार्टी लाइन से अलग चले हुड्डा पिता–पुत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रही कांग्रेस से अलग चलते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी सरकार के फैसले का खुलकर समर्थन किया है। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा दो दिन पहले ही 21वीं सदी में अनुच्छेद 370 का कोई औचित्य नहीं होने की बात कह चुके हैं।

अनुच्छेद 370 पर राहुल गांधी और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद के तीखे विरोध के बीच भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करने वाले प्रस्ताव का हरियाणा विधानसभा में भी खुलकर समर्थन किया था। ऐसे में जहां राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में बवाल मच गया, वहीं प्रदेश में नई राजनीतिक अटकलों ने जन्म ले लिया है। राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हैं। हुड्डा को लगता है कि ऐसे समय में अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध नुकसानदायक साबित हो सकता है। अनुच्छेद 370 पर प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद के विरोध करने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि क्या सही है और क्या गलत है, यह हमें पता है। मैंने अपनी राय से अवगत करा दिया है। गुलाम नबी की राय अलग हो सकती है। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसले स्वागत योग्य है।

तंवर बोले, समय की मांग : जींद के जुलाना में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना समय की मांग है।

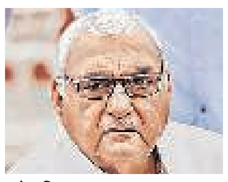
भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल

दीपेंद्र हुड्डा फाइल

21वीं सदी में अनुच्छेद 370 का औचित्य नहीं : दीपेंद्र हुड्डा

पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय रही है कि 21वीं सदी में अनुच्छेद 370 का औचित्य नहीं है और इसको हटना चाहिए। ऐसा सिर्फ देश की अखंडता के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू–कश्मीर के हित में भी है। दीपेंद्र के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि संशोधित नियमों का क्रियान्वयन शांति और विश्वास के माहौल में हो।

पढ़ लें जम्मू–कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास : गुलाम नबी

प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जिन लोगों को जम्मू–कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है, उनसे मुझे कोई लेना–देना नहीं। ऐसे नेता पहले जम्मू–कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें, फिर कांग्रेस में रहें। अनुच्छेद 370 को खत्म किया जाना पूरी तरह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं।

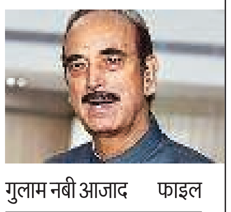
गुलाम नबी आजाद फाइल

मध्य प्रदेश में अनुपयोगी हो चुके 250 से ज्यादा कानून खत्म करने की तैयारी

नईदुनिया, भोपाल

- राज्य विधि आयोग कर रहा इन कानूनों का अध्ययन
- एक माह में सरकार को सौंपा जाएगा इनको रद करने की सिफारिश का ड्राफ्ट

मध्य प्रदेश सरकार अनुपयोगी हो चुके 250 से ज्यादा कानूनों को खत्म करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य विधि आयोग कानूनों का अध्ययन कर ऐसे कानूनों को खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जो समय के साथ अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। आयोग अब तक करीब 800 कानूनों का अध्ययन कर चुका है। इनमें से 200 से ज्यादा कानून अनुपयोगी पाए गए हैं। यह आंकड़ा 250 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। आयोग अगस्त अंत तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ऐसा कर चुकी है।

पिछले साल गठित प्रदेश का तीसरा विधि आयोग पुराने और अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से नए कानून बनाने पर काम कर रहा है। आयोग ने जनवरी से काम शुरू किया है। प्रदेश में कुछ कानून सीमित अवधि के लिए थे। उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, तो ज्यादातर वर्तमान परिस्थिति में अप्रभावी हो गए हैं। आयोग इन्हें रद करने की सिफारिश का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जो अगले एक माह में राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है।

> प्रदेश में एक हजार से ज्यादा कानून हैं। इनमें से करीब 800 से ज्यादा का हम अध्ययन कर चुके हैं। इनमें से पहली नजर में 200 कानून अनुपयोगी पाए गए हैं। जिनका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही शासन को भेजा जाएगा।
>
> –जस्टिस वेद प्रकाश, अध्यक्ष, मप्र राज्य विधि आयोग

विधि विभाग करेगा विचार : विधि आयोग के ड्राफ्ट पर पहले विधि विभाग काम करेगा। विभाग यह देखेगा कि जिन कानूनों को खत्म करने की सिफारिश की गई है, वे वाकई अनुपयोगी हो गए हैं या नहीं। यदि विभाग की जांच में भी यह कानून अनुपयोगी पाए जाते हैं, तो विभाग अपनी रिपोर्ट के साथ आयोग की सिफारिश शासन को भेज देगा। इसके बाद सरकार इन कानूनों को रद करने का फैसला लेगी।

ये हैं कुछ अनुपयोगी कानून : द मप्र एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1984, द भोपाल गैस त्रासदी (जंगिन संपत्ति के विक्रयों को शून्य घोषित करना) अधिनियम 1985 (जंगिन संपत्ति यानी गैस पीड़ित जो संपत्ति छोड़कर भाग गए), मप्र कैटल डिसीजेज एक्ट 1934, मप्र हॉर्स डिसीजेज एक्ट 1960 'मप्र ग्रामीण ऋण विमुक्ति अधिनियम 1982।

न्यूज गैलरी

चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी 23 तक टली

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने 23 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत देने का फैसला किया है। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की पीठ ने कहा कि पिता–पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत सुनवाई नहीं कर सकी। लिहाजा अदालत 23 अगस्त गिरफ्तारी से राहत देती है। वहीं, सीबीआइ व ईडी के अधिवक्ता सोनिया माथुर, एनके मेहता व नितेश राणा ने मामले में बहस करने के लिए और समय मांगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान पी चिंदबरम ने अदालत को बताया था कि उन्हें अग्रिम जमानत देने से इन्कार करने का कोई आधार नहीं है। दोनों जांच एजेंसियों ने उनकी दलील का विरोध किया था। पिछले साल 25 अक्टूबर को ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आरोप पत्र में कार्ति के सीए एस भास्करन, एयरसेल के पूर्व सीईओ वी श्रीनिवासन, मैक्सिस से अगस्तस रालफ मार्शल, एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क, एयरसेल टेलीवेंचर, मैक्सिस मोबाइल सर्विस, बुमि अरमदा, बुमि अरमदा नेविगेशन को भी नामजद किया गया है। (जासं)

रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें छह अगस्त को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। अग्रिम जमानत याचिका दायर करने से पहले वह ईडी के दफ्तर आए थे, लेकिन शौचालय जाने के बहाने दफ्तर से भाग गए थे। इसके बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इससे पहले अदालत ने छह अगस्त को उन्हें अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका निरस्त कर दी थी।। रतुल हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। (जासं)

कमलनाथ का नया नारा– 'मिलावटखोरों प्रदेश छोड़ो'

भोपाल : भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर 'मिलावटखोरों प्रदेश छोड़ो' का नारा दिया है। उन्होंने लिखा कि देखने में आ रहा है कि थोड़े से स्वार्थ और मुनाफे के लिए मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहर बेचकर उन्हें मौत के आगोश में धकेल रहे हैं। आज अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर मिलावटमुक्त प्रदेश का संकल्प लें। उन्होंने कहा, यह नारा दें कि बहुत हो गया–अब मिलावटखोरों प्रदेश छोड़ो। (नईदुनिया)

अब बैलेट से मतदान कराने का सवाल ही नहीं उठता

किया स्पष्ट ▶ ममता की मतपत्र से चुनाव की मांग को सीईसी ने किया खारिज

कहा–बंगाल में अभी एनआरसी लागू किए जाने की कोई योजना नहीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी) सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पुरानी प्रणाली पर लौटने का कोई सवाल नहीं उठता। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 'ईवीएम नहीं बैलेट चाहिए' का नारा दिया है।

अरोड़ा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मतपत्रों से मतदान फिर शुरू करने के खिलाफ कई बार फैसले दिए हैं। उन्होंने यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हम मतपत्रों के युग में वापस नहीं जाने वाले। उच्चतम न्यायालय कई बार कह चुका है कि मतपत्र अतीत की बात है।' सुनील अरोड़ा और उपचुनाव आयुक्त संदीप जैन दो दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा फाइल फोटो

जम्मू–कश्मीर में चुनाव पर संदेश का है इंतजार

जम्मू–कश्मीर में चुनाव की संभावनाओं पर अरोड़ा ने कहा कि गृह और विधि मंत्रालयों से औपचारिक संदेश का इंतजार है।

एनआरसी पर स्पष्ट की स्थिति

बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू किए जाने के अटकलों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि अभी एनआरसी लागू होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय निर्धारित कर दिया है, लेकिन अभी तक बंगाल के लिए कोई फैसला नहीं आया है। इसीलिए इस मुद्दे पर भविष्यवाणी करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से कई बार कहा गया है कि बंगाल में भी एनआरसी लागू किया जाएगा।

मप्र में ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य व पीएससी को नोटिस

नईदुनिया, जबलपुर : हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसद करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य शासन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) को नोटिस जारी किए हैं। जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी व जस्टिस अंजुलि पालो की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र होशंगाबाद के प्रत्यूष द्विवेदी, टीकमगढ़ के पारस जैन, मुरैना के नितेश जैन व छिंदवाड़ा के रामसुंदर रघुवंशी की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मप्र शासन ने आठ जुलाई, 2019 को राजपत्र में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण के प्रावधान का प्रकाशन कर दिया है। इसी के साथ ही प्रदेश की सरकारी सेवाओं के लिए बने मप्र लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक-2019 लागू कर दिया। इस संशोधन के जरिए प्रदेश की सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया। यह संविधान व सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है। बहस के दौरान अधिवक्ता संघी ने दलील दी कि संविधान व सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

पर्यावरण महाकुंभ : उप्र में एक दिन में 22 .49 करोड़ पौधों का रोपण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पौधारोपण अभियान की संज्ञा दे रखी थी, लेकिन लोगों के जोश और भागीदारी ने शुक्रवार को क्रांति दिवस पर इसे 'पर्यावरण महाकुंभ' का रूप दे दिया। राज्यपाल आनंदी बेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों व विभागीय अधिकारियों ने इस महाअभियान में सोत्साह भागीदारी की। राज्यपाल ने कासगंज में 'पारिजात' का पौधा रोपा तो मुख्यमंत्री ने लखनऊ में इस अभियान का शुभारंभ किया और प्रयागराज में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड समेत कई कीर्तिमानों के साक्षी बने। पूरे प्रदेश 22.49 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। साथ ही अगले साल का लक्ष्य 25 करोड़ पौधों के रोपण का अभी से ही निर्धारित कर दिया गया है। योगी ने घोषणा की कि प्रदेश में जो भी वृक्ष सौ वर्ष की आयु से अधिक के हैं, उन्हें हेरिटेज का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में अक्षयवट सबसे पुराना है। बाराबंकी में पारिजात (कल्पवृक्ष) का पांच हजार साल पुराना पेड़ है। ऐसे पेड़ों की गणना कर इनका संरक्षण किया जाए। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि अब देशी आम के पेड़ नहीं काटे जाएंगे।

सात घंटे में एक ही जगह से बंटे 66 हजार पौधे : प्रयागराज के परेड मैदान में सात घंटे के भीतर 66 हजार पौधों का वितरण कर संगमनगरी ने एक नया कीर्तिमान बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के प्रतिनिधि स्वप्निल डांगरेकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र सौंपा। प्रयागराज से पूर्व आठ घंटे में सबसे अधिक पौधे बांटने का रिकार्ड संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के पास था। वहां 2009 में 9371 पौधों का वितरण किया गया था। प्रयागराज में जो रिकार्ड बना वह उससे लगभग सात गुना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पर्यावरण महाकुंभ के तहत लखनऊ में पौधारोपण किया। जागरण

मनी लांड्रिंग मामले में उद्यमी सतीश सना को न्यायिक हिरासत में भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मांस कारोबारी मोईन कुरैशी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के उद्यमी सना सतीश बाबू को राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने 23 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसकी जमानत अर्जी पर कोर्ट 17 अगस्त को सुनवाई करेगी।

सीबीआइ मोईन कुरैशी से जुड़ी कंपनी के 50 लाख रुपये के शेयरों की सना द्वारा की गई कथित खरीद की जांच कर रही है। सीबीआइ ने 26 जुलाई को मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सना को बुलाया था और जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार कर लिया। 14 दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआइ ने विशेष न्यायाधीश किरण बंसल के समक्ष पेश किया था।

आरोप है कि मोईन कुरैशी के मामले को निपटाने के लिए सना ने सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को रिश्वत दी थी। इसी मामले में तत्कालीन सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना और उनके अधीनस्थों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। वहीं, दूसरी तरफ से अस्थाना के करीबी अधिकारियों ने वर्मा पर भी यही आरोप लगाया है। बाद में मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तक पहुंचा था और सीवीसी ने जांच शुरू की जिसके बाद सीवीसी ने पहले तो वर्मा को छुट्टी भेज दिया और फिर आलोक वर्मा को सीबीआइ निदेशक के पद से हटा दिया गया था।

सारधा घोटाले में डेरेक ओ ब्रायन से पूछताछ

जागरण संवाददाता, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन से सीबीआइ ने सारधा चिटफंड घोटाले में शुक्रवार को पूछताछ की। सीबीआइ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डेरेक से तृणमूल के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' के बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेन-देन को लेकर पूछताछ की गई। गौरतलब है कि बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने वाले इस मुखपत्र के प्रकाशक डेरेक हैं। सीबीआइ ने गत 26 जुलाई को उन्हें सारधा मामले की जांच में शामिल होने के लिए तलब किया था। डेरेक को अगस्त के पहले हफ्ते पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होने को कहा गया था। डेरेक ने संसद का मानसून सत्र चलने का हवाला देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी से पेश होने के लिए कुछ समय मांगा था। संसद का सत्र सात अगस्त को खत्म हो गया था। इसके बाद शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे सीबीआइ के साल्टलेक के सीजीओ कांप्लेक्स स्थित कार्यालय में वह हाजिर हुए। सूत्रों के मुताबिक, उनसे मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की पेंटिंग्स की बिक्री को लेकर भी पूछताछ की गई है।

गोवा के सीएम का कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता को सम्मानित करने का आग्रह

पणजी, आइएएनएस : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मौजूदा विधायक प्रताप सिंह राणे को सम्मानित करने का आग्रह किया है। सावंत ने राणे के वर्ष 2022 में विधानसभा में 50 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में यह सम्मान समारोह रखने का आग्रह किया है। बता दें कि राणे उन नेताओं में रहे हैं, जिन्होंने अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद 35-ए पर प्रधानमंत्री के निर्णय का समर्थन किया था। उनके बेटे विश्वजीत राणे राज्य की भाजपा नीत गठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं।

सावंत ने विधानसभा को बताया कि राणे मौजूदा विधानसभा (2022) का कार्यकाल खत्म होने तक एक विधायक के रूप में 50 साल पूरा कर लेंगे। ऐसे में मैं विधानसभा अध्यक्ष राजेश पटनेकर से आग्रह करूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में समारोह का आयोजन किया जाए। सावंत ने कहा कि राणे उन विधायकों में से हैं, जो विधायक, विपक्ष के नेता सहित कई बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। सावंत ने राणे को सम्मानित करने का अनुरोध ऐसे समय किया है जब 2017 के बाद से अब तक कांग्रेस 13 विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। राणे पहली बार महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर 1972 में विधानसभा पहुंचे थे। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए और कई बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वह 1972 से पोरियल विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं।

सीबीआइ से पूछेगी पंजाब सरकार– बिट्टू नहीं तो कौन था बेअदबी का दोषी

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर जांच कर रही सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को पंजाब सरकार अदालत में चुनौती देगी। सरकार पूछेगी कि अगर बेअदबी की घटनाओं के लिए पटियाला की नाभा जेल में मारा गया डेरा प्रेमी महिंदरपाल बिट्टू दोषी नहीं है, तो असली दोषी कौन है? सरकार यह भी कहने जा रही है कि जब छह सितंबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी करके सीबीआइ से केस लौटाने को कहा गया था और हाई कोर्ट ने भी पूर्व एसएसपी चरनजीत शर्मा की ओर से पंजाब सरकार की एसआइटी को चुनौती दी थी, तब भी हाई कोर्ट ने एसआइटी के गठन को वाजिब ठहराया था।

हालांकि, सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि सीबीआइ की ओर से नोटिफिकेशन पर अमल न करने को चुनौती कहां देनी है? इसके लिए मंत्रणा चल रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो दिन पहले देर शाम तक अपने सीनियर अधिकारियों, कानून विशेषज्ञों के साथ मीटिंग करके सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए कहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सतीश चंद्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इसके लिए ऐसे वकील की सेवाएं ली जाएंगी जो सीबीआइ के केस लड़ने में महारत रखता हो। गृह विभाग ने एजी पंजाब को वकीलों का पैनल देने के लिए कहा है।

सीबीआइ ने चार जुलाई को दी थी क्लोजर रिपोर्ट : गौरतलब है कि सीबीआइ ने चार जुलाई को इस मामले में यह कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी कि इस मामले में 18 लोगों का मनोवैज्ञानिक टेस्ट के साथ ही शिकायतकर्ता ग्रंथी का पोलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया, लेकिन जांच में किसी की भागीदारी साबित नहीं हो सकी। इसके अलावा अपमानजनक टिप्पणी वाले पोस्टरों और आरोपियों की लिखावट में एकरूपता नहीं मिली। सीएम ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सीबीआइ को बेअदबी के केस के दोषियों को पता लगाने के लिए केस दिया गया था। अगर पंजाब पुलिस की ओर से आरोपित किए गए दोषी नहीं हैं तो कोई तो दोषी है? सीबीआइ ने उस तरफ जांच क्यों नहीं की? साफ है कि क्लोजर रिपोर्ट देने में जल्दबाजी की गई है।

विधायकों की नाराजगी के चलते सरकार दबाव में

कांग्रेस में कई विधायक क्लोजर रिपोर्ट को लेकर अपनी ही सरकार दबाव बना रहे हैं। दरअसल वे इस बात से नाराज हैं कि एसआइटी के डीजीपी प्रबोध कुमार ने सीबीआइ को फिर से जांच करने के लिए पत्र क्यों लिखा? ये सभी विधायक प्रबोध कुमार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया।

झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार का इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखकर राज्य के आधा दर्जन नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ पार्टी में नए अध्यक्ष के लिए जोड़तोड़ शुरू हो गई है।

डॉ. अजय ने अपने इस्तीफे का ठीकरा राज्य के वरिष्ठ नेताओं पर फोड़ा है। राहुल को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा है कि चंद नेता पैसे के बल पर लोगों को दिल्ली ले जाते हैं, होटलों में ठहराते हैं और प्रदेश कांग्रेस के बारे में झूठी कहानियां फैलाते हैं। ऐसे नेता पार्टी गतिविधियों के लिए पांच हजार रुपये प्रति महीना चंदा देने को भी तैयार नहीं हैं। तीन पेज के इस्तीफे की प्रति सोनिया गांधी, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी के कार्यालय को भी भेजी गई है।

डॉ. अजय कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ पुराने कांग्रेसियों ने उन्हें प्रदेश मुख्यालय में प्रवेश करने से रोकने के लिए गुंडों को काम पर लगाया, तो सुबोधकांत सहाय ने किन्नरों को मेरा विरोध करने के लिए उकसाया।

डॉ. अजय कुमार के इस्तीफे के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ नाम सामने आ रहे हैं, उनमें सुबोधकांत सहाय का नाम सबसे आगे है।

बदले हालात

करीब चार साल पहले राजद प्रमुख ने परिवार के अन्य सदस्यों की अनदेखी कर छोटे बेटे को बनाया था उत्तराधिकारी, लोस चुनाव में हार के बाद अब ढीली पड़ती जा रही है पार्टी पर उनकी पकड़

तेजस्वी ने लालू की विरासत को मझधार में छोड़ा

अरविंद शर्मा, पटना

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने तकरीबन चार साल पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए बड़ी हसरत से अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को राजनीतिक उत्तराधिकार सौंपा था। उम्मीद थी कि लालू के सपने को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआती दो-तीन सालों में तेजस्वी ने ऐसा किया भी, किंतु लोकसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी ने लालू की अनुपस्थिति में नाव की पतवार छोड़ दी। अभी लालू की 22 साल पुरानी पार्टी एवं परिवार दोनों मझधार में हैं और तेजस्वी करीब ढाई महीने से नेपथ्य में हैं।

करीब दो साल बाद शुक्रवार को शुरू हुए राजद के सदस्यता अभियान के उद्घाटन के मौके पर सबको तेजस्वी का इंतजार था। तीन दिन पहले तेजस्वी ने आने का वादा किया था। उनसे सहमति लेने के बाद ही राजद की ओर से मीडिया को बताया गया था कि पटना में तेजस्वी ही अभियान की शुरुआत करेंगे। इसीलिए कार्यक्रम के दौरान भी उनका बेसब्री से इंतजार होता रहा। जब दिल्ली से आने वाली दोपहर की फ्लाइट से भी तेजस्वी नहीं आए तो मायूसी पसर गई। नेता मीडिया के सवालों पर बहाने बनाने लगे। शिवानंद ने कहा कि मुझसे तो तेजस्वी ने 16 अगस्त के बाद आने के लिए कहा था। आज क्यों इंतजार हो रहा है? बहरहाल, राजद के मंच से सबने सबको धैर्य बंधाया। पार्टी को अटूट-एकजुट बताया और कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रखने की कोशिश की। कामयाबी कितनी मिली, यह तो नए बनने वाले सदस्यों की संख्या और पार्टी के कोष में वृद्धि से ही पता चल सकेगा। खुद राबड़ी देवी विधान पार्षद हैं। डॉ. मीसा भारती राज्यसभा सदस्य हैं और तेजप्रताप यादव विधायक हैं। सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव अगर नहीं आए तो कार्यक्रम की औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेवारी दूसरे ने क्यों नहीं उठाई? आखिर क्या मजबूरी थी कि चार में से एक ने भी आने की जरूरत नहीं समझी? लालू और तेजस्वी की अनुपस्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य आ जाता तो कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश जाता।

पौने तीन महीने से राबड़ी देवी को छोड़कर राजद का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। लोकसभा के आखिरी दौर के प्रचार खत्म होने के दिन 17 मई से ही तेजस्वी अदृश्य हैं। ऐसे गायब हुए कि अपना वोट डालने भी नहीं आए। 11 दिन बाद 28 मई को आकर हार की समीक्षा की। एक टीम बनाई। रिपोर्ट मांगी। किंतु उसे देखने की जरूरत नहीं समझी। इस दौरान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। उनके लापता होने के बैनर-पोस्टर भी लगने लगे। अचानक 33 दिन बाद पटना लौटे और मीडिया को बताया कि घुटने में दर्द का दिल्ली में इलाज करा रहा था। दो दिन सदन में गए। कुछ बोले नहीं। इसी दौरान राजद के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेना जरूरी नहीं समझा। अगले दिन राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में भाग तो लिया, लेकिन फिर दिल्ली कूच कर गए, जो अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। सवाल लाजिमी है कि आखिर तेजस्वी इतने क्यों नाराज हैं कि पार्टी और परिवार की जरूरतों को भी समझना नहीं चाह रहे।

तेजस्वी यादव फाइल फोटो

मांझी के बदले सुर, कहा– अकेले लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी के सुर एक बार फिर बदलते नजर आ रहे हैं। मांझी ने कहा, एनडीए हो या महागठबंधन उन्हें हर बार ठगा गया है। पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं की मांग है कि पार्टी स्वतंत्र रूप से विधानसभा चुनाव लड़े। अपने सरकारी आवास पर शुक्रवार को पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ करते हुए मीडिया से मांझी ने उक्त बातें कहीं।

मांझी ने इस दौरान केंद्र की एनडीए सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि आज आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आयोग बनाकर जांच होनी चाहिए कि आज तक अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा को सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण दिया गया। मांझी ने न्यायपालिका में भी आरक्षण देने की मांग की।

मांझी ने कहा कि वह कई गठबंधनों में रहे, लेकिन हर गठबंधन ने उन्हें ठगा है। लोकसभा चुनाव में कहने को उन्हें तीन सीटें दी गई, लेकिन उनका प्रत्याशी सिर्फ एक सीट पर लड़ा। दो सीटों में से एक पर कांग्रेस और एक पर राजद प्रत्याशी को लड़ाया गया। उन्होंने कहा कि इन तमाम तथ्यों को देखते हुए पार्टी में काफी नाराजगी है और पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता चाहता है हमें विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। मांझी ने कहा वे इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे।

जीतन राम मांझी फाइल फोटो

कांटे की टक्कर में वेल्लोर लोकसभा सीट पर द्रमुक ने किया कब्जा

वेल्लोर, प्रेट्र : तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट पर द्रमुक के डीएम काथिर आनंद ने कांटे की टक्कर में निकटम प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक के एसी षणमुगम को 8,141 मतों के बेहद कम अंतर से हरा दिया। राज्य की 38 अन्य लोकसभा सीटों की तरह वेल्लोर के लिए भी अप्रैल में ही चुनाव होना था, लेकिन तैयारियों के दौरान वहां भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद चुनाव को रद कर दिया गया था। यहां पांच अगस्त को मतदान हुए और शुक्रवार को परिणाम घोषित हुआ। राज्य की सत्ताधारी पार्टी अन्नाद्रमुक के लिए वेल्लोर सीट प्रतिष्ठापूर्ण हो गई थी और वह हर हाल में इसे बचाए रखना चाहती थी। कारण है कि अप्रैल में राज्य की 38 लोकसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 37 पर द्रमुक गठबंधन को जीत मिली थी। द्रमुक प्रत्याशी आनंद पार्टी के कोषाध्यक्ष दुरई मुरुगन के बेटे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि आनंद को 4,85,340 (47.3 फीसद) मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी षणमुगम को 4,77,199 (46.51 फीसद) वोट हासिल हुए। इस सीट पर वर्ष 2014 में द्रमुक की धुर विरोधी पार्टी अन्नाद्रमुक ने जीत दर्ज की थी।

4 दिनों में रेलवे ने घाटी से जम्मू लौटे दूसरे राज्यों के करीब 50 हजार श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इसमें अधिकतर श्रमिक बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं।

दो टूक ▶ कश्मीर पर पाकिस्तान के रोने-धोने का नहीं हो रहा असर, भारत के फैसले पर पड़ोसी देश को इस्लामिक देशों का भी नहीं मिला साथ

चीन व अमेरिका ने कहा-कश्मीर द्विपक्षीय मामला, बातचीत से सुलझाएं

अमेरिका ने दोनों पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने का किया आह्वान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मॉर्गन ओर्टागस फाइल फोटो

अनुच्छेद 370 को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान को दुनिया के प्रमुख देशों से कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। शुक्रवार को दुनिया के दो ताकतवर देशों अमेरिका और चीन ने साफ कर दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। इसको लेकर उनकी मंशा हस्तक्षेप करने की नहीं है। दोनों ने भारत व पाकिस्तान को बातचीत से राह निकालने को कहा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा धक्का इस बात से लगा कि अभी तक किसी बड़े इस्लामिक देश ने भी कश्मीर मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है।

अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस ने कहा, 'कश्मीर पर अमेरिकी नीति यही रही है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला है और इस मामले पर वार्ता कब और कैसे करनी है इसका फैसला दोनों देशों को ही करना है। अमेरिका की इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।' उन्होंने कहा, 'हमने सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने का आह्वान किया है। हम शांति और स्थायित्व बनाए रखना चाहते हैं और कश्मीर व अन्य मसलों पर भारत-पाक के बीच सीधी वार्ता का समर्थन करते हैं।'

चीन ने भी भारत-पाक से कहा है कि वो आपसी बातचीत के जरिये ही किसी भी द्विपक्षीय समस्याओं का समाधान निकाले। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जरूर कहा है कि दोनों देशों को मौजूदा हालात को बनाए रखने की जरूरत है ताकि तनाव को बढ़ने से रोका जा सके।

स्थिति के बारे में दी गई जानकारी : जानकारों की मानें तो भारत ने जिस तरह से कश्मीर पुनर्गठन से जुड़े अपने फैसलों को दुनिया के सामने रखा है उसका भी असर हो रहा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने दुनिया के तमाम प्रमुख देशों के राजनयिकों को अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने की वजहों के बारे में विस्तार से बताया है। कश्मीर में ज्यादा सेना भेजने व वहां कर्फ्यू लगाए जाने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। यही वजह है कि यूरोपीय संघ के किसी भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने अपने स्तर पर भारत के कदम की आलोचना जरूर की है लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठनों की तरफ से लगातार यह बयान आए हैं कि भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करे।

कुरैशी पहुंचे चीन, जयशंकर जाएंगे रविवार को : कश्मीर पर त्राहिमाम संदेश लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आनन-फानन में चीन पहुंचे हैं। दो दिन बाद 11 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन जा रहे हैं। वैसे कुरैशी की इस यात्रा का एकमात्र एजेंडा कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार के फैसले के खिलाफ समर्थन जुटाना है। दूसरी तरफ जयशंकर की यात्रा का एजेंडा बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर जयशंकर की यात्रा के दौरान कश्मीर का मुद्दा भी उठेगा लेकिन वह मुख्य तौर पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सितंबर, 2019 में होने वाली भारत यात्रा की तैयारियों को लेकर है।

पाक के पत्र पर सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का टिप्पणी से इन्कार

न्यूयॉर्क, एएनआइ : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष जोआना रोनेका ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के विरोध में पाकिस्तान के लिखे पत्र पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है। भारत ने इसी सप्ताह जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर वहां का विशेष दर्जा खत्म कर दिया है और उसे दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है।

प्रेस कांफ्रेंस में इस बाबत पूछे गए सवाल में जोआना ने संक्षिप्त उत्तर दिया- नो कमेंट्स। जम्मू-कश्मीर पर भारत के कदम के विरोध में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को सुरक्षा परिषद के संकल्प का उल्लंघन बताया है। इससे पहले महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने जम्मू-कश्मीर के हालात पर चिंता जताते हुए भारत और पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पर अधिकतम संयम बरतने की अपील की थी। महासचिव ने 1972 में दोनों देशों के बीच हुए शिमला समझौते के मंतव्य का उल्लेख करते हुए आपसी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की

जोआना रोनेका फाइल फोटो

बात कही। समझौते में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार जम्मू-कश्मीर का मसला सुलझाने की बात कही गई है। शिमला समझौते का उल्लेख करते हुए महासचिव की मंशा उनके प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने अवगत कराई है।

बयान में कहा गया है कि महासचिव ने सभी संबद्ध पक्षों से जम्मू-कश्मीर के संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले संयम बरतने की आवश्यकता जताई है। भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया है और भारत के साथ राजनयिक संबंधों को सीमित कर दिया है।

पाकिस्तानियों पर महंगाई की मार

इस्लामाबाद, एएनआइ : बौखलाए पाकिस्तान ने जो दांव चला, वह उलटे उसी पर भारी पड़ सकता है। पाक ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों का दर्जा कम करने के साथ ही कारोबारी रिश्ते भी तोड़ लिए। अब यह आशंका जताई जा रही है कि इसका खामियाजा पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ सकता है। पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों पर इसकी और मार पड़ सकती है। खाद्य पदार्थों के दाम आसमान पर पहुंच सकते हैं। बकरीद की खुशियां फीकी हो सकती हैं।

पाकिस्तानी कारोबारियों और आम नागरिकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते पहले ही व्यापार और घरों का बजट बिगड़ा हुआ है। अब भारतीय खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगने से मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। इससे बकरीद का त्योहार भी अछूता नहीं रह पाएगा। लोगों के लिए त्योहार मनाना मुश्किलों भरा होने जा रहा है। नजमा नाम की एक गृहिणी ने कहा, 'बढ़ती महंगाई से रसोईघर का खर्च गड़बड़ा गया है। आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन दूध से लेकर सब्जियां और मीट सब कुछ महंगा हो गया। अब भारत के साथ कारोबार रोकने से सभी चीजों के दाम फिर बढ़ जाएंगे।' प्याज कारोबारी इफ्तिखार ने कहा, 'बकरीद में महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन बाजार एकदम ठंडा है। हम सब्जियों और प्याज के लिए भारत पर निर्भर हैं। बकरीद पर ये जरूरी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि प्याज और सभी चीजों की कीमतें और बढ़ जाएंगी। इमरान खान क्या चाहते हैं, हम क्या खाएं?' अशफाक नामक एक बैंकर ने कहा, 'यकीनन इस बार बकरीद फीकी होने जा रही है। इसके बार शुरू होने वाले शादियों के सीजन पर भी भारत के साथ कारोबारी संबंध तोड़ने का असर पड़ेगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या सोचकर भारत के साथ कारोबारी संबंध तोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है?'

डीजल 132 रुपये प्रति लीटर

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार ने इस महीने के शुरू में पेट्रोल 5.15 रुपये और डीजल 5.65 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया। इस वृद्धि के बाद पेट्रोल 117.83 रुपये और डीजल 132.47 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

कैबिनेट की बैठक में महज सात मिनट में हो गया था जम्मू-कश्मीर के भाग्य का फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कश्मीर का 'जोश' अब जमीन तक पहुंचाएगी भाजपा
- भाजपा शासित राज्यों में पारित होंगे पीएम व गृह मंत्री के अभिनंदन प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले से पूरा देश जोश से भर गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव की सबसे अहम बात यह रही कि गत सोमवार को जब कैबिनेट की बैठक हुई तो महज सात मिनट में यह फैसला ले लिया गया। इन सात मिनटों में भी आधे वक्त तक इस फैसले पर मेजें थपथपाई जाती रहीं। उसी वक्त यह आगाह भी कर दिया गया था कि बाहर इसे जश्न की तरह पेश नहीं किया जाएगा। सभी राज्यों को इस आशय की एडवाइजरी भी दी गई थी, लेकिन अब जब धीरे-धीरे इस पर पूरे देश में आम लोगों से लेकर विपक्षी दलों में भी समर्थन बढ़ने लगा है, तो भाजपा ने इस फैसले को जमीन तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। इस के लिए कार्यक्रम भी बना लिए हैं। जिलास्तर तक प्रेस कांफ्रेंस कर इसके अर्थ भी समझाए जाएंगे और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई भी दी जाएगी। भाजपा शासित राज्यों के विधानसभाओं में इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के अभिनंदन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बहुत गुप्त रखा था। इसीलिए जब कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी तो सदस्य आश्चर्यचकित रह गए थे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने का कदम जाहिर तौर पर विचारधारा के रूप में भाजपा की बहुत बड़ी जीत है और जनभावना के इतने करीब है कि विपक्षी दल कांग्रेस में भी इस पर अलग-अलग राय है। ऐसे में अब भाजपा इसे जमीन तक ले जाएगी। पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से सभी प्रदेश अध्यक्षों को जारी निर्देश में कहा गया है कि अगले दो-तीन दिनों में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेसवार्ता आयोजित कर लोगों को इसकी जानकारी दें।

दरअसल, इस फैसले ने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार शासन-प्रशासन के साथ-साथ वैचारिक मुद्दों पर भी बड़े कदम उठाएगी। पिछली मोदी सरकार ने सुधार के बड़े कदम उठाए थे, लेकिन विचारधारा से जुड़े मुद्दों पर बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी। इस बार शुरुआत में ही अनुच्छेद 370 पर वार कर कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ा दिया है।

अब इमरान ने भारत पर युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लगाए आरोप

इस्लामाबाद, प्रेट्र : कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। उसकी यह बौखलाहट दुनिया के दूसरे देशों से समर्थन नहीं मिलने पर हताशा में बदलती जा रही है। इस हताशा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी तक बेसिर पैर की बातें करने लगे हैं। इसी कड़ी में पाक पीएम इमरान खान ने भारत पर युद्ध जैसे हालात पैदा करने के आरोप लगाए हैं। भारत ने इमरान खान के बयान को पाकिस्तान की नई चाल बताया है।

इमरान खान ने गुरुवार को यहां कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि कश्मीर की घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए भारत पुलवामा के बाद एक बार फिर युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हालात गंभीर हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उन्हें लग रहा है कि दोनों देशों में युद्ध शुरू हो सकता है।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक इमरान खान बौखलाहट में यहां तक तक चले गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। खान ने कि भाजपा ऐसा भारत बनाना चाहती है जिसमें हिंदुओं का प्रभुत्व हो। वह नाजियों की तरफ कश्मीर में मुस्लिमों का

इमरान खान फाइल फोटो

नरसंहार करना चाहती है। वह कश्मीर में नस्लीय सफाए की कोशिश में है।

भारत से सांस्कृतिक संबंध तोड़ेगा पाक : पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के सांस्कृतिक संबंध खत्म करने का भी फैसला किया है। पाक सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को 'से नो टू इंडिया' अभियान भी शुरू किया। भारतीय फिल्मों पर भी पाबंदी लगा दी है।

सूचना प्रसारण पर प्रधानमंत्री इमरान खान की विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि भारत के सभी मनोरंजन कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भारतीय डीटीएच उपकरणों की बिक्री रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने थार एक्सप्रेस को बंद करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके रेल मंत्री रहते पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी।

पाकिस्तानी कलाकारों पर पाबंदी की मांग

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान द्वारा भारतीय फिल्मों पर पाबंदी लगाने के जवाब में आल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिख कर पाकिस्तान के सभी कलाकारों पर देश में काम करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। एसोसिएशन ने पाकिस्तान से राजनयिक समेत सभी तरह के संबंध भी तोड़ने की अपील की है। साथ ही भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से भी पाकिस्तानी कलाकारों, संगीतकारों और राजनयिकों से किसी तरह के संबंध नहीं रखने को कहा है।

अफगानिस्तान को कश्मीर मुद्दे से नहीं जोड़े पाकिस्तान : तालिबान

काबुल, आइएएनएस : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने और राज्य के पुनर्गठन से बौखलाए पाकिस्तान को अब तालिबान से भी करारा झटका लगा है। तालिबान ने पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान और कश्मीर मुद्दे को जोड़ने का विरोध किया है। वहीं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा है कि वह क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल नहीं करे। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि कश्मीर के मुद्दे को कुछ पक्षों की ओर से अफगानिस्तान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे संकट से निपटने में किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के मुद्दे का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में फंसना नहीं चाहता है। इसके अलावा काबुल में गुरुवार को पाकिस्तान के दूतावास ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा अफगानिस्तान में चल रहे शांति अभियान को प्रभावित नहीं करेगा।

जम्मू-कश्मीर की जेल से बरेली शिफ्ट किए 20 बंदी

जागरण संवाददाता, बरेली : जम्मू-कश्मीर की जेल में बंद 20 बंदियों को उत्तर प्रदेश के बरेली की जिला जेल में शिफ्ट किया गया है। शुक्रवार दोपहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विशेष हवाई जहाज से उन्हें त्रिशूल एयरबेस लाया गया। वहां से जिला जेल भेजा गया। सभी को पांच-पांच का समूह बनाकर अलग बैरकों में रखा गया है। जम्मू-कश्मीर के बंदी शिफ्ट होने के बाद जिला जेल में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया। जेल के बाहर पीएसी लगा दी गई है। स्थानीय थाने की पुलिस 24 घंटे लगातार आसपास गश्त करेगी। बता दें कि गुरुवार को भी जम्मू-कश्मीर की जेल से 26 बंदी आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए गए थे।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विशेष एहतियात बरती जा रही, अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही वहां की जेल में बंद बंदियों को शिफ्ट किया जा रहा है। इसी के चलते दोपहर करीब 12 बजे हवाई जहाज से 20 बंदियों को जम्मू-कश्मीर से बरेली के त्रिशूल एयरबेस लाया गया। वहां से सभी को पुलिस की बंद गाड़ी में बैठाकर जिला जेल लाया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियां साथ चल रही थीं।

भारत के फैसले का बौद्ध धर्मगुरुओं ने किया स्वागत

कोलंबो, एएनआइ : श्रीलंका के दो प्रमुख बौद्ध धर्मगुरुओं ने लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का स्वागत किया है। मालवत्ते संप्रदाय के सिद्धार्थ सुमंगला महानायके थेरास और असगिरिया संप्रदाय के ज्ञानरत्ने महानायके थेरा ने भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे श्रीलंका और भारत के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों में और मजबूती आएगी। भारत सरकार ने इस सप्ताह लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया। इस निर्णय से लद्दाख देश का पहला बौद्ध बहुलता वाला प्रदेश बन गया है। लद्दाख में बौद्ध धर्म मानने वालों की आबादी 70 फीसद के करीब है।

फैसले को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती

जेएनएन, जम्मू : जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को संयुक्त हाई कोर्ट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरेटरी (यूटी) में चुनौती दी गई है। दिल्ली के वकील शम्स ख्वाजा ने हाई कोर्ट की जम्मू विंग में यह याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 और उसके बाद जारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करने की मांग की है।

याचिका में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की वकालत करते हुए कहा गया कि इस पुनर्गठन में जम्मू की सबसे अधिक अनदेखी हुई है। केंद्र सरकार ने जम्मू की दशकों पुरानी मांग की अनदेखी करते हुए जम्मूवासियों को विशेष दर्जे के तहत मिले अधिकार छीनते हुए एकतरफा फैसला लिया। इस मामले में एडवोकेट परिमोक्ष सेठ ने भी एक कैविएट दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि अगर अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने व राज्य का पुनर्गठन करने संबंधी कोई भी याचिका दायर होती है तो उस पर सुनवाई करते समय उनका पक्ष भी सुना जाए। अब हाई कोर्ट जब भी इस मामले पर सुनवाई करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा। वहीं, एडवोकेट शम्स ख्वाजा ने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ने आनन-फानन में जम्मू-कश्मीर को विभाजित करने का कानून लाया और जिस प्रक्रिया को अपनाकर इस बिल को पारित करवाया, वह असंवैधानिक था। उन्होंने कहा कि अपनी बहस के दौरान वह हाई कोर्ट को बताना चाहेंगे कि किस तरह केंद्र सरकार भारतीय संविधान की धारा 2 और 3 का उल्लंघन करते हुए यह कानून लाई।

केंद्र शासित प्रदेश में कम नहीं होगा कोई जिला

राज्य ब्यूरो, जम्मू

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा, लेकिन किसी मौजूदा जिले का वजूद खत्म नहीं होगा। अलबत्ता, कुछ जिलों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन को बेहतर बनाने और लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में मौजूदा 20 जिलों में से किसी को समाप्त नहीं किया जा रहा है। इस समय 10 जिले कश्मीर में और 10 जिले जम्मू प्रांत में हैं, लेकिन प्रशासनिक गतिविधियों को सरल बनाने और लोगों की सुविधा के लिए कुछ जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव की गुंजाइश है। इसके अलावा केंद्र शासित राज्य को पूरी तरह व्यवस्थित बनाए जाने के समय कुछ नए जिले और ब्लॉक भी वजूद में आ सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया हाल फिलहाल में नहीं होगी। इसे राज्य में विधानसभा के गठन के बाद या फिर विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान अपनाया जा सकता है।

बढ़ेगी सीटों की संख्या : पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 90 की जानी है और इनकी हदबंदी के लिए जल्द ही एक परिसीमन आयोग भी बनाया जाएगा। नए विधानसभा क्षेत्रों का गठन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में 114 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे, लेकिन चुनाव 90 सीटों पर होगा। शेष 24 सीटें गुलाम जम्मू-कश्मीर के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा प्रस्तावित विधानसभा में राज्य सरकार के पास दो महिला विधायकों को नामांकित करने का अधिकार रहेगा।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई : इस बीच, मंडलायुक्त जम्मू संजीव वर्मा ने किसी मौजूदा जिले को समाप्त किए जाने की संभावना को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी मौजूदा जिले को समाप्त कर जम्मू प्रांत में छह जिले बनाने की बात हास्यास्पद और अफवाह है। अफवाह फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कश्मीर में शरारती तत्वों पर नकेल कसें : डोभाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिलकर राज्य के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ईद-उल-जुहा पर किए जा रहे प्रबंधों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित सुरक्षाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि वे कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों पर नकेल कसें। इसके साथ ही आम लोगों के जानमाल की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा वे स्थानीय लोगों और सुरक्षाबलों से भी मिले।

एनएसए अजीत डोभाल ने शुक्रवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। एएनआइ

घाटी में हालात की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद निगरानी कर रहे हैं। वह वादी के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर स्थानीय लोगों और सुरक्षाबलों से भी मिलकर हालात की जानकारी ले रहे हैं। वह सोमवार को कश्मीर आए थे। बुधवार को वह दिल्ली लौटे थे। वहीं, शुक्रवार सुबह वह नई दिल्ली से दोबारा श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से हालात पर चर्चा की।

जम्मू में धारा 144 हटी, आज खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

जागरण संवाददाता, जम्मू

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू शहर में बंद किए गए स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण शनिवार को पांच दिन बाद खुल जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान ने शुक्रवार शाम को आदेश जारी कर जम्मू शहर में लगी धारा 144 को हटाने और स्कूल, कॉलेज खोलने की अनुमति दी। जम्मू सहित पूरे राज्य में रविवार देर रात से धारा 144 लगाई गई थी और सोमवार से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद थे। जम्मू को छोड़ सांबा, कठुआ व ऊधमपुर जिले में सभी शिक्षण संस्थान शुक्रवार को ही खुल गए, जबकि जम्मू शहर में शनिवार से खुल जाएंगे। स्कूल, कॉलेज खोले जाने के आदेश के बाद हालांकि पंद्रह अगस्त के बाद ही कक्षाएं सुचारू होंगी।

बदलते हालात

प्रशासन की ओर से लगाई गई पाबंदी के बीच शुक्रवार को शहर की सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ी गई नमाज

जम्मू में दुकानें खुलीं, सड़कों पर दौड़ीं मिनी बसें

जागरण संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर लगाई गई पाबंदी के बीच शुक्रवार को शहर की सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक ढंग से नमाज पढ़ी गई। एहतियात के तौर पर सभी धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आपात स्थित से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों को विशेष तौर पर तैनात किया गया था। वहीं, शहर के विभिन्न हिस्सों में जनजीवन पटरी पर लौटता नजर आया। बाजार खुले। प्रशासन ने यात्री वाहनों को अभी सड़क पर नहीं उतारा है। इसके बावजूद कुछ रूटों पर मिनी बस दौड़ीं।

प्रशासन ने जुमे की नमाज के मद्देनजर दोपहर तीन बजे से दुकानें खोलने की छूट दी थी। जम्मू सिटी नार्थ (पुराने शहर) के थाना क्षेत्रों में प्रशासन ने दोपहर तीन बजे तक किसी भी बाजार को खुलने नहीं दिया। पिछले कुछ दिन से शहर में पुलिस के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात किए थे। शुक्रवार को पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया। पुराने शहर के सिटी, पीर मिट्ठा,

शुक्रवार को जम्मू के पुराने शहर की सब्जीमंडी खुली तो लोग खरीदारी करने को पहुंचने लगे। जागरण

पक्काडंगा, बस स्टैंड, जानीपुर, बख्शी नगर थाना क्षेत्रों में चार से अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया। पाबंदी इतनी सख्ती से लागू की थी कि सुबह के समय शहर में चल रही मिनी बसों को सुरक्षा बलों ने बंद कर दिया। शाम के बाद दुकानों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया था।

सिटी साउथ क्षेत्र में नहीं रहा पाबंदी का असर : सिटी साउथ पुलिस डिवीजन के अंतर्गत गांधी नगर, छन्नी हिम्मत, सतवारी, गंग्याल, बागे बाहु और त्रिकुटा नगर थाना क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदी का असर नहीं दिखा। गांधी नगर के अप्सरा रोड पर शुक्रवार सुबह कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे और दुकानें बंद करने को कहा। इस बात को लेकर दुकानदार और पुलिसकर्मियों में कहासुनी भी हुई। दुकानदारों का तर्क था कि ईद आ रही है। लोगों ने उनकी दुकान में खरीदारी करने के लिए आना है। डिवीजन के अन्य क्षेत्रों में सामान्य दिनों की तरह हीं दुकानें खुली रही। कई रूट पर मिनी बसें भी चल रही थी। शहर से लगते रूरल पुलिस डिवीजन दोमाना, कानाचक्क, अखनूर, नगरोटा, झज्जरकोटली में हालात सामान्य रहा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने जिले से सभी दुकानदारों को दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी थी। प्रशासन के इस आदेश के उलट दिन भर दुकानें खुली रहीं। यात्री वाहन सड़कों पर दौड़ते रहे।

सीआरपीएफ के बजाय आरएएफ तैनात : शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए थे। भीड़ से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को विशेष तौर पर तैनात किया गया था।

सीताराम येचुरी और डी राजा को श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली लौटाया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी राजा को शुक्रवार को प्रदेश माकपा सचिव मुहम्मद यूसुफ तारीगामी से मिले बगैर दिल्ली लौटना पड़ा। उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने रोक लिया और बाहर नहीं निकलने दिया।

गौरतलब है कि प्रदेश माकपा नेता मुहम्मद यूसुफ तारीगामी को पुलिस ने अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ कथित तौर पर हिरासत में ले रखा है। तारीगामी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। येचुरी और डी राजा शुक्रवार को दिल्ली से श्रीनगर तारीगामी और प्रदेश के अन्य नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। यह दोनों नेता सुबह दस बजे के करीब इंडिगो के विमान में श्रीनगर पहुंचे। इससे पहले वे एयरपोर्ट से बाहर निकलते, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। शहर में तनाव है और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। वे सुरक्षा कवच में भी शहर में नहीं घूम सकेंगे।

हालांकि सीताराम येचुरी ने गुरुवार शाम को ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक को एक पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि वह शुक्रवार को श्रीनगर में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुहम्मद यूसुफ तारीगामी से मिलने आ रहे हैं। माकपा महासचिव ने राज्यपाल के नाम अपने पत्र में लिखा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पार्टी के एक जिम्मेदार नेता के तौर पर निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों को पूरा करने में प्रशासन की तरफ से कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। अलबत्ता, शुक्रवार को प्रशासन ने माकपा और भाकपा के नेताओं को श्रीनगर में दाखिल नहीं होने दिया। दोनों को एयरपोर्ट से ही दिल्ली लौटने के लिए मजबूर कर दिया। माकपा ने राज्य प्रशासन के इस कदम की निंदा की है। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि गत गुरुवार को राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को भी पुलिस ने श्रीनगर शहर में दाखिल नहीं होने दिया था।

जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा मनमाने तरीके से हटाया गया : तुषार गांधी

जागरण संवाददाता, जयपुर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा मनमाने ढंग से हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। जयपुर में गांधी विरासत मंच की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में तुषार गांधी ने आरोप लगाया कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते समय किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। यह काम मनमाने ढंग से किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं तो वहां सेना क्यों तैनात की गई। धार्मिक असहिष्णुता के बारे में तुषार गांधी ने कहा कि लोगों को 'जय श्रीराम' कहने पर मजबूर किया जा रहा है। इसमें भक्ति कहां है। उन्होंने कहा कि धार्मिक असहिष्णुता महात्मा गांधी के समय भी थी और इसी के चलते देश का विभाजन भी हुआ, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे।

जनमत मुद्दा

क्या जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा भारत के साथ सही मायने में उसके जुड़ाव के बीच अघोषित रुकावट था?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

43 फीसद की कमी आई है नक्सली हिंसा में छत्तीसगढ़ में 2009-2013 की तुलना में 2014-18 के दौरान। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में देश भर में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर केवल 60 रह गई है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 10 अगस्त 2019

आकार और प्रकार में नहीं कण-कण में हैं भगवान

दलील ▶ रामलला के वकील ने कहा, जन्मस्थान है न्यायिक व्यक्ति

जन्मस्थान को मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने पर शीर्ष अदालत ने पूछा था सवाल

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या की पुकार

रामलला की ओर से शुक्रवार को जन्मस्थान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए कहा गया कि उसके वही अधिकार हैं जो किसी मनुष्य के होते हैं और मुकदमें में वह एक पक्षकार हो सकता है। अपनी दलील साबित करते हुए वरिष्ठ वकील के. परासरन ने कहा कि भगवान कण-कण में हैं। उनका कोई एक निर्धारित आकार-प्रकार नहीं हो सकता। वे मूर्ति में भी हैं और निराकार भी। वह नदी, सरोवर और पहाड़, हर जगह हैं। ईश्वर अणु के हजारवें हिस्से में भी है। दुनिया में खोजे जा रहे सूक्ष्मतम कण को भी गॉड पार्टिकल कहा जाता है। जन्मस्थान को मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने और उसकी कानूनी हैसियत को लेकर कोर्ट की ओर से गुरुवार को पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए परासरन ने शुक्रवार को ये दलीलें दीं।

कोर्ट ने शुक्रवार को रामलला के वकील परासरन से जिज्ञासा भरा सवाल पूछा कि क्या रघुवंश का कोई वंशज अभी अयोध्या में है। परासरन ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वह पता करने का प्रयास करेंगे। सवाल पूछने वाले जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि वह सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या रघुवंश का कोई वंशज है।

परासरन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट पहले भी पहाड़ी को, सरोवर को ज्यूरिस्टिक पर्सन (न्यायिक व्यक्ति) मान चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भगवान का बहुत व्यापक रूप माना गया है। ईश्वर किसी विशेष आकार-प्रकार तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने प्रहलाद की खंभे में भगवान होने की कथा का जिक्र किया। साथ ही कहा भगवान उस मंदिर में भी हो सकता जिसमें कोई मूर्ति न हो। केदारनाथ में भगवान की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है। स्थान को भी भगवान माना जाता है। पुष्कर का ब्रह्म सरोवर है। तिरुवनमलई पहाड़ी है जिसे पवित्र मानकर परिक्रमा की जाती है। चित्रकूट इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां भगवान राम और सीता ने 13 वर्ष गुजारे थे।

साक्ष्य बताते हैं अयोध्या में राम का जन्मस्थान है परिक्रमा मार्ग

कोर्ट ने अयोध्या केस के साक्ष्यों में जन्मस्थान पर परिक्रमा मार्ग का जिक्र होने का हवाला देते हुए परासरन से परिक्रमा का महत्व पूछा। परासरन ने हिंदू धर्म में परिक्रमा का महत्व बताते हुए माता-पिता की परिक्रमा करने की गणेश जी की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का भी हवाला दिया। परासरन ने कहा कि परिक्रमा के मार्ग और स्थान को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन राम जन्मस्थान में ऐसी मुश्किल नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष मानते हैं कि यही स्थान है। उन्होंने भगवान राम के अयोध्या में राजा दशरथ के यहां जन्म लेने के साक्ष्य में वाल्मीकि रामायण के अंश का हवाला दिया। गीता और अन्य शास्त्रों में हिंदू धर्म और पूजा पद्धति के उदाहरण भी गिनाए। साथ में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों के 1954 के यग्नपुरुष दास फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है। बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी।

अयोध्या मामले में अब गोविंदाचार्य ने ऑडियो रिकार्डिंग मांगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसके जरिये उन्होंने राम जन्मभूमि मामले की नियमित सुनवाई की हर दिन की ऑडियो रिकार्डिंग की मांग की है।

गोविंदाचार्य ने शुक्रवार को अपनी लंबित याचिका में एक अंतरिम अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते पांच दिन होने वाली सुनवाई की ऑडियो रिकार्डिंग दिए जाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अदालती कार्यवाही की पूरी ट्रांसस्क्रिप्ट भी मांगी है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है। विगत मंगलवार को उनकी इस मामले की 'लाइव स्ट्रीमिंग' की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उनके वकील की ओर से कहा गया था कि अगर कोर्ट की कार्यवाही के सजीव प्रसारण पर कोई दिक्कत है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। लेकिन अदालत इसके लिए राजी नहीं हुई।

गोविंदाचार्य ने अपनी नई अपील में ऑडियो रिकार्डिंग की मांग करते हुए कहा है कि इसके लिए अदालत में केवल कुछ माइक की जरूरत है। जिसे कुछ चुनिंदा स्थानों पर लगाया जा सकता है। कुछ स्वतः चालित सेवाओं के जरिए ऑडियो क्लिप को न्यूनतम मानव दखल के साथ ट्रांसस्क्रिप्ट में बदला जा सकता है। इसके लिए रजिस्ट्री कोर्ट की फीस का भुगतान भी किया जाना सुरक्षित है।

संजीवनी से कम नहीं है लद्दाख का सोलो पौधा

लद्दाख सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही देश-विदेश में विख्यात नहीं है, बल्कि यहां की कई जड़ी-बूटियां लोगों को स्वस्थ जीवन भी दे रही हैं। इन्हीं में एक है सोलो पौधा। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संबोधन में इस पौधे के विशिष्ट गुणों का जिक्र किया था।

सोलो पौधा फाइल फोटो

औषधीय गुण

इस पौधे का औषधीय इस्तेमाल किया जाता है। यह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सांस की समस्या से परेशान होने वालों को उससे उबरने में मदद करता है। शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। कम ऑक्सीजन के ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात भारतीय सेना के जवान भी इसका इस्तेमाल अपनी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। इस पर शोध भी चल रहा है।

जड़ी बूटियों का खजाना

लद्दाख क्षेत्र में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में बेहद मददगार साबित हो सकती हैं।

सब्जी के रूप में करते हैं इस्तेमाल

सोलो लद्दाख के ठंडे और ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। लद्दाख के स्थानीय लोग इस पौधे के पत्तेदार हिस्सों का इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं।

चल रहा शोध

इसके औषधीय गुणों पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन और लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यड रिसर्च अध्ययन कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पौधा रेडियोएक्टिव प्रभाव से बचाने में भी कारगर है। यही नहीं, यह औषधि डिप्रेशन को कम करने और भूख बढ़ाने में भी लाभकारी है। सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में जवानों में डिप्रेशन और भूख कम लगने की समस्या के इलाज में यह फायदेमंद है। यह पौधा बढ़ती उम्र को रोकने में सहायक है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी के दौरान न्यूरांस की रक्षा भी करता है।

'सोलो' का वैज्ञानिक नाम रहोडियोला है। लद्दाख के लोग इसे 'सोलो' के नाम से जानते हैं। यह ऐसी जगह पर है, जहां पर जिंदगी जीना किसी भी चुनौती से कम नहीं है

- डॉ यशपाल शर्मा, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय

मोदी व शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज

जासं, बागपत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व बागपत के सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह के प्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य ठाकुर प्रदीप सिंह ने इस संबंध में 20 जुलाई को एसपी से शिकायत की थी। प्रदीप के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 28 जून को जम्मू-कश्मीर के संबंध में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर हरीश वीर नामक व्यक्ति ने अशोभनीय टिप्पणी की। आरोपित ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आठ जुलाई को बजट के संबंध में किए गए ट्वीट को भी री-ट्वीट करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 30 जून को किए ट्वीट को री-ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। आरोपित ने बागपत सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह के 30 जून व चार जुलाई के ट्वीट को भी री-ट्वीट करते हुए अश्लील व अपमानजनक टिप्पणी की।

बीस दिन जांच के बाद दर्ज हुआ मुकदमा : एसपी शैलेश कुमार पांडेय ने मामले की जांच कोतवाल उमेश रोरिया को दी। कोतवाल ने जांच करने के बाद शुक्रवार को आरोपित हरीश वीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

अभिनंदन वर्तमान एक पखवाड़े में फिर संभालेंगे मिग-21 की कमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : अपने अदम्य साहस और शौर्य से दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान एक पखवाड़े में मिग-21 लड़ाकू विमान की कमान एक बार फिर संभाल लेंगे। सूत्रों ने बताया कि मेडिकल बोर्ड ने कॉकपिट में उनकी वापसी को हरी झंडी दे दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद वर्तमान को विमान उड़ाने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि विंग कमांडर अगले पखवाड़े में विमान उड़ाते नजर आएंगे।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी शिविर पर भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद 27 फरवरी को पड़ोसी देश के विमानों ने देश की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया था, बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग-21 से पड़ोसी के देश के अत्याधुनिक एफ-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि, इस क्रम में उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया था और वह पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। वहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने निडर होकर पाकिस्तानी अधिकारियों को कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया था। भारत के दबाव में पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। वायुसेना ने उनके लिए वीर चक्र की सिफारिश की है।

मेरठ में फुटपाथ पर पढ़ी गई जुमे की नमाज

जागरण संवाददाता, मेरठ

▶ यातायात सुचारू रखने के लिए एसएसपी ने बनाई व्यवस्था

▶ शहर की प्रमुख मस्जिदों पर पहले से ही तैनात थे पीएसी और आरएएफ के जवान

उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार को जुमे की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी गई। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस ने सड़क पर नमाज न पढ़ने के निर्देश दिए थे। कुछ मस्जिदों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर फुटपाथ पर नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों ने भरोसा दिलाया कि आगे से व्यवस्था में और भी सुधार लाया जाएगा। शहर की प्रमुख मस्जिदों पर पहले से ही पीएसी और आरएएफ लगा दी गई थी।

जुमे के रोज नमाजी सड़क तक फैल जाते थे। इस कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती थी, जिसे लेकर कप्तान अजय साहनी ने नायब शहर काजी जैनुस राशिद्दीन समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर बातचीत की। पुलिस ने जुमे की नमाज मस्जिदों के अंदर पढ़ने के लिए कहा। नायब शहर काजी ने भरोसा दिलाया था कि सड़क पर जुमे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। शर्त रखी कि बकरीद और ईद की नमाज यथावत रहेगी। नमाज के वक्त आरएएफ और पीएसी लगा दी गई थी। सभी थाना प्रभारियों को नमाज सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए थे।

उधर, पहले से ही मस्जिद के सदर ने एलान कर दिया था कि नमाज मस्जिद में ही अदा की जाएगी। इसके बाद नमाजी मस्जिद के अंदर ही प्रवेश करना शुरू हो गए थे। इमलियान, सोतीगंज, छिपी टैंक और जामा मस्जिद में अंदर ही नमाज अदा की गई। भीड़ बढ़ने पर मस्जिद की छतों एवं फुटपाथ तक नमाजी बैठ गए थे। नौचंदी के पटेल मंडप की मस्जिद में नमाजी सड़क तक आ गए थे। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मस्जिद के सदर ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि आने वाले जुमे की व्यवस्था सही कर ली जाएगी।

इमलियान मस्जिद में जगह कम पड़ने पर फुटपाथ पर नमाज पढ़ते अकीदतमंद। इस दौरान हापुड़ रोड अबाध चलता रहा। अब तक जुमा की नमाज के दौरान एक ओर का ट्रैफिक रोकना पड़ता था। जागरण

शहर में सभी मस्जिदों में नमाज सड़क को छोड़कर अदा की गई। मुस्लिम समाज के सहयोग के कारण नमाज के समय यातायात बाधित नहीं हुआ। अगले जुमे के रोज व्यवस्था में और सुधार होने की उम्मीद है।

- अजय साहनी, एसएसपी, मेरठ

'बकरीद पर गाय और संरक्षित श्रेणी के पशुओं की कुर्बानी न करें'

जागरण संवाददाता, देवबंद : इस्लामी तालीम के विश्व विख्यात केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने ईदुलजुहा पर्व (बकरीद) पर गाय की कुर्बानी न करने की अपील की है। दारुल उलूम ने साफ कहा कि उन पशुओं की कुर्बानी न करें, जिससे हमवतन भाइयों की भावनाएं आहत होती हों। शुक्रवार को दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी की गई पुस्तिका में कुर्बानी के मसाइल बयान किए गए। पुस्तिका में कहा गया है कि गोवंश समेत संरक्षित श्रेणी के पशुओं की कुर्बानी न की जाए।

दारुल उलूम के तंजीम व तरक्की विभाग के प्रभारी मौलाना राशिद ने संस्था द्वारा जारी अपील के संबंध में बताया। उन्होंने कुर्बानी के अवशेषों को सड़क पर न फेंकने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने की अपील की। देवबंदी उलमा ने भी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न किए जाने की अपील मुस्लिम समाज से की है। उनका कहना है कि इससे समाज में बेहतर माहौल बनेगा।

देश के छह निजी विवि से पढ़े शिक्षकों पर विजिलेंस की नजर

दीनानाथ साहनी, पटना

▶ इन विश्वविद्यालयों के नाम पर बने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पा गए 146 शिक्षक

बिहार में शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े की विजिलेंस जांच की आंच अब देश के छह निजी विश्वविद्यालयों तक पहुंच गई है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू, श्री श्री यूनिवर्सिटी, कटक ओडिशा, कोलोर्क्स टीचर्स यूनिवर्सिटी गुजरात, नार्थ फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश, मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़, उत्तर प्रदेश तथा जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, राजस्थान के नाम से निर्गत प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वाले 146 शिक्षकों पर विजिलेंस टीम की नजर है। जांच में ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को संदिग्ध पाया गया है। इसकी रिपोर्ट विजिलेंस टीम ने शिक्षा विभाग को सौंपी है।

ऐसे हुआ मामला उजागर : विजिलेंस टीम ने जांच के क्रम में निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रमाण पत्रों के बारे में संबंधित नियोजन इकाईयों एवं शिक्षकों से पूछताछ की तो वे उन विश्वविद्यालयों के नाम भी ठीक से नहीं बता सके। निजी विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने वाले जालसाज भी विजिलेंस टीम के रडार पर हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू, श्री श्री यूनिवर्सिटी, कटक (ओडिशा) और कोलोर्क्स टीचर्स यूनिवर्सिटी गुजरात ने अपने यहां से निर्गत प्रमाणपत्रों को जाली करार दिया है। नवादा के एक शिक्षक रामानुज शर्मा का स्नातक का अंकपत्र ही फर्जी पाया गया है। इन्होंने श्री श्री यूनिवर्सिटी, कटक से बीए करने का दावा किया था। वैसे इन विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करने वाले शिक्षकों की सूची मिलने के बाद विजिलेंस टीम इनके प्रमाण पत्रों की और गहराई से जांच में जुटी है।

2756 शिक्षकों के प्रमाण पत्र भी जांच के घेरे में

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम ने झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम और राजस्थान जैसे राज्यों के करीब छह दर्जन निजी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त 2756 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को जांच में संदिग्ध पाया है। हालांकि इसका सत्यापन संबंधित राज्यों के शिक्षण संस्थानों से कराया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के एक पदाधिकारी के मुताबिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ऐसे शिक्षकों की बर्खास्तगी तय है क्योंकि इस मामले की जांच की मॉनीटरिंग कर रहे पटना हाई कोर्ट पहले से ही सख्त रुख अख्यितार किए हुए है।

आइआरसीटीसी ई-टिकट पर लगाएगा सर्विस चार्ज, महंगा होगा रेल सफर

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइआरसीटीसी के माध्यम से खरीदा गया ई-टिकट अब महंगा हो जाएगा। दरअसल, रेलवे ने करीब तीन साल बाद एक बार फिर से ई-टिकटों पर सर्विस चार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। तीन साल पहले नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे हटा लिया गया था।

रेलवे बोर्ड ने भी भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तीन अगस्त को जारी एक पत्र में बोर्ड ने कहा है कि रेलवे की खानपान एवं पर्यटन इकाई आइआरसीटीसी ने ई-टिकटों पर सर्विस चार्ज की व्यवस्था की पुनर्बहाली के लिए मामलों का विस्तृत अध्ययन किया, जिसका सक्षम प्राधिकार ने परीक्षण भी किया है।

▶ रेलवे बोर्ड व वित्त मंत्रालय ने तीन साल बाद व्यवस्था को दोबारा लागू करने के लिए दी हरी झंडी

▶ आइआरसीटीसी ने व्यवस्था की पुनर्बहाली के लिए मामलों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद रखा था प्रस्ताव

एसी टिकट पर 40 व बिना एसी पर 20 रुपये लगता था सर्विस चार्ज

अधिकारियों ने बताया कि सर्विस चार्ज हटाए जाने के बाद आइआरसीटीसी को वित्तीय वर्ष 2016-17 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के राजस्व में 26 फीसद की गिरावट का सामना करना पड़ा था। आइआरसीटीसी प्रत्येक एसी टिकट पर 40 रुपये व बिना एसी वाले ई-टिकट पर 20 रुपये सर्विस चार्ज लेता था। हालांकि, अब आइआरसीटीसी को निर्णय लेना है कि वह पहले वाला सर्विस चार्ज लेगा या इसमें बढ़ोतरी करेगा।

पत्र में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय भी सर्विस चार्ज को फिर से लागू करने के पक्ष में है। उसका कहना है कि सर्विस चार्ज माफ करने की योजना अस्थायी थी। रेलवे मंत्रालय ई-टिकट पर सर्विस चार्ज फिर से लागू कर सकता है। पत्र के अनुसार, 'वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुरूप सक्षम प्राधिकार ने निर्णय लिया है कि ई-टिकटों पर सर्विस चार्ज लगाने के लिए आइआरसीटीसी उचित फैसला ले सकता है।'

बास्केटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी को शौहर ने दिया एक साथ तीन तलाक

जागरण संवाददाता, अमरोहा : तीन साल से दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लड़ रहीं बास्केटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमायला जावेद को तारीख पर आए पति ने कचहरी परिसर में तत्काल तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने सीओ सदर को पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।

बिजनौर निवासी शुमायला जावेद की शादी फरवरी 2014 को लखनऊ निवासी मुहम्मद फारूख के साथ हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है। शुमायला का आरोप है कि 2016 में उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। वह बेटी के साथ मायके में रहने लगीं। शुमायला ने पति और ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा अमरोहा जिला न्यायालय में विचाराधीन है। शुक्रवार को मुकदमे की तारीख थी। दोनों ही अदालत आए थे। यहीं मारपीट करने के बाद फारूख ने उन्हें एक साथ तीन तलाक बोल दिया।

18 गवाहों को मुहैया कराई गई सुरक्षा

उन्नाव दुष्कर्म मामला

जागरण संवाददाता, उन्नाव

▶ दुष्कर्म पीड़िता के पिता का इलाज व पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी मिलेगी सुरक्षा

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और घायल वकील के परिवार के साथ केस की पैरवी करने वाले अन्य वकीलों को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने के बाद अब गवाहों को भी सुरक्षा मिलेगी। सीबीआइ द्वारा गवाह बनाए गए 18 लोगों की सुरक्षा को लेकर उप्र शासन ने शुक्रवार को सभी को गनर देने का आदेश जारी कर दिया।

मामले में सीबीआइ ने 18 स्वतंत्र गवाह बनाए हैं। अभी तक इनकी सुरक्षा को लेकर कोई पहल नहीं की गई थी। रायबरेली में हुए कार हादसे के बाद सर्वोच्च न्यायालय के कड़े रुख पर दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार व तीन वकीलों की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगाई गई है। एसपी एमपी वर्मा ने बताया कि 18 गवाहों को गनर दिया जा रहा है।

दुष्कर्म पीड़िता के पिता का इलाज करने से लेकर पोस्टमार्टम तक में शामिल रहे डॉक्टर भी हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए शासन के निर्देश पर गुरुवार को ही अंडर सीएमओ और जिला अस्पताल के डॉक्टरों की सूची के साथ उनकी एलआइयू जांच करा रिपोर्ट भेजी गई है।

चाचा की तिहाड़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी : दुष्कर्म पीड़िता के तिहाड़ जेल में बंद चाचा पर दर्ज दोनों मुकदमों की कोर्ट में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। सुरक्षा कारणों से उन्हें यहां नहीं लाया गया। चाचा पर दर्ज पांच में से चार मामलों की अगली सुनवाई अब 19 अगस्त को होगी। शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के खिलाफ जीआरपी थाने में दर्ज लूट व माल बरामदगी मामले में 12वें व अंतिम गवाह के बयान हुए।

कोर्ट ने चाचा के बयान के लिए 19 अगस्त की तारीख नियत की है। वहीं जीआरपी में ही दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में भी अदालत उसी रोज सुनवाई करेगी। इसके साथ, माखी थाने में दर्ज झूठी सूचना देने और फर्जी टीसी मामले में भी 19 अगस्त की ही तारीख लगाई गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर आरोपित को हाजिर करने का भी आदेश दिया है।

यह है मामला

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

आरोप है कि नौकरी देने का वादा करके कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने आवास पर 4 जून 2017 को किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब पीड़िता और उनकी मां ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। पीड़िता के पिता के खिलाफ 3 अप्रैल 2018 को शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। 28 जुलाई को रायबरेली में पीड़िता, उनकी चाची, मौसी व वकील की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसमें चाची व मौसी की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता व उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लखनऊ से दिल्ली लाकर एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तीस हजारी अदालत में स्थानांतरित करते हुए 45 दिनों में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है।

धमकियों से वाकिफ थी सीबीआइ

जागरण संवाददाता, उन्नाव

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां और चाची द्वारा लिखा गया पत्र रायबरेली कार हादसे के पांच दिन पूर्व सीबीआइ को मिल चुका था। पत्र के जरिये सीबीआइ पीड़िता के परिवार को मिल रही धमकियों से वाकिफ हो गई थी। वहीं 12 जुलाई को लिखे गए इस पत्र पर पुलिस अधीक्षक ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामला संज्ञान में लेने के बाद 31 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया। अगर यही तेजी पहले दिखाई गई होती शायद कार हादसे को टाला जा सकता था।

दुष्कर्म कांड की पीड़िता, उसकी मां तथा गवाहों को विधायक के गुर्गों और परिजनों से लगातार धमकियां मिल रही थीं। इसी से भयभीत हो दुष्कर्म पीड़िता की मां, चाची और बहन ने शिकायती पत्र भेजा, जिसमें आरोप लगाया था कि सात जुलाई को विधायक के भाई मनोज सिंह और जेल में बंद सहआरोपित शशि सिंह के बेटे ने अपने साथियों के साथ दरवाजे पर चढ़कर पीड़िता की बहन, मां और चाची को गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दूसरे दिन शशि सिंह के पति हरपाल सिंह ने धमकाया। पीड़िता की मां, चाची और बहन ने 12 जुलाई को एसपी उन्नाव, सीबीआइ और हाई कोर्ट को शिकायती पत्र भेज कार्रवाई कराने की गुहार लगाई थी। सीबीआइ को यह पत्र 23 जुलाई को मिल गया था।

पीड़िता के परिजनों को सुविधा उपलब्ध कराए एम्स : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एम्स में भर्ती उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध कराए। सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने एम्स के विश्राम सदन की गवर्निंग बॉडी से कहा कि पीड़िता के परिजनों को कम से कम दो कमरे और एक दिन में तीन बार भोजन उपलब्ध कराएं। इसका खर्च मामले की जांच कर रही सीबीआइ को मिलने वाली प्रतिपूर्ति से लिया जाए। इस आदेश का सख्ती से और तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए। ऐसा नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

खौफ

उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर से डरे इनामी बदमाश ने थाने में किया आत्मसमर्पण, पिछले सात महीने में 70 से अधिक बदमाशों को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है

'साहब! मुझे लंगड़ा नहीं होना, जेल भेज दो'

जागरण संवाददाता, कानपुर

उत्तर प्रदेश में बदमाशों और उनके परिजनों में पुलिस के 'हाफ एनकाउंटर' का खौफ नजर आने लगा है। सात महीने में 70 से अधिक बदमाशों के पैर में गोली मारकर पकड़ने (हाफ एनकाउंटर) और 100 से अधिक बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद परिवार के लोग ही वांछित बदमाशों को थाने में आत्मसमर्पण करा रहे हैं। इसकी बानगी शुक्रवार को कानपुर के बिधनू थाने में तब दिखी, जब 25 हजार के इनामी लुटेरे को लेकर उसके पिता परिवार के अन्य सदस्यों, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के साथ पहुंचे और उसका आत्मसमर्पण कराया। लुटेरे ने थानेदार से कहा, 'साहब! मुझे लंगड़ा नहीं होना, जेल भेज दो।'

शातिर लुटेरा नारायण उर्फ लाला बिधनू में स्कूटी लूट में वांछित था। उसने एक सप्ताह पहले शहर के टॉप टेन अपराधियों में शामिल धर्मेंद्र उर्फ पट्टू और राहुल उर्फ शेरा के साथ मिलकर स्कूटी लूटी थी। दो अगस्त को तीनों फिर लूट के इरादे से किसान नगर से बिधनू नहर की ओर आ रहे थे, तभी पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। पट्टू के पैर में गोली लगी थी, जबकि शेरा और लाला फरार हो गए थे। एसएसपी अनंतदेव ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा। इसके बाद बिधनू पुलिस शेरा और लाला की गिरफ्तारी के लिए लगातार रिश्तेदारों के घर तक दबिश देने लगी। चार अगस्त को बिधनू पुलिस ने मझावन चौकी के टिकरिया मोड़ के पास घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों साथियों की गिरफ्तारी के बाद लाला के लिए पड़ रही दबिश से परिजन दहशत में थे। पिता छोटे सिंह उर्फ बाबा उसे तलाश कर गुरुवार को घर ले आए। फिर शुक्रवार को आत्मसमर्पण करा दिया।

उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोली से बचने के लिए इनामी बदमाश नारायण ने कानपुर के बिधनू थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। जागरण

▶ ग्राम प्रधान और परिजनों संग थाने पहुंचा 25 हजार का इनामी

▶ दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद दहशत में था शातिर अपराधी

▶ पुलिस की कार्रवाई से उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले है पस्त

किसी भी अपराधी को न छोड़ने के कारण बदमाशों में पुलिस का खौफ बढ़ रहा है। शुक्रवार को परिजनों ने शातिर लाला का थाने में आत्मसमर्पण कराया।

-अनुराग सिंह, थाना प्रभारी, बिधनू

महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बाढ़ का कहर

बढ़ीं मुसीबतें ▶ राहत और बचाव में जुटीं एनडीआरएफ की टीमें, केरल में बाढ़ से कोच्चि एयरपोर्ट रविवार तक बंद

अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान, लाखों लोग हुए हैं प्रभावित

जेएनएन, नई दिल्ली

महाराष्ट्र और गुजरात समेत दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। इन राज्यों में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। केरल में कोच्चि एयरपोर्ट को सुरक्षा कारणों से रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ समेत सेना के तीनों अंगों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों के हालात पर नजर रखे हुए है। पीड़ित राज्यों को केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने यहां शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में इन राज्यों में बाढ़ से पैदा हुए हालात की समीक्षा की। मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ प्रभावित महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गुजरात के लिए नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) की 83 और टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। एक टीम में 45 सदस्य होते हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित राज्यों में सेना, नौसेना, वायु सेना और कोस्ट गार्ड की 173 टीमें पहले से ही तैनात की गई हैं।

मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने बताया कि पिछले दो दिनों में महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में मूसलधार बारिश होने से हालात और खराब हुए हैं। विभाग ने अगले चौबीस घंटों में इन राज्यों के साथ ही गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रभावित राज्यों में अब तक लगभग एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे ढाई हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 30 पहुंच गई है। राज्य के सांगली जिले में बाढ़ से घिरे लोगों तक हेलीकॉप्टर की मदद से खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। केरल में अब तक 22 लोगों की जान गई है। 22 हजार लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भारी बारिश से पांच लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों को राहत देने के लिए कर्नाटक ने अलमाटी बांध से अब तक साढ़े चार लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है।

महाराष्ट्र के सांगली में मूसलधार बारिश के बाद बाढ़ से बुरा हाल है। आलम यह है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना को भी लगाया गया है (बाएं)। वहीं, केरल में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ ने विकराल स्थिति पैदा कर दी है। यहां के कोच्चि स्थित एयरपोर्ट के रनवे एरिया में भी पानी भर गया है। ऐसे में कोच्चि एयरपोर्ट को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। (दाएं) एएफपी/प्रेट्र

येदियुरप्पा बोले-केंद्र सरकार ने मदद का भरोसा दिलाया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बारिश और बाढ़ से खराब होते हालात से निपटने के लिए केंद्र ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को राज्य के हालात की जानकारी दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से मदद का किया वादा

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल के बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड समेत केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात को लेकर प्रधानमंत्री से बात की थी और मदद की मांग की थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री ने आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी तरह की सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है।' कांग्रेस नेता ने गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से भी बात की थी और बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया था।

गुजरात ने बांध के फाटक खोले

गुजरात ने नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के 30 में से 26 फाटकों को खोल दिया है। ऐसा बांध में ज्यादा पानी आने के चलते किया गया है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे।

खेती को होने वाले नुकसान पर सरकार की नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मानसून की झमाझम बारिश से कई राज्यों में भीषण बाढ़ के हालात हैं। इससे खेती को होने वाले नुकसान पर सरकार नजर रख रही है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की रोपाई पीछे चल रही है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि मानसून की सक्रियता को देखते हुए धान का रकबा कम नहीं होगा।

तोमर शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसून की भारी बारिश के चलते दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्र के कई राज्यों में आई बाढ़ से खेती को नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। सरकार प्राकृतिक आपदाओं से खेती को होने वाले नुकसान पर नजर रख रही है। तोमर ने माना कि चालू सीजन में मानसून विलंब से आया जिससे बुआई प्रभावित हुई है। यह किसानों के साथ सरकार की भी चिंता का विषय थी। लेकिन मानसून के सक्रिय होते ही खेती का रकबा लगातार संतोषजनक गति से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल औसत बारिश 2.5 फीसद कम रह गई है जो पूरी हो जाएगी।

मालूम हो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मानसून के देर से आने और फिर बाढ़ के चलते खरीफ बुआई और रोपाई का रकबा 50 लाख हेक्टेयर तक पीछे चल रहा है। जबकि इसमें धान की रोपाई लगभग 40 लाख हेक्टेयर पिछड़ गई है। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज वाली फसलों का बुआई रकबा घटा है।

कई राज्यों में खरीफ की फसल बाढ़ में डूब गई है जिससे वहां नुकसान की भरपाई के लिए कृषि मंत्रालय ने योजना तैयार करनी शुरू कर दी है। राज्यों की ओर से सूचना मिलते ही टीमें नुकसान का आकलन करेंगी और वैकल्पिक खेती की योजना का खाका पेश किया जाएगा। बिहार और असम के ज्यादातर जिलों में बाढ़ के पानी से फसलों की क्षति हुई है। इसका आकलन करने के लिए जल्द ही केंद्रीय टीम रवाना होगी।

हालात का जायजा लेने पहुंचे मंत्री सेल्फी लेते नजर आए

कोल्हापुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन बाढ़ का जायजा लेते वक्त सेल्फी लेने पर विवादों में आ गए हैं। सांगली जिले में गुरुवार को बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे महाजन मोटरबोट पर सेल्फी में हंसते और हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। मंत्री के इस व्यवहार पर विपक्षी दलों ने निशाना साधने में देर नहीं की। सेल्फी का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाजन की आलोचना की। जवाब में महाजन ने इन दलों से बाढ़ के राहत कार्यों को लेकर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। राकांपा ने कहा कि ऐसा लगता है भाजपा के मंत्री बाढ़ से पैदा हुए हालात का जायजा लेने नहीं, बल्कि 'आपदा पर्यटन' पर निकले थे। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से महाजन के इस्तीफा लेने की मांग की है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में बाढ़ से हालात खराब हैं और मुख्यमंत्री और मंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं।

जल्द ही गंगा के नीचे दौड़ेगी देश की पहली 'अंडर वॉटर ट्रेन'

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ 16 किमी लंबी ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना के बारे में रेल मंत्री ने किया एलान

बंगाल के कोलकाता में देश का पहला अंडर वॉटर ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। इसके पूरा होते ही यहां जल्द मेट्रो संचालित होगी। यह एलान केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के जरिये किया है।

गोयल ने हिंदी में ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, भारत की पहली अंडर वॉटर ट्रेन शीघ्र ही कोलकाता में हुगली (गंगा) नदी के नीचे चलना शुरू होगी। उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण यह ट्रेन देश में निरंतर हो रही रेलवे की प्रगति का प्रतीक है। इसके संचालन से कोलकाता निवासियों को सुविधा, और देश को गर्व का अनुभव होगा।

कोलकाता मेट्रो की यह 16 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट मेट्रो ट्रेन सेवा सॉल्टलेक सेक्टर-5 को हावड़ा मैदान के साथ जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट का फेज वन जो सेक्टर-5 को सॉल्टलेक स्टेडियम से जोड़ता है, जल्द ही शुरू हो जाएगा। जिस सुरंग से होकर यह मेट्रो

पीयूष गोयल फाइल फोटो

गुजरेगी, उसे चार स्तरीय सुरक्षा कवच हुगली के पानी से बचाएगा।

इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी है, जिसमें इस परियोजना की खासियतों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार, इसमें अप और डाउन लाइन की दो सुरंगें होंगी। यह लाइन दो फेज में बंटी है। इस ट्रेन की शुरुआत कोलकाता वासियों के लिए राहत भरा कदम है। इससे उन्हें यातायात के लिए नया साधन मिलेगी।

असम में दुर्घटनाग्रस्त सुखोई-30 मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

नई दिल्ली, एएनआइ: भारतीय वायुसेना ने गुरुवार रात असम के तेजपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुए सुखोई-30एमकेआइ एयरक्राफ्ट मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। बता दें कि तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा होने की बात कही जा रही है।

भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार आठ अगस्त की रात को ट्रेनिंग मिशन 01 के दौरान तकनीकी खराबी के चलते सुखोई-30एमकेआइ एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट समय रहते सुरक्षित निकल गए। दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। गुरुवार को दिए गए बयान में वायुसेना ने कहा था कि आज शाम असम के तेजपुर से सुखोई-30 एयरक्राफ्ट अपने नियमित ट्रेनिंग मिशन पर गया था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट विमान से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हादसे का कारणों का पता लगाएगी।

आयुष्मान व विक्की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कीर्ति सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना तथा विक्की कौशल क्रमशः 'अंधाधुन' और 'उरी' फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किए गए हैं। तेलुगु फिल्म 'महानती' के लिए कीर्ति सुरेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। गुजराती फिल्म 'हेल्लारो' सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है।

करीब दो महीने की देरी से शुक्रवार को घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बॉलीवुड बड़ा विजेता बनकर उभरा। इन पुरस्कारों की घोषणा मई में होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण यह टल गई थी। 23 गैर फीचर फिल्मों और 31 फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार दिए गए हैं।

आदित्य धर ने फिल्म 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए बेस्ट डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपने पुरस्कार को देश के बहादुर सैनिकों को समर्पित किया है।

फिल्म 'अंधाधुन' ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तथा बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीनप्ले का भी पुरस्कार हासिल किया है। संजय लीला भंसाली की विवादित रही फिल्म 'पद्मावत' को 'घूमर' के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है। इसके गाने 'बिंते दिल' के लिए अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक का पुरस्कार मिला है।

66 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, गुजराती 'हेल्लारो' सर्वश्रेष्ठ फिल्म

23 गैर फीचर फिल्मों और 31 फीचर फिल्म की श्रेणी में दिए गए अवार्ड

आयुष्मान खुराना

विक्की कौशल

कीर्ति सुरेश सभी फाइल फोटो

गायक-गीतकार स्वानंद किरकिरे को मराठी फिल्म 'चुंबक' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। किरकिरे ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की थी। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार 'बधाई हो' को दिया गया है। अक्षय कुमार स्टारर 'पैडमैन' को सामाजिक विषयों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। राहुल रवेल की अध्यक्षता वाली जूरी ने पुरस्कारों की घोषणा की। लेकिन ये पुरस्कार कब दिए जाएंगे इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हर साल पुरस्कार वितरण समारोह तीन मई को होता है।

उत्तराखंड को मिला 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट' का अवार्ड : राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेस यानी फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू करने के लिए दिया गया है। पिछले एक साल के दौरान राज्य में 150 से अधिक फिल्मों, धारावाहिक, डाक्यूमेंट्री आदि की शूटिंग की गई है। इनमें मीटर चालू, बत्ती गुल, परमाणु, बाटला हाउस, कबीर, केदारनाथ जैसी फिल्में शामिल हैं।

बटला हाउस फिल्म से जुड़ी याचिका पर विचार करने से हाई कोर्ट का इन्कार

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बटला हाउस एनकाउंटर घटनाक्रम पर बनी फिल्म बटला हाउस को रिलीज करने से रोके जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आपने फिल्म नहीं देखी तो फिर कैसे तय किया कि इसमें कुछ अप्रिय है। पीठ का रुख देख अरिज खान व शहजाद अहमद ने याचिका वापस ले ली। गुरुवार को न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर पाया गया कि फिल्म का प्रभाव 2008 से जुड़े सीरियल ब्लास्ट और एनकाउंटर से जुड़े मुकदमे पर पड़ेगा, तो इसके रिलीज पर रोक लगा दी जाएगी। अरिज खान व शाहजाद ने याचिका में कहा कि फिल्म पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे केस के ट्रायल पर असर पड़ेगा। अरिज के खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है। सितंबर 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर पर बनी फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज की जानी है। इसमें अभिनेता जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में हैं।

ध्वनि प्रदूषण रोकने में लापरवाही पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

राज्य ब्यूरो, रांची

▶ कोर्ट के कई निर्देश के बावजूद नहीं जारी हुई अधिसूचना

▶ कोर्ट के पास तेज लाउडस्पीकर बजने पर लिया है संज्ञान

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की पीठ ने रांची में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए अधिसूचना जारी नहीं किए जाने पर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अदालत सात माह से इस मामले की मॉनीटरिंग कर रही है। इस दौरान ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई निर्देश दिए, लेकिन सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी नहीं हो सकी है। अदालत ने अधिसूचना जारी कर 13 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया।

मालूम हो कि हाई कोर्ट के पास तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रांची के एसएसपी, एसडीओ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव हाई कोर्ट में उपस्थित हुए थे। इस दौरान अदालत ने पूछा कि आदेश देने के बाद भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की अधिसूचना जारी क्यों नहीं हुई? इस पर बोर्ड के सचिव ने कहा कि इसके लिए वह सक्षम पदाधिकारी नहीं हैं। राज्य सरकार के स्तर से ही इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव को रांची उपायुक्त ने दो बार पत्र लिखा है। इसके बाद अदालत ने कहा कि यह अवमानना का मामला है और अधिकारी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कोर्ट के आदेश को हल्के में न लें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अदालत ने कहा कि एसडीओ को एक आदेश निर्गत करना चाहिए कि रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाए।

दरअसल, हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर इन अधिकारियों से कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बनाए गए कानून के अनुसार अधिसूचना जारी करें। लेकिन रांची जिला प्रशासन ने इसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है।

दाभोलकर मामले में विदेशी एजेंसी करेगी हथियार की तलाश : सीबीआइ

मुंबई, प्रेट्र : वामपंथी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच कर रही सीबीआइ ने बांबे हाई कोर्ट को बताया है कि वह हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश के लिए एक विदेशी एजेंसी की मदद ले रही है।

सीबीआइ के वकील और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने शुक्रवार को जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जीएस पटेल की खंडपीठ को बताया कि इस एजेंसी के विशेषज्ञ रविवार को भारत पहुंच रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तीस दिन लगेंगे। सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि ऐसी आशंका है कि आरोपितों ने हत्या के बाद हथियारों को ठाणे क्रीक में छिपा दिया है।

खंडपीठ दाभोलकर और दिवंगत वामपंथी नेता गोविंद पनसारे की हत्या के संबंध में उनके रिश्तेदारों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में दोनों मामलों की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की अपील की गई है। पनसारे मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र सरकार के विशेष जांच दल (एसआइटी) ने हाई कोर्ट को बताया कि उसके अधिकारी कोल्हापुर में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कोर्ट नहीं पहुंच पाए हैं। लिहाजा, हाई कोर्ट ने सुनवाई आगामी 16 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।

छत्तीसगढ़ समेत 13 सेंचुरी को बतौर ईएसजेड मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व समेत 13 वन्य जीव अभयारण्यों (वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज) को ईको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) घोषित कर दिया है ताकि पारिस्थितिकीय तंत्र (इकोसिस्टम) का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जा सके।

सोशल मीडिया पर शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तमिलनाडु में 11 और छत्तीसगढ़ में एक सेंचुरी को ईको-सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अंतिम अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।

मंत्रालय के अनुसार भारत में 651 संरक्षित क्षेत्रों में से 316 अंतिम ईएसजेड अधिसूचना से संरक्षित हैं। इस अधिसूचना से संरक्षित क्षेत्रों से लगे एक किलोमीटर के दायरे में खनन, पत्थरों के उत्खनन और पत्थर काटना आदि पर प्रतिबंध लग जाएगा। ईएसजे अधिसूचना को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत लागू किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने एक साथ कई ट्वीट जारी कर इस अधिसूचना के दायरे में आने वाली सभी सेंचुरी के नामों की घोषणा कर दी है। मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संबंध में भी अधिसूचना जारी करके उसे अंतिम ईएसजेड के दायरे में ला दिया है। तमिलनाडु की 11 सेंचुरी के नाम हैं :- वाडुवूर बर्ड सेंचुरी, कंजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी, श्रीविल्लीपुतर ग्रिजिल्ड स्कैवरल सेंचुरी, मेगामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, वेट्टनगुडी बर्ड सेंचुरी, कोडाईकनाल वाइल्डलाइफ सेंचुरी, सक्करकोट्टाई बर्ड सेंचुरी, वल्लानाडु ब्लैकबक सेंचुरी, ओउस्सुडु लेक बर्ड सेंचुरी और प्वाइंट क्लेमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अचानकमर टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के तुंगरेश्वर वाइल्डलाइफ सेंचुरी को भी ईएसजेड के तहत मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि अंतिम ईको-सेंसिटिव जोन की वैज्ञानिक सरहदबंदी और दस किलोमीटर तक संरक्षित क्षेत्रों से किसानों, ग्रामीणों और छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी।

एयर इंडिया झुकी, दिल्ली-खजुराहो के बीच शुरू होगी प्रतिदिन उड़ान

नईदुनिया, खजुराहो : मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो लगातार तीसरे दिन भी बंद रही। शुक्रवार को भी आंदोलनकारियों ने दुकानें नहीं खोलीं। वहीं, एयर इंडिया ने कहा है कि 28 अक्टूबर से प्रतिदिन एक उड़ान दिल्ली से खजुराहो पहुंचेगी। वापसी में यह उड़ान वाराणसी होकर दिल्ली आएगी। एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने जारी बयान में यह जानकारी दी।

उधर, लगातार हड़ताल व शहर बंद रहने का सीधा असर पर्यटकों पर पड़ा। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। खजुराहो घूमने आए देशी-विदेशी सैलानियों को होटल से मंदिरों तक जाने के लिए न तो ऑटो मिल सके और न ही रास्ते में खाने-पीने की कोई सुविधा। पर्यटन विभाग के रीजनल मैनेजर एमके समाधिया भी गुरुवार को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अभी सप्ताह में तीन दिन चल रही एयर इंडिया की फ्लाइट को 28 अक्टूबर से नियमित करने का निर्णय लिया जा रहा है। इस सूचना को आंदोलनकारियों ने जब लिखित में मांगा तो उन्होंने तीन-चार दिन में लिखित सूचना देने का आश्वासन दिया।

नेशनल पार्क की शान बढ़ा रहा कस्तूरी मृग

बढ़ा रहे शोभा

हिम तेंदुओं की संख्या का पता लगाने के लिए पार्क में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ कस्तूरी मृग, पार्क में तीन साल बाद देखा गया है

मुकेश मेहरा, कुल्लू

शर्मिला पशु यानी कस्तूरी मृग भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की शोभा बढ़ा रहा है। वन्य प्राणी विंग की ओर से हिम तेंदुओं की संख्या का पता लगाने के लिए पार्क में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में कस्तूरी मृग भी कैद हुआ है। पार्क में कस्तूरी मृग तीन साल बाद देखा गया है। हिरण प्रजाति से संबंधित कस्तूरी मृग शर्मिला जानवर माना जाता है और आसानी से सामने नहीं आता है। वन्य प्राणी विंग इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहा है।

कस्तूरी मृग आमतौर पर 2400 से 3600 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका शरीर 20 से 30 इंच ऊंचा होता है। नाक से लेकर पीठ तक 750 से 950 मिलीमीटर लंबा होता है। इसकी पूंछ पर बाल नहीं होते हैं। हालांकि मादा मृग की पूंछ घने वालों वाली होती है। पिछली टांगें अगली टांगों से लंबी होती हैं। अपने फुर्तीले स्वभाव के कारण यह ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रहता और हल्की सी आहट पर भी एकदम गायब हो जाता है।

ग्रेट हिमालयन नेशनल में सीसीटीवी कैमरा में ट्रैप हुआ कस्तूरी मृग

बर्फानी तेंदुओं की संख्या जानने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में कस्तूरी मृग की फुटेज सामने आई है। यह दो तीन साल बाद यहां देखा गया है। आमतौर पर यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही रहता है। यह जानवर अधिक देर तक एक जगह पर नहीं टिकता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इनकी संख्या कितनी है इसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी।
-अजीत ठाकुर, अरण्यपालप वाइल्ट लाइफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के सीसीटीवी कैमरों में कस्तूरी मृग के पाए जाने के बाद अब वन्य प्राणी विंग की टीम अन्य कैमरों की फुटेज भी जांचेगी। पार्क में विभिन्न स्थानों पर 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से अभी तक चार से पांच कैमरों को ही खंगाला गया है। इसमें बर्फानी तेंदुआ और कस्तूरी मृग की फुटेज सामने आई है।

कस्तूरी के लिए होता है शिकार : कस्तूरी मृग की कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए शिकारी इसे निशाना बनाते हैं। इसका शिकार प्रतिबंधित है। इसके बाद कृत्रिम कस्तूरी का प्रयोग ही इत्रों में होता है। कस्तूरी मृग भारत, नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन व साइबेरिया आदि देशों में पाया जाता है।

इजरायली मिसाइल स्पाइडर का पोखरण में हुआ परीक्षण

जासं, जयपुर : राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज एक बार फिर मिसाइल के सफल परीक्षण की साक्षी बनी है। शुक्रवार को यहां इजरायली मिसाइल स्पाइडर का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 15 किलोमीटर दूर से हवा में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है।

भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को और अधिक स्मार्ट बनाने की कवायद के तहत इजरायली मिसाइल स्पाइडर का परीक्षण किया गया है। सैन्य सूत्रों के अनुसार यह क्विक रिएक्शन करने के साथ ही सतह से आकाश में (सरफेस टू एयर) मार करने वाली मिसाइल है। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना और इजरायली विशेषज्ञों की मौजूदगी में जमीन से आकाश में सटीक निशाना दागने के साथ ही इसकी मारक क्षमता को आंका गया। सूत्र बताते हैं कि इसी तरह की एक मिसाइल का पहले भी परीक्षण किया जा चुका है। भारत इस मिसाइल को पश्चिमी सीमा पर तैनात करने की योजना बना रहा है।

रुबिया अपहरण व वायुसेना अफसरों की हत्या मामले में वारंट जारी

जेएनएफ, जम्मू : जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण और एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या मामले में टाडा कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के तत्कालीन प्रमुख अमानुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया है।

कोर्ट ने जेकेएलएफ चेयरमैन यासीन मलिक को भी पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन सीबीआइ ने समय की कमी के चलते मलिक को पेश करने में असमर्थता जताई। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान मलिक को पेश करने का निर्देश दिया। टाडा कोर्ट ने एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या मामले में जेकेएलएफ प्रमुख अमानुल्लाह खान के अलावा जावेद मीर, डॉ. गुलाम कादिर और अब्दुल रहमान के खिलाफ हिरासती वारंट जारी किया है। वहीं, रुबिया सईद के अपहरण मामले में रियाज भट्ट, खुर्शीद अहमद डार, बशारत उर्फ बिट्टा कराटे, तारीक अशरफ, शफत अहमद, मंजूर अहमद, अब्दुल माजिद

▶ टाडा कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान यासीन मलिक को भी पेश करने का दिया निर्देश

भट्ट, निसार अहमद, मोहम्मद याकूब, एमएस हलीमा, जावेद इकबाल मीर, मोहम्मद याकूब पंडित और गुलाम मोहम्मद टपलू के खिलाफ वारंट जारी किया है।

डॉ. रुबिया सैयद अपहरण केस में सीबीआइ चालान के मुताबिक श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में आठ दिसंबर 1989 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके अनुसार रुबिया सईद मिनी बस में ललदाद अस्पताल श्रीनगर से नौगाम स्थित अपने घर जा रही थीं। तभी कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका अपहरण कर लिया। सीबीआइ ने जांच पूरी करने के बाद 18 सितंबर 1990 को जम्मू की टाडा कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया। सीबीआइ के दूसरे चालान के मुताबिक 25 जनवरी 1990 की सुबह करीब साढ़े सात बजे रावलपोरा में किराये पर रह रहे एयरफोर्स के अधिकारी सनत नगर क्रॉसिंग पर गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 10 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

पराजय से मनुष्य खत्म नहीं होता- मैदान छोड़ने से होता है

पाकिस्तान का प्रलाप

जम्मू-कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 370 एवं 35-ए हटाने और राज्य का पुनर्गठन करने के बाद जब इसकी हर संभव कोशिश हो रही है कि घाटी में अमन-चैन का माहौल कायम हो तब पाकिस्तान वहां के हालात बिगाड़ने में जुटा हुआ है। स्पष्ट है कि उससे सतर्क रहने की जरूरत है। यह जरूरत इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि वह छल-कपट का सहारा लेने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के छल-कपट पर केवल यह मान लेना पर्याप्त नहीं कि यह उसकी हताशा का नतीजा है। उसकी हरकतों पर गंभीरता से निगाह रखनी होगी, क्योंकि वह बौखलाहट में आकर ऐसे कोई कदम उठा सकता है जो कश्मीर की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साबित हों। पाकिस्तान इस झूठ को सच का रूप देने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में असंतोष उफान पर है और मोदी सरकार के फैसले पर वहां लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। इस झूठ का प्रतिकार और पर्दाफाश सक्रियता के साथ किया जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि वह इसी तरह के झूठ से विश्व जनमत को प्रभावित करने की फिराक में है।

हालांकि अभी तक किसी भी प्रमुख देश ने पाकिस्तान के मन माफिक बयान नहीं दिया है, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कश्मीर पर अपने दुष्प्रचार से किसी देश को झांसे में न ले सके। चूंकि पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है इसलिए वह ऐसी किसी बात पर ध्यान देने वाला नहीं कि उसे कश्मीर की हकीकत स्वीकार करनी चाहिए। वह इस सच को आसानी से इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने जन्म के बाद से ही उसने यह सपना देखा है कि कश्मीर उसका है और वह उसे छल या बल से एक दिन हासिल करके रहेगा। उसने यही सपना अपने लोगों को भी दिखाया और इसी कारण वहां की जनता का एक बड़ा वर्ग इस मिथ्या धारणा का शिकार हो गया कि कश्मीर पाकिस्तान बनने को बेताब है। धीरे-धीरे इस धारणा ने एक उन्माद का रूप धारण कर लिया और उसके चलते वहां ऐसे आतंकी संगठन पैदा हुए जो बंदूक के बल पर कश्मीर हासिल करने की सनक से ग्रस्त हो गए। इस सनक को पाकिस्तानी सेना ने इसलिए बढ़ावा दिया, क्योंकि उसे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक दुश्मन चाहिए था। पश्चिमी देश यह कहते-कहते थक गए कि पाकिस्तान के लिए खतरा भारत नहीं, उसके अपने जेहादी संगठन हैं, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं बदली। चूंकि अनुच्छेद 370 से पाकिस्तान के पैरों तले की जमीन खिसक गई है इसलिए वह बौखलाया हुआ है। भारत को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी यह बौखलाहट आसानी से शांत नहीं होने वाली।

हर वर्ष हो परीक्षा

झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का तीन वर्षों की रिक्तियों के आधार पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय सराहनीय है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए सभी विभागों को रिक्तियां आयोग को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके तहत वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के लिए एकीकृत संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सवाल उठता है कि समय पर सिविल सेवा परीक्षा नहीं हो पाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर जेपीएससी को तीन वर्षों की परीक्षा एक साथ क्यों लेनी पड़ रही है? यह सही है कि इससे रिक्तियां भरेंगी, लेकिन जो युवा इस परीक्षा की तैयारी में अपना जीवन लगा देते हैं उनका क्या होगा? समय पर परीक्षाएं नहीं होने से उनकी आयु बीत जाती है और वे बेरोजगार रह जाते हैं। छठी सिविल सेवा परीक्षा की ही बात करें तो यह हमेशा विवादित रहने के कारण पांच वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकी है। भले ही इसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है, लेकिन इससे संबंधित एक मामला कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश के बाद ही इसका परिणाम प्रकाशित होगा। इस बीच इस परीक्षा की प्रक्रिया में कई बार बदलाव किए गए। कई मामले कोर्ट में गए। इन्हीं सब कारणों से राज्य गठन से लेकर अब तक जहां 18 सिविल सेवा परीक्षा होनी चाहिए थी, वहीं अभी तक महज पांच परीक्षाएं ही सही मायने में पूरी हो पाई हैं। उनमें दो परीक्षाएं विवादित रहीं और उनकी सीबीआइ जांच चल रही है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दूबे की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने वर्ष 2014 में ही अपनी रिपोर्ट में सिविल सेवा परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित करने की अनुशंसा की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब भी तीन वर्षों की परीक्षा एक साथ कराकर अगले वर्ष से यह प्रत्येक वर्ष आयोजित हो तो न केवल राज्य सेवाओं के विभिन्न पद भरेंगे, बल्कि प्रदेश के कई युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी। उम्मीद है कि राज्य सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में पहल कर रही होगी। जरूरत यह भी है कि सभी विभाग रिक्तियां समय पर आयोग को भेज दे, ताकि प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सके।

मोदी-शाह ने बनाया असंभव को संभव

प्रदीप सिंह

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का जो ऐतिहासिक काम किया उसका आजाद भारत के इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है

कुशल और सफल नेतृत्व के बारे में चाणक्य ने कहा है, 'जब किसी काम को करना शुरू करो तो असफलता से मत डरो और उसे छोड़ो मत। शासक के अंदर असफलता का डर नहीं होना चाहिए। काम करते रहो परिणाम की चिंता मत करो।' जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाते समय शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य की इसी नीति पर चले। इस मुद्दे पर देश पिछले सात दशकों से एक ही रास्ते पर चलते-चलते बंद गली में पहुंच गया था। इस जोड़ी ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो पांच अगस्त से पहले अकल्पनीय माना जाता था। आजाद भारत के इतिहास में इसका कोई सानी नहीं है। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर देश सत्तर साल से एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। इस चक्रव्यूह को तोड़ना तो दूर इसको तोड़ने के बारे में सोचने से भी देश की सरकार और सत्तारूढ़ दल कतराता था। इस अनुच्छेद से सूबे के गिने हुए लोगों का निहित स्वार्थ जुड़ा था। अभिनेता मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई थी 'अय्यार'। इसमें उनका फौजी अफसर पूछता है कि जब सब लोग जानते हैं कि कश्मीर समस्या का हल क्या है तो इसे हल क्यों नहीं करते? मनोज वाजपेयी कहते हैं कि जिस समस्या से सबके स्वार्थ जुड़े हों, उसे कोई हल नहीं करना चाहता। मोदी और शाह ने संसद में एक संकल्प के जरिये इसे तोड़ दिया।

मोदी और शाह ने जो काम किया उसका असर देशवासियों पर तारी होने में अभी वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि पूरा देश मान चुका था कि यह काम करने का साहस कोई जुटा नहीं पाएगा। मोदी से इसकी अपेक्षा थी कि शायद वह कुछ करें, लेकिन अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो लोगों ने इसे प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लिया। दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें जनादेश देते समय मतदाता ने मान लिया था कि मोदी भी यह काम नहीं कर पाएंगे। वास्तव में ऐसी दो-तीन पीढ़ियां हैं जिन्होंने मान लिया था कि अपने जीवनकाल में वे यह होते हुए नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लग रहे वंदेमातरम् और भारत माता की जय के नारे को रोका नहीं। वह सदन में खड़े हुए और कहा, 'सत्तर साल की टीस जा रही है तो भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।' प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का जो ऐतिहासिक काम किया उसका आजाद भारत के इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। यह ऐसा सुखद आश्चर्य है जो ज्यादातर लोगों के लिए अकल्पनीय था और अब भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि यह सचमुच हो गया।

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर पल रहे कुछ दल और बुद्धिजीवी इस कदम की गोपनीयता पर सवाल उठाकर इससे अलोकतांत्रिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के तरीके से एक बार फिर चाणक्य नीति याद आती है। चाणक्य ने मंत्र (नीति) गुप्ति का सिद्धांत दिया था। इसे मंत्र संरक्षण भी कहा गया है। इसके मुताबिक राजा को अपनी नीति का संरक्षण कछुए की तरह करना चाहिए। जैसे कछुआ अपने खोल से उतना ही अंग निकालता है जितने की जरूरत होती है उसी तरह जिसको जितना काम दिया गया है उसे उतना ही पता होना चाहिए।

अवधेश राजपूत

अमरनाथ यात्रा रोकी गई तब से लोग कयास लगा रहे थे कि क्या होने वाला है? अब जब अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाकर और सूबे को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया तो कहा जा रहा है कि इससे राज्य की हालत बिगड़ जाएगी। ऐसे लोगों से कोई पूछे कि सत्तर साल में राज्य के हालात सुधरे कब थे। क्या तब जब एक तिहाई से ज्यादा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जब साढ़े तीन लाख हिंदुओं को घाटी से निकाल दिया गया, जब मस्जिदों से एलान हुआ कि अपनी जायदाद और औरतों को छोड़कर चले जाओ तब या जब सैयद अली शाह गिलानी निजामे मुस्तफा लाने की बात कर रहे थे अथवा जब सूफी कश्मीर को जिहादी बना दिया गया या फिर जब नारे लग रहे थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा? पिछले तीन दशक में करीब 42 हजार लोग मारे गए। क्या इसे सुधरे हुए हालात का नतीजा कहें?

दरअसल विरोधियों के पास कोई तर्क है नहीं। संसद के दोनों सदनों में दो दिन इस पर बहस हुई। एक भी वक्ता यह नहीं बता पाया कि अनुच्छेद 370 और 35 ए ने कश्मीर के लोगों को क्या दिया या इस अनुच्छेद को बनाए रखने का औचित्य क्या है? जो अस्थायी था उसे स्थायी क्यों बनाया जाए। पांच अगस्त को जब अमित शाह ने इस अनुच्छेद के एक को छोड़कर बाकी सभी प्रावधानों को हटाने का संकल्प और जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक संसद में पेश किया तो एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का ही शुभारंभ नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और भारत के साथ वास्तविक मायने में एकीकरण और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में विघटन का बीजारोपण भी हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जनार्दन द्विवेदी, भुवनेश्वर कलिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुडा, मिलिंद देवड़ा, रायबरेली की विधायक अदिति सिंह और कर्ण सिंह ने पार्टी के बजाय सरकार के समर्थन का विकल्प चुना।

इतिहास आपको इस बात के लिए याद नहीं रखता कि आपकी पैदाइश क्या है? इतिहास इस बात को याद रखता है कि आपने किया क्या? कश्मीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया वह मोदी और शाह ही सोच सकते थे। संसद के दोनों सदनों में अमित शाह ने जिस तरह पूरी बहस का जवाब दिया उससे उनका राजनीतिक कद कई गुना बढ़ गया है। अभी तक देश ने उनके संगठन का कौशल देखा था। अब उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवा लिया है। अब इस जोड़ी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती घाटी के लोगों को यह समझाने की है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह उनके हित में है। यह चुनौती इसलिए बड़ी है, क्योंकि घाटी और उसके बाहर के कुछ राजनीतिक तत्वों की मंशा और कोशिश है कि शांति व्यवस्था बिगड़े। इसमें उनका साथ देने के लिए लिबरल मीडिया भी लामबंद है। हर तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है। इन तत्वों की पूरी ताकत इसमें लगी है कि संसद में मिली कामयाबी सड़क पर नाकामी में बदल जाए। यह चुनौती सरकार के लिए एक अवसर है। इसकी सफलता में विकास की अहम भूमिका होगी। शायद इसीलिए गृह मंत्री ने संसद में और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास करके दिखाएंगे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

जमीन का टुकड़ा भर नहीं है कश्मीर

नीरजा माधव

एक समय कश्मीर वैसे ही था जैसे रामेश्वरम, द्वारका या पुरी हैं, हमारी अर्चनाओं का भूखंड था यह क्षेत्र

पांच अगस्त, 2019 का दिन भारत के लिए 1947 में मिली आजादी से कम महत्व नहीं रखता। इस दिन अनुच्छेद 370 और 35ए के रूप में कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा और कुछ विशेष अधिकार को समाप्त करने की निर्णायक पहल हुई। ये अधिकार कश्मीर को भारत से अधिक पाकिस्तान की ओर धकेल रहे थे। साथ ही जम्मू-कश्मीर को भारतीय संस्कृति से दूर कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के फैसले से एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग तो बन ही गया, साथ ही भारतीय संस्कृति से उसके जुड़ाव वाले अवरोधक भी खत्म हो गए। दरअसल किसी भी भूखंड का इतिहास उसकी राजनीतिक गलतियों से निर्मित नहीं होता, अपितु उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से तय होता है। ऐसे ही कश्मीर को समझने से पहले उसका सांस्कृतिक इतिहास जानना जरूरी है। कोई भी राष्ट्र मात्र कागज पर पेंसिल से खींचा गया राजनीतिक या भौगोलिक मानचित्र नहीं होता। उसकी एक निरंतर प्रवाहमान सांस्कृतिक धारा भी होती है। जैसे एक नदी कहीं से निकलती है और प्रवाहित होती है। काल के थपेड़ों में कभी वह पूरी तरह सूख जाए, पर जैसे ही वर्षा होती है वह नदी पुनः अपने स्वरूप में जीवित हो उठती है। कश्मीर भी मात्र एक भूखंड नहीं, अपितु अपने अतीत में नदी की तरह पूरा सांस्कृतिक प्रवाह समेटे है। समय के साथ विदेशी हमलावरों के आघात के कारण कश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक छवि भले दब गई हो, पर समय आते ही वह पुनः जीवित हो उठी। कश्मीर की इस प्राचीन विरासत को हमें समझना होगा।

वास्तव में कश्मीर सनातन धर्म और दर्शन का केंद्र रहा है। आज भी प्राचीन काल के अलौकिक मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। वहां की अपनी पूजा पद्धति है। कश्मीर का ज्ञान-विज्ञान इतना उन्नत था कि चीन, जापान से यात्री वहां गए और वहां की संस्कृति, आध्यात्मिकता का वर्णन अपने यात्रा वृतांतों और साहित्य में किया। कश्मीर जो शैव-दर्शन का केंद्र था और हिंदुओं की पहचान था वह किसी कालखंड में इस्लाम का परिचय बन गया। आज जो यह दावा करते हैं कि इस्लाम ही कश्मीरियत है उन्हें यह याद रखना होगा कि कश्मीरियत वह है जो आदि शंकराचार्य के दर्शन में प्रकट होती है और जो अभिनव गुप्त के नाट्यशास्त्र में प्रदर्शित होती है। अध्यात्म का शिखर क्षेत्र है कश्मीर। वह कश्मीर प्राचीन काल से ही ज्ञान, कला और दर्शन का शिखर रहा है। कश्मीर वैसे ही था जैसे रामेश्वरम, द्वारका या पुरी। हमारी अर्चनाओं का भूखंड था यह क्षेत्र। दुखद है कि लोग संस्कृति के नाम पर विलाप करते हैं, उसका वास्तविक अध्ययन नहीं करते। सभी वैचारिक दंगलों के पीछे यही त्रुटि होती है। भारत 'अतिथि देवो भव' जैसी भावुकताओं में विश्वास करने वाले भोले लोगों का देश था। भारत में इस्लाम भारतीय चोला धारण कर मेहमान की तरह आया। हमने उसे अपने घर में स्थान दिया। बाद में क्या हुआ, यह किसी से छिपा नहीं। सब जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ?

यहां यह जानना जरूरी है कि 1947 में भारत की आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर का जितना क्षेत्रफल था, उसके लगभग आधे पर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर कब्जा कर लिया। गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली आदि क्षेत्रों पर पाकिस्तान का बलात नियंत्रण हो गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इसी कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले के पास से पवित्र 'कृष्ण-गंगा' नदी बहती है, जिसका पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे स्वयं ब्रह्मा द्वारा मां शारदा का मंदिर बनाकर उन्हें स्थापित किया गया और उसी के बाद से सारा कश्मीर 'नमस्ते शारदा देवी कश्मीरपुर वासिनी' कहते हुए उनकी आराधना करता रहा। मां शारदा की ऐसी कृपा कश्मीर पर हुई कि शिवपुराण, कल्हण की राजतरंगिणी, चरक संहिता, अष्टांग योग आदि ग्रंथों की रचना वहीं हुई। शैव दार्शनिकों की एक लंबी परंपरा भी कश्मीर से प्रारंभ हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि शारदा पीठ के पास बहुत बड़े-बड़े विद्वान रहते थे और वहां एक विद्यापीठ था जहां दुनिया भर के विद्यार्थी ज्ञानार्जन करने आते थे। हिंदू धर्म की पताका फहराने वाले आदि शंकर ने इसी शारदा पीठ में मां वाग्देवी के दर्शन किए थे। स्पष्ट है कि कश्मीर भारतीयों की पहचान का क्षेत्र है। अब जब अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त हो गए हैं तो उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के साथ ही जीर्ण-शीर्ण मंदिरों का उद्धार भी होगा और मोक्ष और ज्ञान की कामना से लोग वहां प्रवास कर सकेंगे।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | भारत-पाक के बीच व्यापार

(प्रतिशत में भारत के कुल व्यापार का हिस्सा)

वर्ष	व्यापार	प्रतिशत
2018-19	2.56 अरब डॉलर	0.30%
2017-18	2.41 अरब डॉलर	0.31%
2016-17	2.27 अरब डॉलर	0.34%
2015-16	2.61 अरब डॉलर	0.41%
2014-15	2.35 अरब डॉलर	0.31%

ऊर्जा

भूल के लिए माफी

मनुष्य का जीवन मिला है तो उसमें गलतियां होती रहती हैं। गलतियों की व्याख्या ऋषियों-मुनियों ने यह की है कि जब व्यक्ति स्व-हित में शास्त्र विरुद्ध या संविधान विरुद्ध कार्य करता है तो वह पाप या अपराध के रूप में माना जाता है। पर-पीड़ा को निंदनीय माना गया है। कुछ गलतियां तो अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर गलतियां तो जानबूझकर होती हैं। संविधान द्वारा बनाए गए नियम-कानून का उल्लंघन करने पर शासन-व्यवस्था दंड देती है, लेकिन परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों के साथ गलती या नकारात्मक कार्य, जिसका दंड यदि कानून व्यवस्था से नहीं मिलता, उसका फल प्राकृतिक ढंग से मिलता है। प्रथमतः तो आदतें बिगड़ती हैं। गलत रास्तों से मिली सुविधा या भौतिक संसाधन के साथ पीड़ित व्यक्ति की आह भी मिलती है। किसी का धन हड़प कर उससे की गई पूजा-पाठ का लाभ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस भगवान की कृपा के लिए पूजा-पाठ या अनुष्ठान किया जाएगा, वह भगवान स्वीकार कर लेगा, यह असंभव है।

मनुष्य-जीवन में गलती का पता लगाने के लिए उपाय बताए गए हैं जिसमें हर दिन शाम को सोते समय इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए कि पूरे दिन तिकड़म, धोखा, झूठ करके किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचाई? यह पूरी तरह सच है कि तेजी से भागती जिंदगी में थोड़ी देर के लिए रुक कर अपने मन से संवाद किया जाए तो मन सब कुछ सच सच बता देता है।

ऋषियों-मुनियों ने आनंदपूर्ण जीवन के लिए ही प्रायश्चित करने का उपाय बताया है। जिसमें सर्वप्रथम जिसके साथ गलती की गई है, उसे जाकर बता देना कि मैंने आपके साथ गलत काम कर दिया है। यदि यह न हो सके तो अपने मन में यह ठान लेना चाहिए कि अब इस तरह की गलती किसी के साथ किसी भी हालत में नहीं करूंगा। गलतियों का खुलेआम बयान प्रायश्चित-यज्ञ है। ऐसा न करने पर जीवनपर्यंत की गई गलती को लेकर पश्चाताप होता रहेगा और यह पश्चाताप जीवन को कष्टदायी बनाता रहेगा।

सलिल पांडेय

उड़न तश्तरियों की सच्चाई

सौरभ सिंह

दुनिया भर में उड़न तश्तरी देखे जाने के ढेरों दावे किए जा चुके हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर उड़न तश्तरी अब भी खरी नहीं उतरी है

पिछले दिनों चीन के कई प्रांतों में लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने आसमान में एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु या यूएफओ देखा है जिसके पीछे चमकती रेखा दिख रही है। दुनिया के कई शहरों में उड़न तश्तरियों को उड़ते हुए देखे जाने की खबरें जब तब आती रही हैं। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं अर्थात अनआइडेंटीफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स (यूएफओ) का आकार किसी डिस्क या तश्तरी के समान होता है या ऐसा दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें उड़न तश्तरियों का नाम मिला।

उड़न तश्तरी शब्द 1940 के दशक में निर्मित किया गया था और ऐसी वस्तुओं को दर्शाने या बताने के लिए प्रयुक्त किया गया था जिनके उस दशक में बहुतायत में देखे जाने के मामले प्रकाश में आए। उड़न तश्तरी शब्द ऐसी उड़ती वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो दिखने में किसी तश्तरी जैसी दिखाई देती है। उड़न तश्तरियों के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर की अधिकांश सरकारों द्वारा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ गवाह उड़न तश्तरियों के देखे जाने का दावा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उड़ती वस्तुओं का संबंध परग्रही दुनिया से है, क्योंकि इनके संचालन की असाधारण और प्रभावशाली क्षमता मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त किसी भी उपकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वह बिल्कुल अलग दिखती है। प्राचीनकाल से ही उड़न तश्तरियों के देखे जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये पिछले 50-60 वर्षों से अधिक प्रकाश में आई हैं। इनके अध्ययन को यूफोलॉजी कहा जाता है। ये वे लोग होते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं की खोज करते हैं।

दुनिया भर में उड़न तश्तरी देखे जाने के हजारों दावे किए जा चुके हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर उड़न तश्तरी अब भी खरी नहीं उतरी है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रो. कोलिन प्राइस उड़न तश्तरी को प्राकृतिक परिघटना के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उड़न तश्तरी एक प्राकृतिक परिघटना है। उन्होंने इसका नाम स्प्राइट यानी जादुई परी रखा था। वर्ष 1989 में दुर्घटनावश स्प्राइट की परिघटना को रिकॉर्ड कर लिया गया था। उस समय एक खगोल विज्ञानी ने तारों का अध्ययन करते समय अपनी शक्तिशाली दूरबीन से जुड़े कैमरे में कौतूहलपूर्ण क्षणिक घटना को कैद कर लिया था। बाद में प्रो. प्राइस और उनकी टीम ने उस पर गंभीर अध्ययन किया तो पाया कि धरती से 50 से 120 किलोमीटर पर इस तरह की घटनाएं खास परिस्थितियों में लगातार होती रहती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि खास प्राकृतिक घटनाओं की वजह से ऐसा दिखाई देता है। आकाश में काफी ऊंचाई पर बनने वाले शक्तिशाली चक्रवातों की वजह से विद्युतीय तरंगें पैदा होती हैं, जो विमानों और राडारों को प्रभावित करती हैं। कई बार तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी प्रभावित हो जाता है। चक्रवात जैसी ये प्राकृतिक घटनाएं किसी को भी चमत्कारिक लग सकती हैं। इन्हीं घटनाओं को लोग उड़न तश्तरी समझ लेते हैं।

(लेखक दिल्ली विवि में शोधार्थी हैं)

भ्रमित कांग्रेस

नई शुरुआत के इंतजार में कांग्रेस शीर्षक से लिखे अपने लेख में रशीद किदवई ने ठीक ही लिखा है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रही है। अनुच्छेद 370 के हटने पर ही नहीं, देश के अन्य सभी मुद्दों पर कांग्रेस खुद अपनी विचारधारा की तलाश करती सी नजर आ रही है। सौ वर्षों से अधिक के अपने जीवन में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इतना विवश और दिशा भ्रमित कभी नहीं पाया होगा। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहर लाल नेहरू और कामराज जैसे दिग्गज अध्यक्ष देख चुकी कांग्रेस पार्टी आज एक बेहद कमजोर अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद अपने नए अध्यक्ष का चयन करने में भी असमर्थ है। खेदजनक है कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेसियों को अध्यक्ष के लिए प्रियंका गांधी ही नजर आती हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कुछ कांग्रेसी प्रियंका के बेटे का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित कर दें। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना मजबूत सरकार के बराबर ही महत्वपूर्ण होता है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस की कमान दूसरी पीढ़ी के किसी सक्षम नेता के हाथों में सौंपी जाए। फिर वह देश भर में पार्टी के संगठन को सक्रिय करने का काम करे, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है।

राजीव वार्ष्णेय, चंदौसी

कश्मीर में अब असली आजादी

अनुच्छेद 370 को हटाकर भाजपा सरकार ने अपनी संकल्पशक्ति, दृढ़ता, दूरदर्शिता तथा साहस से एक देश, एक विधान का सपना साकार किया है। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आजादी के 70 वर्षों बाद आज सही मायनों पूरा हुआ है। अनुच्छेद 370 भारत के लिए नासूर बन चुका था। इस ऐतिहासिक भूल ने देश की अखंडता के लिए बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी थी। 70 वर्षों तक एक ही रास्ते पर चलते-चलते हम 41500 से ज्यादा जानें गंवा चुके हैं। ये हिंसा, खून खराबा अब बंद होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र प्रशासित राज्यों कश्मीर एवं लद्दाख में बांटा गया है इससे दोनों राज्य विकसित होंगे। केंद्र सरकार ने 370 हटा कर भारत को सही मायनों में आजादी दिलाई है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय हित में लिए इस साहसिक एवं ऐतिहासिक फैसले का सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर स्वागत करना चाहिए।

thakurkk999@gmail.com

मेलबाक्स

पाक की बौखलाहट

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने एवं जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है। जबसे पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना है, तब से ही उसकी आदत रोने की है। रोने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि पाक जैसे देश को विकास, निर्माण व सद्भावना नहीं हमेशा कड़वाहट ही दिखाई देती है, क्योंकि इसके खून में ही कटुता है। भारत को भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की दरकार है। पाकिस्तान को यह इल्म कराना होगा कि उसको भारत की जरूरत है, ना कि हमें पाकिस्तान की। जिस सख्ती से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद समाप्त किया, उसी सख्ती से पाकिस्तान को जवाब देने की दरकार है।

hemahariupadhyay@gmail.com

कुछ तथ्य ठीक नहीं

दैनिक जागरण के 07 अगस्त के अंक में प्रकाशित शेरू थपलियाल का लेख, नेहरू की जिद्द से जुड़ा था अनुच्छेद 370, में संभवतः विलय पत्र पर कुछ तथ्य ठीक नहीं लगते। जहां तक मेरा ज्ञान है, उससे यह ज्ञात होता है कि विलय पत्र का प्रारूप अन्य सभी रियासतों के समान ही था। राजा हरि सिंह ने भी उसी ही स्थिति में बिना शर्त उस विलय पत्र को स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भविष्य में इस विलय पत्र में कोई परिवर्तन होगा तो मुझसे अनुमति ली जाए, परंतु उन विषम परिस्थितियों में कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण जो भी परिवर्तन विलय पत्र में किए गए एवं अन्य जो निर्णय हुए वे सब लॉर्ड माउंटबेटन एवं नेहरू की सहमति से हुए थे। जबकि इसमें शेख अब्दुल्ला की विशेष भूमिका सर्वविदित ही है।

विनोद कुमार सर्वोदय, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

अर्थव्यवस्था मांग रही अधिक निवेश

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीते दिनों प्रतिकूल खबर आई कि विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों में भारत का स्थान वर्ष 2017 के पांचवें से अब सातवें पर आ गया है। हालांकि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में कायम है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो देश में अर्थव्यवस्था में सुस्ती को इंगित करने के लिए पर्याप्त हैं, फिर भी समय रहते ध्यान दिया जाए तो इससे उबरना बहुत मुश्किल नहीं है

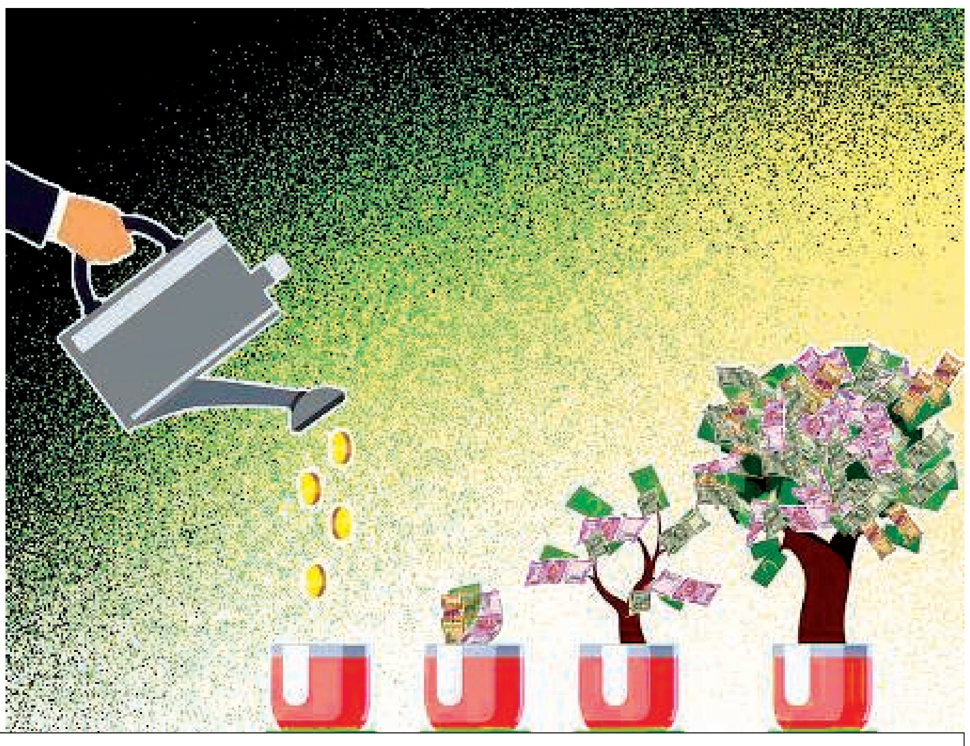

प्रो. लल्लन प्रसाद
पूर्व विभागाध्यक्ष, बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पिछली चार तिमाहियों में विकास दर (जीडीपी) में गिरावट, विदेशी संस्थागत निवेशकों, एफआइआइ द्वारा बड़ी मात्रा में भारतीय शेयरों की बिकवाली, शेयर मार्केट में लगातार सूचकांक नीचे की ओर लुढ़कना, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होना, स्वदेशी बचत और निवेश में कमी, औद्योगिक उत्पादन में शिथिलता और सेवाओं के विकास में कमी, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापार युद्ध (ट्रेड वार), अमेरिकी फेडरल रिजर्व की उधार नीति (क्रेडिट पॉलिसी) से निराशा और विश्व व्यापार में कमी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता के विषय हैं, किंतु फिलहाल स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है। ऐसे में आंतरिक बचत और निवेश में भारी वृद्धि की आवश्यकता है जिससे कल-कारखानों, खेतों और सेवाओं में उत्पादन बढ़े, रोजगार के अवसर बनें और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो सके।

आर्थिक गिरावट के संकेत

निवेश और मांग में कमी विकास दर में गिरावट और आर्थिक मंदी का संकेतक है। पिछली तिमाही में विकास दर 5.8 प्रतिशत पर आ गई जो मोदी सरकार के शासन का सबसे निचला स्तर है। मार्च 2017 में विकास दर 7.2 प्रतिशत रही, 2018 में 6.8 प्रतिशत, और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित विकास दर सात प्रतिशत है। ऐसे में वर्ष 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कम से कम आठ प्रतिशत वृद्धि दर अपेक्षित है।

आधारभूत उद्योगों (इंफ्रास्ट्रक्चर) का औद्योगिक विकास के सूचकांक में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान होता है। ये उद्योग धीमी गति से बढ़ रहे हैं। जून 2019 में इनका विकास दर मात्र 0.2 प्रतिशत था जो पिछले 50 महीनों में सबसे निचले स्तर पर था। रिफाइनरीज के उत्पादन में नौ प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज की गई, क्रूड ऑयल में 6.3 प्रतिशत, नेचुरल गैस में 2.1 प्रतिशत और सीमेंट में 1.5 प्रतिशत की गिरावट हुई। बिजली उत्पादन में वृद्धि 7.3 प्रतिशत की हुई जो संतोषजनक कही जा सकती है। निर्यात में नौ प्रतिशत से अधिक गिरावट का एक बड़ा कारण ओएनजीसी की मंगलौर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का कुछ समय के लिए बंद होना और जामनगर रिफाइनरी में मरम्मत संबंधी कार्यों के कारण उत्पादन में व्यवधान पैदा होना माना जा रहा है।

ऑटोमोबाइल पर असर

मंदी का सबसे अधिक असर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पड़ा है। गाड़ियों की बिक्री पिछले दो दशक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री जुलाई 2019 में जुलाई 2018 की अपेक्षा 37 प्रतिशत कम रही, हुंडई मोटर्स इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में क्रमशः 10 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पिछले एक वर्ष में पांच बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री में 31 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई।

ऑटोमोबाइल सेक्टर निवेश और रोजगार दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मांग में गिरावट निवेश और रोजगार दोनों में कमी का कारण बनता है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार लगभग 300 डीलर्स ने काम बंद कर दिया है। कारों के अलावा अन्य वाणिज्यिक वाहनों और मोटर साइकिलों की मांग में भी भारी कमी आई है। शहरी और देहाती क्षेत्रों से मांग में कमी के कारण उत्पादन में कंपनियों को कटौती करनी पड़ रही है। निवेश में कमी का एक कारण नॉन बैंकिंग कंपनियों (एनबीसी) द्वारा कर्ज लेने में कठिनाई बताई जा रही है। साथ ही किसानों की आमदनी में कमी मोटर साइकिलों की बिक्री में कमी का बड़ा कारण है।

बड़ी कंपनियों के राजस्व में कमी

बड़ी कंपनियों का व्यापार मंदी के कारण प्रभावित हुआ है, उनके राजस्व में कमी आई है। शेयर सूचकांक में सम्मिलित जिन कंपनियों का राजस्व हाल के महीनों में कम हुआ है उनमें प्रमुख हैं- बजाज ऑटो, हीरो मोटर, हिन्दुस्तान यूनी लीवर, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, वेदांता और यस बैंक। हालांकि वित्तीय कंपनियां उतनी प्रभावित नहीं हुई हैं जितनी गैर-वित्तीय कंपनियां, जिनके राजस्व और लाभ दोनों में गिरावट आई है। स्टाक मार्केट में शेयर सूचकांक में हाल में जो भारी गिरावट देखी गई है उसका एक प्रमुख कारण है स्वदेशी कंपनियों के राजस्व और लाभ में कमी। दूसरा प्रमुख कारण है विदेशी निवेशकों ने जो 9.4 अरब डॉलर के शेयरों की खरीद की थी, उसका 20 प्रतिशत वे बेच चुकी हैं। जुलाई 2019 में सरकार ने बजट में बड़ी कंपनियों की आमदनी पर सरचार्ज लगाकर उनकी टैक्स रेट में जो वृद्धि कर दी है उसका असर विदेशी संस्थागत निवेशकों पर भी पड़ा है।

बजट आने के बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वह थम नहीं रहा है। हालांकि इसके कुछ बाहरी कारण भी हैं। अमेरिका और चीन में ट्रेड वार लंबा खिंच रहा है जिससे विदेशी व्यापार प्रभावित हो रहा है। निर्यात में कमी आई है, क्योंकि बहुत सारे देश मंदी की मार झेल रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में हाल ही में जो थोड़ी कमी की उसके साथ यह भी जता दिया कि यह एजस्टमेंट था जिसका अर्थ निकाला गया कि निकट भविष्य में फिर कमी की संभावना नहीं है। निवेशकों में इससे निराशा हुई जो शेयर बाजार को विश्व भर में प्रभावित कर रही है। शेयर बाजार आर्थिक स्थिति के अलावा आगे आने वाली संभावनाओं के आकलन पर भी ऊपर नीचे होता रहता है। निकट भविष्य में मांग में कमी रहने और निवेश न बढ़ने की संभावना शेयर की कीमतों के चढ़ाव में बाधक है।

किसानों की आय में कमी

किसानों की आमदनी में कमी, जो इनके द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं में भी परिलक्षित होती रही है, बाजार में मांग की गिरावट का बड़ा कारण है। अतिवृष्टि और बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कृषि पदार्थों की लागत से कम कीमत किसानों की दुर्दशा का कारण बनती है। बैंकों से कर्ज न मिलने पर सूदखोरों के चंगुल में फसे छोटे किसानों की संख्या कम नहीं है। कर्ज माफी के वादे कई राज्यों में कागज पर ही रहे, बहुत कम संख्या में किसान लाभान्वित हुए। सतही (मार्जिनल) और छोटे किसानों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। किसान सम्मान निधि और फसलों की सरकारी खरीद की कीमतों में वृद्धि से किसानों को कुछ राहत मिली है।

पर्यटन, रीयल एस्टेट, बीमा आदि में कमी

सेवा क्षेत्र, जिसमें व्यापार, यातायात, होटल, पर्यटन, वित्त, रीयल एस्टेट, बीमा आदि शामिल हैं, जो देश की जीडीपी में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान करते हैं, उनका विकास दर भी मंदी के कारण प्रभावित हुआ है। वर्ष 2017-18 में सेवाओं का विकास दर 8.1 प्रतिशत था जो 2018-19 में 7.5 प्रतिशत अनुमानित है। औद्योगिक और उपभोक्ता पदार्थों की मांग में कमी से लघु और मध्यम उद्योगों में भी उत्पादन में कमी आई है, रोजगार के अवसर भी कम हुए हैं। असंगठित क्षेत्र में विनिर्माण में कमी आने से बाजार में और कमजोरी आई है।

घरेलू बचत योजनाएं बनें आकर्षक

घरेलू बचत (हाउस होल्ड सेविंग्स) निवेश का बड़ा स्रोत है जो घटता जा रहा है। वर्ष 2011-12 में घरेलू बचत दर जीडीपी का 36.6 प्रतिशत था जो 2017-18 में 17.2 प्रतिशत पर आ गया। विभिन्न बचत योजनाओं में सरकार के पास जो धन आता है वह केंद्र सरकार के बजटीय घाटे को पूरा करने, राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए उपयोग में आता है। कंपनियों में निवेश के लिए भी घरेलू बचत महत्वपूर्ण स्रोत है। घरेलू बचत जो रीयल इस्टेट में लगता है उसमें कमी आई है और वित्तीय सेक्टर में लगने वाले में भी कमी आई है। छोटे कारोबारियों द्वारा किया जाने वाला बचत भी घरेलू बचत की श्रेणी में आता है। घरेलू बचत की दर में जहां लगातार गिरावट हो रही है, वहीं इस क्षेत्र के लोगों की देनदारी बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2009-10 की अपेक्षा यह 200 प्रतिशत तक बढ़ गई है। घरेलू बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बचत बैंक खातों और बचत योजनाओं के ब्याज दर बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले कई वर्षों से जमाकर्ताओं को मिलने वाली ब्याज दर में कटौती होती रही है, जिससे आम लोगों के बीच बचत का आकर्षण कम होता गया।

सुगमता से मिले कर्ज

उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पिछली चार तिमाहियों में लगातार रेपो रेट (वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देती है) में कमी करती आई है। फरवरी 2019 में रेपो रेट 6.25 प्रतिशत था, अप्रैल 2019 में छह प्रतिशत, जून 2019 में 5.75 प्रतिशत और अगस्त 2019 में 5.4 प्रतिशत हो गया है जिसकी घोषणा रिजर्व बैंक ने सात अगस्त को की। रेपो रेट में कमी का उद्देश्य है बैंकों के लिए कर्ज सस्ता करना ताकि वे इसका लाभ उधार लेने वाली कंपनियों और आम लोगों को दें। किंतु रिजर्व बैंक के द्वारा रेट में कमी के बावजूद बैंकों ने कर्ज लेने वालों के लिए रेट में उतनी कमी नहीं की जितनी अपेक्षित है। इसका एक कारण है सरकारी बैंकों का एनपीए जो 31 मार्च 2018 को लगभग नौ लाख करोड़ रुपये था। सरकार द्वारा रीकैपिटलाइजेशन के लिए बैंकों को अनुदान एवं अन्य सुधारों के फलस्वरूप अब यह करीब आठ लाख करोड़ रुपये रह गया है। सरकार द्वारा सख्ती दिखाए जाने के बाद बैंक बड़े कर्ज देने में अब काफी सावधानी बरतने लगे हैं।

उपभोक्ता विश्वास सूचकांक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया हुआ उपभोक्ता विश्वास सूचकांक (कंज्यूमर्स कान्फिडेंस इंडेक्स) इस बात का संकेत दे रहा है कि निकट भविष्य में मांग में तेजी के आसार कम हैं। विश्वास का सूचकांक उस समय नीचे था जब यूपीए की सरकार का आखिरी दौर था, और एनडीए 2014 में सत्ता में आई। उसके बाद बाजार में तेजी का दौर शुरू हुआ जो फिर मंदी में बदलने लगा जब नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण हुआ और उसके बाद जीएसटी लागू हुआ। अर्थव्यवस्था अभी तक इनके प्रभाव से पूरी तरह उबर नहीं पाई है।

घरेलू बचत से पूंजी बाजार में निवेश

अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक को मिलकर प्रयास करना होगा। बजत योजनाओं, प्रॉविडेंट फंड, बचत बैंक और फिक्स डिपाजिट पर ब्याज दर बढ़ाकर घरेलू बचत को बढ़ावा देने की जरूरत है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े करदाता कंपनियों पर जो अधिभार लगाया गया है उस पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। आयकर की 80 सी में छूट की सीमा बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर सकती है। बढ़ाई जाने वाली छूट यदि पूंजी बाजार में निवेश कर दी जाए तो शेयर बाजार में लोगों को भागीदारी का प्रोत्साहन मिलेगा। परंपरागत निर्यात उद्योगों जैसे जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाईल आदि में निवेश को प्रोत्साहन की विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। नॉन बैंकिंग कंपनियों (एनबीसी) जो छोटे और मध्यम उद्योगों के कर्ज की बड़ी स्रोत है, के प्रति रिजर्व बैंक के रवैये में नरमी की आवश्यकता है। मंदी की अर्थव्यवस्था को बढ़ता निवेश और बढ़ती मांग ही सहारा दे सकती है।

खरी-खरी

आलमारी हटा दी, बिलबिला रहे चूहे

अतुल कनक

मेरे आवासीय परिसर में एक पुरानी आलमारी रखी थी। मैं बहुत दिनों से उसे हटाना चाहता था, लेकिन अड़ियल और मूर्खता को प्राप्त हो चुका छोटा भाई हर बार कोई खुराफात कर इसे हटने से रोक देता। कभी वो बुआ को समझाता कि ये आलमारी उसके पुरखों की निशानी है तो कभी दूर के मौसाजी को भड़का देता कि इस आलमारी को हटाकर मैं सारे परिसर पर कब्जा करना चाहता हूं। जबकि घर के बंटवारे के समय यह आलमारी मुझे ही मिली थी, मगर अब यह मेरे लिए आफत बन चुकी थी।

मेरे बाबा ने बंटवारे के समय न जाने क्यों उस आलमारी को परिसर में रखवा दिया था। हो सकता है तब घर अस्त-व्यस्त रहा होगा, इसलिए पहले घर को व्यवस्थित करना प्राथमिकता में रहा होगा।

बंटवारे में छोटे को ज्यादा ही दिया गया था। लेकिन छोटे की नीयत खोटी थी कि उसे ये आलमारी भी चाहिए थी। जब बाबूजी ने उसे न दी तो उसने पड़ोस के गुंडे भेज उसे हथियाना चाहा। तब मैंने ही उन गुंडों को मार-मारकर भगा दिया था। मगर तब तक उन्होंने आधी आलमारी हड़पते हुए उसमें अपना सामान रख लिया था। मैंने भी सोचा कि चलो इसने आधी ले ली है, तो अब क्या झगड़ा करें! मैं बड़ा था, सो समझदारी दिखाई।

मगर बाद में छोटे ने आलमारी से कपड़े हटाकर उसमें बम रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आलमारी के पीछे चूहों ने बिल बना लिया। कई बार उस तरफ से मेरे घर में चूहे, यहां तक कि जहरीले सांप तक इन बिलों से रेंगकर हमारी तरफ आ जाते थे। मैंने छोटे को कई बार समझाया तो वह मानने के बजाय लड़ाई पर उतर आया।

मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए। वे समझदार भी थे, चतुर भी और दमदार भी। संयोग से कुछ चूहे, कॉकरोच उनके सामने ही आलमारी के पीछे से निकले और हमारे घर में उधम मचाने लगे। पहले तो मेरे बेटे ने उन चूहों को सबक सिखाया और आलमारी में जहां कॉकरोचों ने घर बनाए थे, वहीं पर ऐसी दवा डाली कि सब मर-खप गए।

मगर छोटा जन्मजात खुराफाती था, इसलिए वह कहां मानने वाला था। इस बीच मेरे बेटों ने मिलकर तय किया कि अगली बार कॉकरोच आएं, उससे बेहतर है कि आलमारी की साफ-सफाई कर उसे घर के अंदर रख लिया जाए। दोनों ने ऐसी झाड़ू लगाई कि आलमारी एक ही दिन में साफ करके घर के अंदर रख ली।

ट्वीट-ट्वीट

तीन दशक बाद भी आम पाकिस्तानियों को देश की कश्मीर नीति का कोई लाभ नहीं मिला, सिवाय इसके कि जिहाद के आधार पर समाज ध्रुवीकृत हुआ और लोगों में भारत के खिलाफ घृणा भरी गई।
नायला इनायत@nailainayat

कश्मीर पर मोदी सरकार के कदम की मैं अब भी आलोचना करता हूं, लेकिन इसकी वेस्ट बैंक से तुलना करना गलत है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कश्मीर 'अधिकृत क्षेत्र' नहीं, बल्कि 'विवादित क्षेत्र' है और 1947 से भारत का हिस्सा है तथा कश्मीरी भारतीय नागरिक हैं, जबकि वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनी हैं।
शशि थरूर@ShashiTharoor

कुछ लोग ज्ञान दे रहे कि कश्मीर में सब खुश नहीं। सब खुश कैसे होंगे? पत्थरबाज कैसे खुश होंगे? आतंकियों के जनाजे में शामिल होनेवाले कैसे खुश होंगे? जिनकी सियासी दुकान बंद होगी वो कैसे खुश होंगे? हां, जिन्होंने कभी किसी से नहीं पूछा कि 'इंडिया से आए हो' वे जरूर खुश हैं।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

मानव जनित समस्याओं से जूझते वन्य प्राणी

अनु जैन रोहतगी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

हाल ही में असम का एक गांव हारमति अचानक चर्चा में आ गया। इस गांव के पास ही में बसे काजीरंगा नेशनल पार्क से एक बाघ भाग कर गांव में घुस गया और एक घर में बिस्तर पर डेरा डाल लिया। यह खबर गांववालों के लिए डरावनी और पशुप्रेमियों के लिए चिंता का विषय थी, क्योंकि वे समझ रहे थे कि क्यों एक बाघ को अपने घर से भागकर इंसानों के बीच शरण लेनी पड़ी। दरअसल असम में बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में रहने वाले सैकड़ों जानवरों को इधर-उधर भटकने पर मजबूर कर दिया है, बहुतों मारे भी गए हैं। आंकड़े गवाह हैं कि हर साल बाढ़ के रूप में पानी का तांडव इन जानवरों का जीवन संकट में डाल देता है।

कुछ सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो जानवरों की मौत और उनके बेघर होने का एक बड़ा कारण है बाढ़। अकेले काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के कारण 220 से अधिक जानवरों की मौत हो चुकी है। यही नहीं सुरक्षित घरों की तलाश में भागे 16 हाट डियर यानी एक विशेष प्रजाति के प्राणी नेशनल हाइवे-37 पर वाहनों की चपेट में आ चुके हैं। वर्ष 2018 में संसद में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि इसी पार्क में बाढ़ और नेशनल हाइवे पर वाहनों का शिकार होकर मारे जाने वाले जानवरों की संख्या 400 थी। 2017 में भी यहां बाढ़ ने 335 जानवरों की जान ली थी।

यूनेस्को द्वारा घोषित 'वर्ल्ड हैरिटेज साइट' में हर साल बाढ़ के दौरान जानवर मर रहे हैं और इसको रोक पाने के तमाम कदम निराधार साबित हो रहे हैं। चिंताजनक यह भी है कि पानी से बचने के लिए जानवर जब सड़क पर आ जाते हैं तो कितनी बेहरमी से कुचल दिए जाते हैं। ट्रेन से मरने वाले जानवरों की संख्या तो और भी भयावह है। हाल ही में रेल मंत्री ने संसद में बताया कि 2016 से जून 2019 तक 35,732 जानवर ट्रेन दुर्घटना में जान गवां चुके हैं। पिछले छह सालों में ट्रेन दुर्घटना में 2,330 हाथियों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक आंकड़े इससे अधिक होंगे, क्योंकि दुर्घटना और बाढ़ के कारण मारे जाने वाले जानवरों पुख्ता लेखा-जोखा नहीं है। कई मानवजनित कारणों से भी जानवर मारे जा रहे हैं। सबसे अहम हैं हाइवे के पास ज्यादातर नेशनल पार्क का होना। नेशनल हाइवे-37 के पास बने काजीरंगा नेशनल पार्क की तरह देश में कई ऐसे पार्क हैं जो हाइवे के पास बने हैं और यहां पर गलती से सड़कों पर आए जानवर सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। जैसे कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क एनएच-67 और एनएच-22 नेशनल हाइवे के पास है। इसी प्रकार नीलगिरी के पास सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य एनएच-209 पर है जो जानवरों की मौत का बड़ा कारण बन रहा है।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि रेलवे ट्रैक के आसपास बड़ी संख्या में पेड़-पौधे उग आते हैं जिससे जानवरों को ट्रेन नहीं दिखाई देती है। ऐसी जगहों पर सोलर लाइट्स की व्यवस्था करने का सुझाव है। देखा गया है कि शाम छह बजे से सुबह छह के बीच रेल दुर्घटना से अधिकांश जानवर मारे जाते हैं। ऐसे इलाकों में रेलवे की कोशिश होनी चाहिए कि इस दौरान ट्रेन कम चलें तथा ट्रेन की गति कम हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ट्रैक के आसपास कोई जानवर दिखाई देने की दशा में उसे तत्काल रोका जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि समय-समय पर उन वन्य अधिकारियों और रेल ड्राइवरों का सम्मान भी हो जिनकी सूझबूझ से जानवरों की जान बची। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को और खास तौर पर गांववालों को जानवरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है। गन्ने और केले के खेतों के आसपास बिजली के तारों की बजाय कोई और उपाय अपनाया जाए ताकि हाथी या अन्य कोई जानवर उसकी चपेट में आकर मारा नहीं जाए।

वैसे जानवरों को सड़क-रेल दुर्घटना से बचाने के लिए सरकार के कई स्तरों पर प्रयास जारी हैं। जंगली इलाकों और वन्य जीव अभयारण्यों के बीच और आसपास बनी सड़कों, पुलों, पाइप लाइनों को किस तरह से डिजाइन करें कि जानवरों और इंसानों के बीच टकराव न हो, इसके लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने पर्यावरण मंत्रालय, नेशनल हाइवे अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सहयोग से पर्यावरण अनुकूल अनेक योजनाएं बनाने की बात कही है। इस संबंध में हमें तमिलनाडु में किए गए एक प्रयोग से सीख लेनी चाहिए जहां हाथियों को रेल दुर्घटना से बचाने के लिए बाकायदा कोयंबटूर में हाथियों द्वारा रेलवे ट्रैक पार करने की तमाम संभावित जगहों पर रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सेंसर लगाए हैं जिससे जब कोई हाथी ट्रैक के पास पहुंचता है, वन्य अधिकारियों को अलार्म के जरिये इसकी सूचना मिल जाती है जिससे इनकी जान बचाने में सहायता मिलती है।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या रिजर्व बैंक द्वारा दरें घटाने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी?

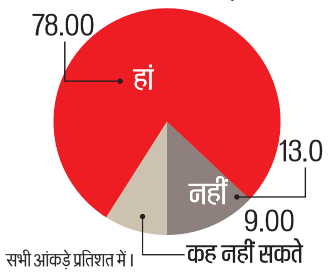

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारत को भी अब पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लेने चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'समझौता' कैसे चले जब हो मन में खोट,
हम छींके भर थे जरा उन्हें लग गई चोट!
उन्हें लग गई चोट दिख रहे हैं झल्लाए,
खंभा नोचें आप बिलैया ज्यों खिसियाए।
मुंडन-छेदन हेतु कहां तक भेजें न्यौता,
करना है तो बंद करो भाई 'समझौता'!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

पुलिस तंत्र में सुधार पर हो जोर

हमारे देश में पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौर वाली ही है जब सत्ता के संचालन में सहूलियत के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आजाद और लोकतांत्रिक मुल्क में जिस तरीके से इसमें व्यावहारिक बदलाव किया जाना था वैसा नहीं हो पाया है

सुनील तिवारी

वर्तमान पुलिस तंत्र में व्यापक सुधार करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। आजादी के सात दशक बाद भी हमारे देश में अंग्रेजों के समय की पुरानी पुलिस व्यवस्था लागू है। अगर इतिहास में झांककर देखें तो पता चलता है कि भारतीय पुलिस आज भी 1861 में गोरों द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम के माध्यम से संचालित होती है। पुलिस प्रशासन का मूल कार्य समाज में अपराध रोकना एवं कानून व्यवस्था को कायम रखना होता है। ब्रिटिश हुकूमत ने 1861 के पुलिस अधिनियम का गठन भारतीयों के दमन एवं शोषण के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया था। ऐसे दमनकारी एवं शोषणकारी पुलिस अधिनियम की राह पर चलने वाली पुलिस व्यवस्था से स्वच्छ छवि की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? इसी कारण से समाज में पुलिस का चेहरा बदनाम हुआ है। आज लोगों के भीतर पुलिस का चेहरा एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति की तरह समा गया है। पुलिसकर्मियों की काली करतूतें तकरीबन रोजाना पढ़ने या सुनने को मिलती हैं।

दरअसल इसमें पूरी तरह से दोषी इन पुलिसकर्मियों को भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इन सभी के अंदर भी शोषण एवं दुख की एक कहानी दबी हुई होती है। निर्दयी पुलिस के दिल की बात जानने पर हमें यह पता चलता है कि वह आखिर ऐसी क्यों बनी? पुलिस वाले भी तो समाज का ही हिस्सा होते हैं। उन्हें भी घूमने, टहलने एवं घर वालों के साथ समय बिताने की इच्छा होती है और इसके लिए उन्हें समय मिल नहीं पाता। मनोविज्ञान भी यह कहता है कि इस स्थिति में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने मन की खुन्नस दूसरों पर उतारने लगता है। इसी से पुलिस का एक ऐसा चेहरा उभरकर आता है जिसमें वह निर्दयी दिखाई देता है।

आज देश में पुलिस सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश नहीं की गई है। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कई समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया है और उनकी रिपोर्ट भी सौंपी गई है, लेकिन अमल के स्तर पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ। अभी तक जितने भी प्रयास किए गए उनमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का साफ अभाव देखा गया है। पुलिस सुधार के लिए कई समितियों और आयोगों का गठन किया गया और इन सबने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी पर सरकारों ने उन पर अमल नहीं किया।

वर्ष 1996 में पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह और एनके सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआइएल लगाकर अनुरोध किया था कि केंद्र एवं राज्य सरकारें 1979 के राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) रिपोर्ट को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पूर्व पुलिस अधिकारी रिबेरो के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी और उसने अपनी रिपोर्ट 1999 में दी। इसके बाद पद्मनाभैया कमेटी का गठन किया गया जिसने वर्ष 2000 में रिपोर्ट दी। अंत में पूर्व एटार्नी जनरल सोली सोराबजी को पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया। उनसे कहा गया कि वे 1861 के औपनिवेशिक पुलिस कानून के स्थान पर कमेटियों एवं आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर एक नए पुलिस एक्ट की ड्राफ्टिंग करें। इसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस सुधारों को केंद्र और राज्य सरकारें तत्काल लागू करें किंतु आज तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हुआ। वर्ष 1861 में बने पुलिस अधिनियम के मुताबिक ही देश में पुलिस आज भी काम कर रही है। वर्ष 1861 में ब्रिटिश भारत में जिस पुलिस अधिनियम का गठन हुआ था उसका उद्देश्य अपराधमुक्त समाज की स्थापना करना नहीं, बल्कि उसका तत्कालिक कारण 1857 का विद्रोह था।

आजादी के बाद हमने औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था को अंगीकार कर लिया जो आम जनता के लिए या समाज को अपराधविहीन बनाने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि शासन के सुचारू संचालन के लिए थी। ऐसी पुलिस से निष्पक्ष, पारदर्शी व दबावमुक्त कार्यशैली की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? ऐसी पुलिस तो सत्ता की ही नुमाइंदगी करती है। मौजूदा दौर में पुलिस अतिशय राजनीतिक दबाव में है। यहां तक कि विभागीय काम-काज पर भी राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है। अधिकांश राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के चलते पुलिस प्रशासन में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। आम आदमी के दिमाग में पुलिस की छवि सिर्फ नेताओं को हिफाजत देने वाले की बन गई है। ऐसी स्थिति में पुलिस स्वायत्तता पर गौर करना आवश्यक है।

भारतीय पुलिस स्वतंत्रता के संदर्भ में हमें पश्चिमी देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जहां पुलिस तंत्र को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं जनसहयोगी बनाने पर विशेष बल दिया गया है और उसके अनुरूप सुधार भी किए गए हैं। वहां की पुलिस का स्वरूप ऐसा बनाया गया है कि शासन प्रशासन में पर्याप्त दखल रखने वाले भी पुलिस के कार्यों से घबराते हैं। यही कारण है कि वहां की पुलिस राजनीतिक एवं नौकरशाही के दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। हमारे यहां स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। यदि 1861 के पुलिस अधिनियम में प्रभावी बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सात सूत्रीय निर्देशों का पालन किया जाए तो निश्चय ही पुलिस व्यवस्था में सुधार आ सकता है। हालांकि कुछ राज्यों ने नए अधिनियम के तहत पुलिस को संचालित करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र और गुजरात में 1951 का बंबई पुलिस अधिनियम लागू है। कर्नाटक में 1963 में और दिल्ली में 1978 में नया पुलिस अधिनियम बनाकर पुलिस को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद भी नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही निकला है।

यह सही है कि कानून व्यवस्था राज्य सूची में होने के कारण ज्यादातर पुलिस राज्य सरकारों के अधीन होती हैं और राज्यों में पुलिस व्यवस्था पर पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव होता है। राज्य में जैसी सरकार होगी वैसी उसकी पुलिस भी होगी। पुलिस की अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती। सवाल है कि राज्य सरकारें यदि पुलिस को अपना नौकर मानकर उसे अपनी जरूरतों के मुताबिक संचालित करेंगी तो भला मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना कैसे सार्थक होगी?

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राष्ट्रीय संस्करण
शनिवार 10 अगस्त 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

सेल का मुनाफा 81 फीसद गिरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2019) में 81.39 फीसद गिरकर 102.68 करोड़ रुपये रह गया। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की परिचालन आय भी घटकर 14,820.89 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 15,907.53 करोड़ रुपये थी। कंपनी के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में कई कारणों से स्टील की घरेलू मांग कमजोर रही।

देश के विकास में अगले एक दशक में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। अभी 27 फीसद भारतीय महिलाएं ही रोजगार क्षेत्र में हैं, जबकि वैश्विक औसत 48 फीसद का है।
— अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
37,327.36	11,109.65	₹ 38,330	₹ 44,010	₹ 70.78	$ 58.70
254.55	77.20	₹ 140	₹ 390	₹ 0.09	

बदहाली ▸ दूसरी तिमाही में 8-14 दिन उत्पादन बंद करेगी महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति ने भी की कटौती

उत्पादन में बड़ी कटौती की ओर ऑटो सेक्टर

कई कंपोनेंट कंपनियां भी कर रहीं उत्पादन में कटौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : मंदी की मार से बेबस घरेलू ऑटो कंपनियां अब उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी अवधि के लिए उत्पादन में कटौती को मजबूर हो रही हैं। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने उत्पादन में बड़ी कटौती की बात कही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को बताया कि कंपनी चालू तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) में अपने विभिन्न संयंत्रों में 8-14 दिन के लिए उत्पादन बंद करेगी। कंपनी उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बैठाने के लिए कंपनी यह कदम उठा रही है। कई ऑटो कंपोनेंट कंपनियों ने भी उत्पादन में कटौती की बात कही है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई महिंद्रा व्हीकल्स मैन्यूफैक्चरर्स लि. के विभिन्न संयंत्रों में उत्पादन बंद करेगी। कंपनी ने उत्पादन स्थगित करने की घोषणा ऐसे समय की है, जबकि उद्योग बिक्री में गिरावट के सबसे लंबे दौर से गुजर रहा है। इस वर्ष अप्रैल-जुलाई के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू वाहन बिक्री आठ फीसद घटकर 1,61,604 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 1,75,329 इकाई थी। इस अवधि में निर्यात सहित कंपनी की कुल बिक्री भी घटकर 1,71,831 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 1,87,299 इकाई थी।

टाटा मोटर्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाहरी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, जिससे मांग में कमी आई है। हमने अपने उत्पादन में वास्तविक मांग के हिसाब से बदलाव किया है। इसके अलावा हमने उत्पादन की जरूरतों के हिसाब से काम की शिफ्ट और अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या में भी समायोजन किया है।

इसी सप्ताह देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भी कहा था कि उसने जुलाई में भी उत्पादन घटाया, जो उत्पादन कटौती का लगातार छठा महीना रहा।

बिक्री में गिरावट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है ऑटो सेक्टर। फाइल

जीएसटी घटाने की मांग पर ऑटो उद्योग एकमत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संगठन सियाम ने स्पष्ट किया है कि पूरा ऑटो उद्योग जीएसटी की दर को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करने की मांग पर एकमत है। संगठन ने अपने एक बयान में कहा है कि पूरा उद्योग मानता है कि आज के हालात में जीएसटी की दर में कमी करना बेहद जरूरी है। इस बात की मांग ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ साथ दोपहिया वाहनों के लिए ओरिजिनल कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स (ओईएम) भी इसकी मांग कर रहे हैं। सियाम के प्रेसिडेंट राजन वढेरा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में इसी मुद्दे पर जोर दिया था।

ऑटो उद्योग की सलाह पर विभिन्न चरणों में चलेगा ई-मोबिलिटी मिशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि सरकार ई मोबिलिटी मिशन ऑटो उद्योग के फीडबैक पर चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। उन्होंने नीतिगत मसलों पर ऑटो उद्योग को पूरी मदद देने का भरोसा दिया और ताकि ऑटो उद्योग मौजूदा व्यवस्था से इलेक्ट्रिक वाहनों के दौर में सहजता से प्रवेश कर सके। हाल ही में ऑटो उद्योग के प्रतिनिधियों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात हुई थी। बैठक में ऑटो उद्योग ने न केवल राहत पैकेज की मांग की थी बल्कि सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अपनी रफ्तार को भी धीमा करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री ने भी उद्योग को भरोसा दिया था कि इस दिशा में सरकार विचार करेगी। गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने भी ऑटो उद्योग की परेशानियों को पिछले दिनों लगातार प्रकाशित किया था। तीसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मेघवाल ने कहा कि अब तक फेम स्कीम के तहत तीन लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है। इसके अतिरिक्त साल 2019-20 के बजट में इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का रोडमैप और विजन तैयार करने के संबंध में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के रूप में एक दस्तावेज तैयार किया है। इसके तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की भारत में मैन्यूफैक्चरिंग का भी खाका खींचा गया है।

जून में आइआइपी में मात्र दो फीसद की बढ़ोतरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

औद्योगिक क्षेत्र में सुस्ती का संकेत देते हुए औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस साल जून में घटकर मात्र दो फीसद रह गई है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि का यह स्तर चार माह में न्यूनतम है। इस गिरावट की वजह मैन्यूफैक्चरिंग और खनन का खराब प्रदर्शन है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में पिछले साल जून में सात फीसद वृद्धि दर्ज की गई थी। इससे पूर्व आइआइपी का न्यूनतम स्तर इस साल फरवरी में 0.2 फीसद था। इसके बाद आइआइपी में थोड़ा उछाल आया और मार्च में यह 2.7 फीसद के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद अप्रैल में यह बढ़ते हुए 4.3 फीसद और मई में 4.6 फीसद पर पहुंचा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3.6 फीसद वृद्धि हुई है जबकि एक साल पहले इसमें 5.1 फीसद वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार सुस्त पड़ने की एक वजह मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की धीमी वृद्धि है। इस साल जून में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में मात्र 1.2 फीसद वृद्धि हुई है, जबकि पिछले साल जून में यह 6.9 फीसद थी। निवेश का बैरोमीटर माने जाने वाले कैपिटल गुड्स क्षेत्र में इस वर्ष जून के दौरान उत्पादन में 6.5 फीसद की कमी आई है, जबकि पिछले साल जून में इसमें 9.7 फीसद की वृद्धि हुई थी। इसी तरह खनन क्षेत्र की वृद्धि दर भी पिछले साल की 6.5 फीसद से घटकर इस साल 1.6 फीसद रह गई है। बिजली उत्पादन में इस साल जून में 8.2 फीसद की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले साल भी इसमें 8.5 फीसद वृद्धि हुई थी। अगर उपयोग के आधार पर देखें तो इस साल जून में प्राइमरी गुड्स में 0.5 और इंटरमीडिएट गुड्स में 12.4 फीसद की वृद्धि हुई है जबकि कंस्ट्रक्शन गुड्स में 1.8 फीसद गिरावट आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 5.5 फीसद गिरावट रही है, तो कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स में 7.8 फीसद वृद्धि हुई है।

एक और महत्वपूर्ण आंकड़े में सुस्ती। फाइल

▸ चार माह के न्यूनतम स्तर पर आई आइआइपी वृद्धि दर

▸ पहली तिमाही के उत्पादन में भी दर्ज की गई गिरावट

न्यूज गैलरी

वीडियोकॉन ग्रुप की 13 कंपनियां सुनवाई में संयुक्त

मुंबई : अपनी तरह के पहले फैसले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने वीडियोकॉन ग्रुप की 15 में से 13 कंपनियों को सुनवाई के लिए संयुक्त करने को कहा है। हालांकि भारतीय इन्सॉल्वेंसी कानून में किसी ग्रुप की विभिन्न कंपनियों को इकट्ठा करने की परंपरा नहीं के बराबर रही है, लेकिन एनसीएलटी की मुंबई खंडपीठ ने ब्रिटेन और अमेरिका के दिवालिया कानूनों की तर्ज पर यह फैसला दिया है। खंडपीठ के जज ने कहा कि इन 13 कंपनियों की प्रकृति एक जैसी है और उनके अकाउंट्स भी आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में कंपनियों का बेहतरीन मूल्य हासिल करने के लिए इन्हें इकट्ठा करना ही अच्छा कदम साबित होगा। (प्रेट्र)

केयर ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग घटाई

नई दिल्ली : क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग घटाकर नकारात्मक आउटलुक के साथ 'केयर ए' कर दी है। एक बयान में एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में और गिरावट आई है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा कि दोनों विलय के बाद वोडाफोन आइडिया ने परिचालन में तारतम्यता के लिहाज से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। (प्रेट्र)

यूको बैंक का घाटा घटा

नई दिल्ली : सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता यूको बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2019) में 601.45 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक को 633.88 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। शेयर बाजारों को दी जानकारी में बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में उसका सकल फंसा कर्ज (एनपीए) थोड़ा घटकर 24.85 फीसद पर आ गया। (प्रेट्र)

सूचीबद्ध सिक्युरिटीज में ही निवेश करें म्यूचुअल फंड

नई दिल्ली : म्यूचुअल फंड्स के हितों की रक्षा करने और जोखिम वाले क्षेत्रों में निवेश घटाने के उद्देश्य से सेबी चाहता है कि ये फंड कंपनियां केवल सूचीबद्ध सिक्युरिटीज में ही निवेश करें। पूंजी बाजार नियामक चाहता है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां धीरे-धीरे अपना सारा निवेश सूचीबद्ध हो चुकी या होने को तैयार इक्विटी और डेट उपकरणों में हस्तांतरित कर लें। (प्रेट्र)

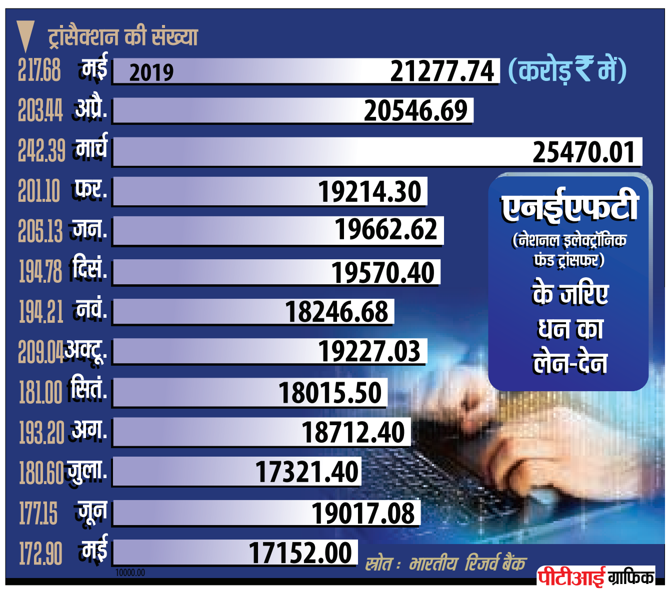

स्टार्ट-अप को सीबीडीटी से बड़ी राहत

नई दिल्ली : एंजल टैक्स की चिंता में घुल रही स्टार्ट-अप कंपनियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि जो कंपनियां टैक्स के सीमित सवालों के जवाब दे देंगी, उनके जवाब मोटे तौर पर स्वीकार कर लिए जाएंगे और उनसे उसके बाद कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।

वित्त मंत्री से एफपीआइ पर सरचार्ज हटाने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने सरकार से मांग की है कि चालू वित्त वर्ष के आम बजट में पर जो सरचार्ज लगाया गया था, उसे वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की खातिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की समीक्षा करने की मांग भी की।

सूत्रों के मुताबिक सीतारमण ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों की बात धैर्यपूर्वक सुनी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस बीच शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन सोमवार को इस उम्मीद में ऊपर चढ़ा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से सरकार शायद बाजार के अनुकूल उपायों की घोषणा कर सकती है। अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश को बढ़ावा देने के इरादे से वित्त मंत्री पिछले कई दिनों से अलग-अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही हैं। इसी सिलसिले में एफपीआइ के साथ बैठक बुलाई गई। अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों से मंदी की आहट आ रही है। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि आम बजट पेश होने के बाद से एफपीआइ ने घरेलू इक्विटी और डेट बाजारों से लगातार बिकवाली की है।

ये सुझाव दिए गए : सूत्रों का कहना है कि बैठक में विभिन्न पक्षों ने कर्मचारी भविष्य निधि फंड (ईपीएफ) द्वारा स्टॉक मार्केट में किए जाने वाले निवेश की सीमा बढ़ाने का सुझाव भी दिया, ताकि इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़े। इसके अलावा लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को घटाने या समाप्त करने की मांग भी की। इसी तरह दो करोड़ रुपये से अधिक आय पर बढ़ाया गया सरचार्ज एफपीआइ पर लागू नहीं होना चाहिए। सरकार के सरचार्ज संबंधी फैसले से बाजार पर असर पड़ा है। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने कारोबार की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए एफपीआइ के केवाइसी नियमों में ढिलाई देने की मांग की। साथ ही मसाला बांड्स पर विथहोल्डिंग टैक्स को खत्म करने की मांग भी की। बैठक में गोल्डमैन सैक्श, नौमुरा, ब्लैकरॉक सीएलएसए, बार्कलेज और जेपी मॉर्गन ने भाग लिया। बैठक के बाद एनएसई के सीईओ और एमडी विक्रम लिमये ने कहा कि मंत्री ने सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनी।

जारी है भरोसा बढ़ाने का सिलसिला। एएनआइ

▸ कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान उठाई यह मांग

▸ वित्त मंत्री ने सबकी सुनी, मगर ठोस आश्वासन किसी को नहीं दिया

कॉरपोरेट पर टैक्स घटाने का सरकार का इरादा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का इरादा कारपोरेट पर टैक्स घटाने का है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी रूप में उद्योग के लिए कठिनाई पैदा नहीं करना चाहती। उद्योग संगठन सीआइआइ की नेशनल काउंसिल के सत्र को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार का इरादा कॉरपोरेट पर टैक्स कम करने का है। इसमें कोई दो-राय नहीं है। टैक्स राजस्व में वृद्धि होने पर सरकार सभी कंपनियों के लिए 25 फीसद टैक्स पर विचार करेगी। टैक्स की प्रक्रिया सरल बनाने और करदाताओं की परेशानी कम करने के मुद्दे पर सीतारमण ने कहा कि हम टैक्स की प्रक्रिया सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

छह साल बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में गिरावट

लंदन, प्रेट्र : ब्रेक्जिट से संबंधित अनिश्चितताओं में कारोबारी निवेश प्रभावित होने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इस साल की दूसरी तिमाही में गिरावट दर्ज गई। छह साल बाद ब्रिटेन में ऐसा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। अधिकांश अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के स्थिर रहने का अनुमान लगा रहे थे। ऐसे में गिरावट को अप्रत्याशित माना जा रहा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि यह गिरावट ऐसे समय दर्ज हुई है जब ब्रेक्जिट की समय-सीमा को लेकर अनिश्चितता बढ़ी हुई है। इस साल के मार्च में ही ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाना था। हालांकि यूरोपीय संघ के साथ हुए करार को संसद द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब यह अक्टूबर में प्रस्तावित है।

ब्रेक्जिट की समय-सीमा टालने के निवेदन से पहले कंपनियों ने भंडार बढ़ाने पर जोर दिया था। इसके कारण पहली तिमाही की जीडीपी में 0.5 फीसद की वृद्धि हुई। हालांकि बाद में जब कंपनियों ने भंडार जमा करना बंद किया तो इसका असर वृद्धि दर पर दिखा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पिछले साह कहा था कि ब्रेक्जिट सुगमता से होने के बाद भी ब्रिटेन अगले वर्ष की शुरुआत में मंदी की चपेट में आ सकता है।

बिल्डर के दिवालिया होने पर भी नहीं डूबेगी घर खरीदारों की पूरी रकम

नई दिल्ली, प्रेट्र : घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) में संशोधन वाले कानून को सही ठहराते हुए घर खरीदारों को वित्तीय कर्जदाता का मिला दर्जा बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करती या होती है, तो उसकी संपत्ति की नीलामी से हासिल रकम में घर खरीददारों को भी हिस्सा मिलेगा।

आइबीसी में संशोधन कायम रहने से मकान ग्राहकों को भी कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी वित्तीय कर्जदाता के बराबर का दर्जा बरकरार रहेगा। यानी घर खरीदने वालों की अहमियत बिल्डर को लोन देने वाले बैंकों के बराबर होगी। इस कानून के खिलाफ 180 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जहां कहीं भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा और आइबीसी की किन्हीं धाराओं में आपसी विवाद की स्थिति पैदा होगी, वहां आइबीसी के नियम मान्य होंगे।

अब यह होगा : अब मकान खरीदारों को प्रोजेक्ट पूरा न होने की स्थिति में राहत मिलेगी। ऐसे मामलों में उन्हें दिए गए बैंकों के बराबर अधिकार बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद घर खरीदार भी किसी बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की मांग कर सकते हैं। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन ने कहा कि इस संशोधन से मकान ग्राहकों को एक और प्लेटफॉर्म मिला है, जहां वे रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ अपनी मुश्किलें रख सकते हैं। हालांकि बेंच ने कहा कि केवल वास्तविक खरीदार ही बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की मांग कर सकता है।

सरकार को निर्देश : सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को भी सुधार के उपायों पर एक हलफनामा दायर करने को कहा है। सरकार को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' और अपील ट्रिब्यूनल की खाली पद जल्द भरे, ताकि काम सही ढंग से हो सके।

कई कंपनियों में फंसा है पैसा : देशभर में कई रियल एस्टेट कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को मकान देने का वादा तो किया, लेकिन बीच राह में हाथ खड़े कर दिए। ऐसी कंपनियां खुद को नुकसान में बताकर दिवालिया घोषित हो गईं। ऐसी स्थिति में कंपनियों और उनके मालिकों की संपत्तियां जब्त की जाती हैं। पहले जब्त की गई संपत्ति का पूरा पैसा बैंकों को मिलता था, लेकिन अब घर खरीदने वाले लोगों को भी इसमें से हिस्सा दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के ग्राहकों को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने आम्रपाली मामले में फैसला सुनाया है कि अब एनबीसीसी घर बनाकर देगी।

फाइल फोटो

▸ सुप्रीम कोर्ट ने आइबीसी में संशोधन को रखा बरकरार

▸ इस बारे में रियल एस्टेट कंपनियों की याचिका खारिज

फिसलन के बाद भी सोना 38 हजार के ऊपर

नई दिल्ली, प्रेट्र : लगातार दो कारोबारी सत्रों में तेज उछाल के बाद शुक्रवार को सोने में मामूली नरमी देखी गई। इसके बाद भी वह 38 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बंद रहने में कामयाब रहा। चांदी में भी थोड़ी नरमी आई और उसका भाव भी 290 रुपये प्रति किलोग्राम गिर गया। कारोबार के आखिर में सोने का भाव 38,330 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 44,010 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर था। दूसरी तरफ, विदेशी बाजारों में सोना 1,500 डॉलर प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर पहुंच गया।

सराफा कारोबारियों का कहना था कि दो दिनों की जबर्दस्त बढ़त के बाद निवेशकों का सोने-चांदी में निवेश के प्रति थोड़ा सुस्त रुख रखना स्वाभाविक था। वहीं, शेयर बाजारों में दिख रहे सुधार के चलते भी निवेशक सोना-चांदी में निवेश के जोखिम से थोड़ा दूर रहे। इसी वजह से चांदी को भी सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाइयों का भरपूर साथ नहीं मिल पाया।

140 रुपये गिरकर 38,330 रुपये रह गया प्रति 10 ग्राम सोने का भाव

290 रुपये की गिरावट के बाद चांदी 44,010 रुपये प्रति किलोग्राम पर

न्यूयॉर्क में सोने का भाव उछाल के साथ 1,504.40 डॉलर, जबकि चांदी का भाव 17.12 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर पहुंच गया। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 38,330 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 38,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा।

सोने की आठ ग्राम गिन्नी का भाव 28,500 रुपये के पिछले स्तर पर बरकरार रहा। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 665 रुपये टूटकर 43,065 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। चांदी के सिक्कों का भाव प्रति सैकड़ा 1,000 रुपये चढ़कर 88,000 रुपये खरीद और 89,000 रुपये बिक्री पर पहुंच गया।

आस

वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए हरसंभव प्रयास की बात कही, सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल, दोनों साप्ताहिक बढ़त के साथ हुए बंद

शेयर बाजार ने जताया वादों पर भरोसा

मुंबई, प्रेट्र : केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सभी कदम उठाने के आश्वासनों पर निवेशकों ने भरोसा जताया। सरकार के रुख पर सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में शुक्रवार को बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स 254.55 अंक यानी 0.68 फीसद चढ़कर 37,581.91 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला निफ्टी भी शुक्रवार को 77.20 अंकों यानी 0.70 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 11,109.65 अंक पर स्थिर हुआ। इस पूरे सप्ताह में सेंसेक्स ने 463.69 अंकों और निफ्टी ने 112.30 अंकों की बढ़त ली।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआइ) से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने ऑटो सेक्टर के दिग्गजों की चिंताएं सुनी थीं। सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह एफपीआर पर इस वर्ष बजट में लगाए गए उच्च सरचार्ज पर पुनर्विचार कर सकती है। सीतारमण के अलावा वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उद्योग जगत के विभिन्न हिस्सों से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर उनका भरोसा बहाल किया जाए। कारोबारियों का कहना था कि इन सभी कवायदों से निवेशकों में शेयर बाजार के प्रति रुझान लौटा है।

सेंसेक्स पैक में शुक्रवार को सबसे ज्यादा बढ़त मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, वेदांता, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में दर्ज की गई। दूसरी तरफ यस बैंक के शेयर 7.91 फीसद गिर गए। टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आइटीसी व सन फार्मा के शेयरों में भी 2.50 फीसद तक की गिरावट देखी गई। सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में बीएसई ऑटो, फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंकेक्स, रियल्टी व एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि मेटल, टेक, टेलीकॉम, आइटी व पावर सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट देखी गई। एशिया के अन्य बाजारों का रुख मिला-जुला रहा।

दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बाजार अभी अनिश्चितता के भंवर में दिख सकता है। हालांकि सरकार द्वारा उठाए सुधारवादी कदमों का असर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर से दिखना शुरू हो जाएगा।

निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार एफपीआइ पर लगाया सरचार्ज वापस ले लेगी। प्रतीकात्मक

कारोबारियों को कर अपील में बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, कानपुर : आयकर आयुक्त अपील का निर्णय करदाता के पक्ष में होने पर अफसर तभी अपील कर सकेंगे, जब विवादित राशि 50 लाख रुपये या उससे अधिक होगी। इससे कम होने पर अफसर अब अपील नहीं कर सकेंगे। अभी तक यह सीमा 20 लाख रुपये थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सीबीडीटी के इस निर्णय से कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें फैसले के बाद फिर विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं, विभाग में अपील के लंबित मामले कम होंगे। इसी तरह अधिकरण का निर्णय करदाता के पक्ष में होने पर आयकर अधिकारी उच्च न्यायालय में तभी अपील कर सकेंगे जब विवादित राशि एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। अभी यह सीमा 50 लाख रुपये थी। इसी तरह अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकेंगे जब विवादित राशि दो करोड़ रुपये या अधिक होगी। यह राशि अब तक एक करोड़ रुपये थी। आयकरदाताओं के खिलाफ टैक्स की राशि विवादित होने की बड़ी संख्या में अपील मामले अपीलीय प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।

रत्न-आभूषणों का निर्यात 8.48 फीसद घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश का रत्न एवं आभूषण निर्यात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि में 8.48 फीसद गिरकर 9.7 अरब डॉलर (करीब 86,000 करोड़ रुपये) मूल्य का रह गया। विकसित बाजारों में सुस्ती से निर्यात पर असर पड़ा।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेइपीसी) के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल-जून अवधि में 10.6 अरब डॉलर के रत्न और आभूषणों का निर्यात किया गया था। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, श्रम आधारित क्षेत्र है। इसकी देश के कुल निर्यात में करीब 15 फीसद हिस्सेदारी है। तराशे एवं पॉलिश हीरों, रंगीन रत्न और स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में सुस्ती से देश का रत्न एवं आभूषण निर्यात प्रभावित रहा।

आंकड़ों के मुताबिक, तराशे एवं पॉलिश हीरों के निर्यात में 17.5 फीसद की गिरावट रही। इसी प्रकार, रंगीन रत्नों के निर्यात में 10 फीसद की गिरावट आई। अप्रैल-जुलाई में सोने के आभूषणों का निर्यात 4.8 फीसद गिरकर चार अरब डॉलर रहा। हालांकि सोने के सिक्कों और पदकों का निर्यात बढ़कर 30.9 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया।

▸ अप्रैल-जून तिमाही में 9.7 अरब डॉलर का रहा निर्यात

▸ देश के कुल निर्यात में सेक्टर की रही है 15 फीसद हिस्सेदारी

अमेरिका को सर्वाधिक निर्यात

भारत मुख्यत: अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन को रत्न एवं आभूषणों का निर्यात करता है। निर्यात में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी एक-चौथाई है। पिछले वित्त वर्ष में रत्न एवं आभूषण निर्यात 5.32 फीसद गिरकर 30.96 अरब डॉलर रहा था।

4 लोगों की मौत हो गई अमेरिका के दो शहरों में हुई चाकूबाजी के दौरान। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने सबसे पहले गार्डन ग्रोव स्थित अपने अपार्टमेंट परिसर में बनी छह दुकानों को लूटा और दो लोगों को चाकू से मार दिया। उसके बाद वह पास के सांता अना शहर में गया और वहां उसने एक सुरक्षा गार्ड समेत दो लोगों की हत्या कर दी।

अमेरिका ने चीनी शासन को बताया ठग

बड़ा मामला ▶ चीन ने अमेरिकी राजनयिकों को दी थी हांगकांग के मामले में दखल नहीं देने की चेतावनी

राजनयिक की तस्वीरें और उनके बच्चों के नाम लीक करना अस्वीकार्य : अमेरिका

वाशिंगटन, एएनआइ

हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। अमेरिकी राजनयिकों को हांगकांग के आंतरिक मामले में दखल नहीं देने की चीन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने चीन को ठग शासन करार दिया है।

अमेरिका की यह तीखी प्रतिक्रिया हांगकांग के स्थानीय मीडिया में प्रकाशित उन खबरों के बाद आई है जिनमें बताया गया था कि हांगकांग में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी ने हाल में लोकतंत्र समर्थक समूह से मुलाकात की थी। हांगकांग के एक अखबार में अमेरिकी राजनयिक की लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की एक तस्वीर भी प्रकाशित हुई है। इस खबर पर चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिका से कहा था कि वह हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को गलत संदेश देना बंद कर दे। इसके साथ ही उन खबरों पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, जिनमें बताया गया था कि अमेरिकी अधिकारी हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के संपर्क में हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ऑर्टागस ने शुक्रवार को कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी राजनयिक की निजी सूचना, तस्वीरें और उनके बच्चों के नाम लीक करना औपचारिक विरोध है। ऐसा कोई ठग शासन ही करेगा। कोई जिम्मेदार देश इस तरह का बर्ताव नहीं करेगा। यह अस्वीकार्य है।'

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजनयिक सिर्फ हांगकांग या चीन में ही नहीं बल्कि हर देश में वहां के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। इसलिए हमारे राजनयिक सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। बता दें कि हांगकांग में बीते जून माह से चीन शासन और प्रस्तावित प्रत्यर्पण बिल के विरोध में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि, बीते दिनों हांगकांग की कार्यकारी नेता कैरी लैम ने विवादास्पद प्रस्तावित कानून को वापस लेने की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। लेकिन हांगकांग में उसके बाद भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है।

इस कानून के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति चीन में अपराध करके हांगकांग में शरण लेता है तो उसे जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चीन भेज दिया जाएगा। हांगकांग सरकार इस मौजूदा कानून में संशोधन के लिए फरवरी में प्रस्ताव लाई थी।

हांगकांग में शुक्रवार को प्रस्तावित प्रत्यर्पण बिल के विरोध में लोकतंत्र समर्थकों ने स्थानीय एयरपोर्ट पर जोरदार प्रदर्शन किया। रायटर

हांगकांग में आर्थिक मंदी का खतरा

▶ दो महीने से छिड़े आंदोलन से अराजक स्थिति, चीन की प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों को चेताया

हांगकांग, एएफपी : हांगकांग में चीन सरकार की प्रतिनिधि कैरी लैम ने लोकतंत्र समर्थकों को चेताया है कि उनके आंदोलन से इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इससे आने वाले दिनों में आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने हिंसक प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए किसी तरह की रियायत या सुविधा देने से इन्कार कर दिया है।

शुक्रवार को दुनिया के प्रमुख आर्थिक केंद्र हांगकांग के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हजारों आंदोलनकारियों का धरना शुरू हो गया। आंदोलनकारी धरने के जरिये अपनी बात अंतरराष्ट्रीय जगत तक पहुंचाना चाहते हैं और उसका समर्थन चाहते हैं। इस बीच कैरी लैम ने हांगकांग के उद्योगपतियों के साथ बैठक कर आर्थिक नुकसान पर चर्चा की है और हालात को सुधारने के लिए उनसे सुझाव लिए हैं। हांगकांग में दो महीने पुराने इस आंदोलन की शुरुआत कैरी लैम के चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि के समर्थन के बाद हुई। इसके तहत हांगकांग में दर्ज मुकदमों की सुनवाई चीन की अदालतों में करने का प्रस्ताव था। संधि के विरोध में लोगों का गुस्सा देख हांगकांग में चीन का प्रतिनिधि प्रशासन तो पीछे हट गया लेकिन आंदोलन शांत नहीं हुआ। एकजुट आंदोलनकारी लोकतंत्र की मांग पर उतर आए। इसी के बाद से हांगकांग की सड़कों पर आंदोलन जारी है। आंदोलन का समाज के सभी वर्ग और सरकारी कर्मचारी भी समर्थन कर चुके हैं।

कैरी लैम एपी

कैरी लैम ने आंदोलन से पैदा हुई स्थिति को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि 2003 में छिड़े आंदोलन से ज्यादा गंभीर स्थितियां इस बार पैदा हुई हैं। इस आंदोलन से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लंबे समय में हो पाएगी। इस दौरान हांगकांग आने वाले विदेशियों की संख्या में हाल के हफ्तों में भारी कमी देखी गई है।

मरयम नवाज 21 अगस्त तक एनएबी की हिरासत में

मरयम नवाज एपी

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम नवाज को 21 अगस्त तक राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया है। देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था एनएबी ने विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की उपाध्यक्ष मरयम को गुरुवार को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह इसी जेल में बंद अपने पिता से मिलकर लौट रही थीं। नवाज शरीफ भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं।

एनएबी ने शुक्रवार को 45 वर्षीय मरयम को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड की मांग की। अदालत ने हालांकि 12 दिनों की रिमांड स्वीकृत की। इसी मामले में मरयम के चचेरे भाई यूसुफ अब्बास को भी इतने ही दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। चौधरी चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में शरीफ परिवार के कई सदस्य आरोपित हैं। इसी मामले में आरोपित शरीफ परिवार के एक अन्य सदस्य अब्दुल अजीज की गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी ने शहबाज शरीफ के घर पर भी छापेमारी की।

न्यूज गैलरी

तूफान की आशंका से चीन में रेड अलर्ट

शंघाई : चीन के पूर्वी तट से तूफान लेकिमा के टकराने की आशंका को देखते हुए देश के मौसम विभाग ने शुक्रवार को रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान के चीन के झेजियांग प्रांत से शनिवार तड़के टकराने की संभावना जताई गई है। इस तूफान की चपेट में पूरा शंघाई शहर आ सकता है। लेकिमा के लेकर पड़ोसी ताइवान में भी अलर्ट जारी किया गया है और हवाई यात्रा के अलावा स्कूल भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। (रायटर)

आंधी से ऑस्ट्रेलिया में जान-माल का नुकसान, उड़ानें रद

सिडनी : तेज आंधी से ऑस्ट्रेलिया में शुक्रवार को जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार से चली हवा के कारण विक्टोरिया प्रांत में एक कार पर पेड़ के गिर जाने से उसमें सवार महिला की मौत हो गई। सिडनी और मेलबर्न से उड़ान भरने वाली 60 से अधिक उड़ानें रद कर दी गई हैं। आंधी की वजह से देश के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यह हाल सप्ताह के अंत तक रहने की संभावना है। (रायटर)

काठमांडू जा रही बस नदी में गिरी, पांच की मौत

काठमांडू : नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रही एक सवारी बस के नदी में गिर जाने से शुक्रवार को पांच लोगों की मौत हो गई। राहत व बचाव कार्य में लगे सुरक्षाकर्मियों ने 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। दुर्घटना के शिकार 24 लोग अभी भी लापता हैं। धदिंग जिले के पुलिस प्रमुख राज कुमार बैदवार ने बताया कि बाकी लोगों की तलाश जारी है। 50 सवारियों से भरी बस बेनीघाट इलाके में नदी में जा गिरी। (प्रेट्र)

दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा ने जीता मुकदमा

जोहांसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने अपने खिलाफ लोक अभियोजक बुसिसीवे ख्वेबाने द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार का मुकदमा जीत लिया है। राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार रोधी संस्था द्वारा लगाए गए आरोप पर निर्णय सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में रामफोसा ने कुछ भी गलत नहीं किया। अदालत का यह निर्णय लोक अभियोजक ख्वेबाने की हाल में हुई तीसरी बड़ी पराजय है। (रायटर)

रूस ने फ्रीज किए विपक्षी नेता के बैंक खाते

मॉस्को : रूस ने विपक्षी नेता एलेक्सेई नवलनी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। अधिकारियों ने यह कार्रवाई नवलनी के खिलाफ चल रही मनी लांड्रिंग की जांच को लेकर की। फ्रीज किए गए खातों में नवलनी द्वारा स्थापित भ्रष्टाचार रोधी संस्था से जुड़े बैंक खाते भी शामिल हैं। सरकार का विरोध करने पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले नवलनी अभी भी जेल में बंद हैं। (रायटर)

1971 युद्ध के बाद इंदिरा को समझाकर वापस ले ली थी अपनी जमीन : जरदारी

▶ कश्मीर पर बुलाए संयुक्त सत्र में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का दावा

▶ कहा- शिमला में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुई थी वार्ता

इस्लामाबाद, एएनआइ : भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध के बाद अपने कब्जे वाली पाकिस्तान की जमीन को लेकर बातचीत की थी। इसके बाद उसे जमीन वापस मिली थी। बुधवार को कश्मीर मुद्दे पर बुलाए गए संयुक्त सत्र के दौरान यह दावा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया है।

डॉन न्यूज ने जरदारी के हवाले से कहा, 'हमें यह महसूस करना चाहिए कि 1971 के युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कैसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) का गठन कश्मीर के लिए किया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बातचीत के बाद (पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री) इंदिरा से कब्जाई जमीन वापस ले ली थी।' उन्होंने कहा, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पर स्वतंत्रता मिलने के बाद शिमला में भुट्टो ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। शिखर सम्मेलन के दौरान शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और भारत ने सभी युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) को रिहा कर दिया था। पीपीपी के नेता ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जे को रद करने का भारत का निर्णय पूर्वी पाकिस्तान की त्रासदी के समान ही गंभीर है।

उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद की दूसरी बड़ी घटना है। इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए जरदारी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि भारत को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए लोकतंत्र है। क्या उन्हें हमारी खस्ताहाल आर्थिक हालत के बारे में पता नहीं है।

नीदरलैंड्स में गर्मी से गई 400 की जान

एम्सटर्डम, रायटर : यूरोपीय देश नीदरलैंड्स में भीषण गर्मी के चलते दो हफ्तों में करीब 400 लोगों की जान चली गई। गत 22 जुलाई से देश गर्मी के प्रकोप का सामना कर रहा है। देश की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार, इस साल 22 जुलाई से अब तक 2964 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह हर साल इस अवधि में होने वाली औसत मौतों से 15 फीसद अधिक है। माना जा रहा कि गर्मी के कारण ही मरने वालों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है।

जुलाई के अंत में नीदरलैंड्स ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप अत्यधिक गर्मी और गर्म हवाओं की चपेट में था। इस साल गर्मी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 25 जुलाई को नीदरलैंड्स के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। 1.7 करोड़ की आबादी वाले देश में जुलाई सबसे गर्म माह होता है। इसके बावजूद आमतौर पर जुलाई में तापमान औसतन 13 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। इस साल गर्मी से मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 80 या उससे अधिक है। सबसे ज्यादा मौतें देश के पूर्वी हिस्से में हुईं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी और धरती के गर्म होने से भविष्य में गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा।

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने शाह रुख को दी डॉक्टरेट की मानद उपाधि

मेलबर्न, प्रेट्र : बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान को ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित लॉ ट्रोब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी ने भारतीय फिल्म उद्योग जगत में अतुलनीय योगदान और मीर फाउंडेशन के जरिये वंचित बच्चों की मदद व महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में शाह रुख के काम की सराहना करते हुए यह उपाधि प्रदान की। शाह रुख को यूनिवर्सिटी ऑफ इडेनबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर भी मानद उपाधियों से सम्मानित कर चुकी हैं।

दसवें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए शाह रुख यहां पहुंचे थे। इसी बीच शुक्रवार को एक कार्यक्रम में लॉ ट्रोब यूनिवर्सिटी के चांसलर और विक्टोरिया प्रांत के पूर्व प्रमुख जॉन ब्रंपी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने पर शाह रुख ने कहा, 'इस वक्त समाज में गुस्से और नफरत का माहौल है। ऐसे में प्रेम और सहानुभूति के लिए किए गए काम को सम्मान मिलना इस बात का सुबूत है कि विश्व में मानवता अब भी जिंदा है।' यूनिवर्सिटी ने शाह रुख के नाम पर एक रिसर्च स्कॉलरशिप की भी घोषणा की है। चार साल की यह स्कॉलरशिप स्वास्थ्य, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में शोध करने वाली भारतीय महिलाओं को दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप के लाभार्थी को दो लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 96 लाख रुपये) दिए जाएंगे।

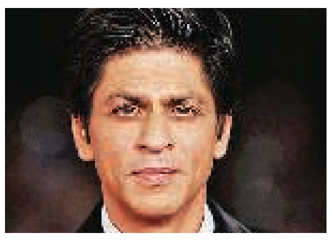

शाह रुख खान। फाइल

▶ महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में काम के लिए मिला सम्मान

▶ शाह रुख के नाम पर एक रिसर्च स्कॉलरशिप भी देगी लॉ ट्रोब यूनिवर्सिटी

एक्सिलेंस इन सिनेमा अवार्ड से नवाजा

मेलबर्न, प्रेट्र : अभिनेता शाह रुख खान को मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल (आइएफएफएम) के 10वें संस्करण में गुरुवार को 'एक्सिलेंस इन सिनेमा' अवार्ड से नवाजा गया। शाह रुख इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। उन्हें यह अवार्ड सिनेमा और भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान के लिए दिया गया। इस दौरान 53 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि करीब 40 वर्षों की उम्र तक उन्होंने हमेशा वास्तविक फिल्मों से ज्यादा इसके निर्माण प्रक्रिया को महत्व दिया। हालांकि, कई बार यह गलत साबित हुआ। आइएफएफएम-2019 अवार्ड समारोह में श्रीराम राघवन की अंधाधुन ने दो पुरस्कारों के साथ दबदबा कायम किया। तब्बू को बेस्ट एक्ट्रेस व राघवन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड तेलुगु फिल्म सुपर डिलक्स के लिए अभिनेता विजय सेतुपति को मिला।

समाचारों के लिए लाखों डॉलर की पेशकश कर रहा एफबी

▶ 'न्यूज टैब' की शुरुआत पर कर रहा काम साइट पर समाचार सामग्री प्रकाशन के लिए देगा हर साल 30 लाख डॉलर

सैन फ्रांसिस्को, एपी : समाचारों की दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाने की कवायद में जुटे फेसबुक ने प्रकाशकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक ने अपनी साइट पर समाचारों के प्रकाशन के लिए प्रकाशकों को लाखों डॉलर की पेशकश की है। घाटे में चल रहा मीडिया उद्योग फेसबुक पर ऑनलाइन विज्ञापनों में एकाधिकार का वर्षों से आरोप लगाता रहा है। माना जा रहा है कि इसी क्रम में फेसबुक ने नया कदम उठाया है।

वाल स्ट्रीट जनरल की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक के प्रतिनिधियों ने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि वे समाचार, हेडलाइन व अन्य सामग्री के प्रकाशन की अनुमति देने के लिए हर साल 30 लाख डॉलर (21.26 करोड़ रुपये) तक दे सकते हैं। हालांकि, फेसबुक ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि कंपनी अपनी सेवाओं के लिए 'न्यूज टैब' की शुरुआत पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि इसी साल अप्रैल में फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी सेवाओं में 'न्यूज सेक्शन' पर बात की शुरुआत की थी।

इस मामले के एक जानकार ने वाल स्ट्रीट जरनल की स्टोरियों के प्रकाशन की अनुमति के लिए फेसबुक की तरफ से न्यूज कॉर्प को संपर्क किए जाने की पुष्टि की है। हालांकि, जनरल की रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि फेसबुक ने 30 लाख डॉलर की पेशकश किसी प्रकाशन विशेष के लिए की है या समस्त मीडिया संगठनों के लिए। उल्लेखनीय है कि मीडिया उद्योग लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि फेसबुक व गूगल उसकी सामग्री का मुफ्त इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिये मीडिया उद्योग के राजस्व को गटक जाते हैं।

सोशल मीडिया की प्रमुख वेबसाइट है एफबी।

हिजबुल्ला के मददगार को पांच साल की जेल 350 करोड़ जुर्माना

वाशिंगटन, एएफपी : लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्ला की वित्तीय मदद करने वाले एक कारोबारी को अमेरिका में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। न्याय विभाग के अनुसार, कासिम तजीदीन (63) पर पांच करोड़ डॉलर (करीब 350 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है। लेबनान और अफ्रीका में बिजनेस नेटवर्क चलाने वाले कासिम को मार्च, 2017 में प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया था।

हिजबुल्ला को लाखों डॉलर की वित्तीय मदद देने के लिए मई, 2009 में अमेरिकी कोषागार विभाग ने कासिम को वैश्विक आतंकी घोषित किया था। उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे जिसके तहत वह अमेरिकी कंपनियों या नागरिकों के साथ किसी तरह का कारोबार या लेन-देन नहीं कर सकता था, लेकिन उसने इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। सहायक अटार्नी जनरल ब्रायन बेंजकोव्सिकी ने कहा, 'कासिम को सुनाई गई सजा हिजबुल्ला के सफाये के लिए की जा रही कोशिशों का नमूना है।' सीरिया के गृहयुद्ध में राष्ट्रपति बशर-अल-असद का समर्थन करने वाले हिजबुल्ला को अमेरिका ने 1997 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था।

नागासाकी ने की परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की मांग

नागासाकी, आइएएनएस : जापानी शहर नागासाकी ने शुक्रवार को परमाणु हमले की 74वीं बरसी मनाई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शहर के मेयर ने दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की मांग की। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नौ अगस्त, 1945 को अमेरिका ने इस शहर पर 'फैट मैन' परमाणु बम गिराया था, जिससे करीब 74 हजार लोगों की जान चली गई थी। इससे तीन दिन पहले अमेरिका ने एक अन्य जापानी शहर हिरोशिमा पर भी परमाणु बम गिराया था।

स्थानीय पीस पार्क में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मेयर तोमिहीसा टाउ ने कहा, परमाणु हथियारों पर पाबंदी का काम जल्द- से-जल्द पूरा होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा लाई गई परमाणु प्रतिबंध संधि पर अभी तक 50 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे यह लक्ष्य अधूरा है। जापान भी इन्हीं 50 देशों में शामिल है। इस कार्यक्रम में जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो के अलावा संयुक्त राष्ट्र (यूएन), यूरोपीय संघ और परमाणु संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। पीएम एबी ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार परमाणु शक्ति संपन्न देश और अन्य देशों के बीच मध्यस्थता का काम करेगी ताकि परमाणु हथियारों का प्रसार रोका जा सके। एबी ने हालांकि परमाणु संधि को लेकर कुछ नहीं कहा।

जापान के नागासाकी में शुक्रवार को शहर पर अमेरिकी परमाणु बम हमले की 74वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान अपने परिजन को याद कर एक महिला रो पड़ी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नौ अगस्त, 1945 को अमेरिका ने यहां 'फैट मैन' परमाणु बम गिराया था। रायटर

आयोजन

हाउस ऑफ कॉमंस के सभागार में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू

ब्रिटिश संसद परिसर में गूंजे गीता के श्लोक

बिजेंद्र बंसल, लंदन : यूनाइटेड किंगडम (यूके) के हाउस ऑफ कॉमंस परिसर स्थित सभागार में भगवत गीता के श्लोकोच्चारण व शंखनाद के बीच तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में यूके की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के वाइस चेयरमैन पॉल स्कल्ली और विशेष अतिथि हरियाणा के उद्योगमंत्री विपुल गोयल मौजूद थे।

इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि गीता शांति और सद्भाव की प्रेरणा देने वाला धर्म और कर्म ग्रंथ है। अहं और महत्वाकांक्षा के त्याग में शांति और सद्भाव है। गीता केवल हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ ही नहीं है बल्कि यह विश्व के सभी धर्म-संप्रदाय के लोगों के लिए है। गीता जीवन शास्त्र को समझने वाला ग्रंथ है। कर्तव्य पथ से कोई विचलित न हो यह संदेश भगवत गीता से मिलता है। महोत्सव का आयोजन हरियाणा सरकार, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हिंदू काउंसिल यूके, इंडो, ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप सहित जीयो गीता के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

महोत्सव की शुरुआत में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि से हुआ। उपस्थित लोगों ने एक मिनट का मौन रखकर शोक जताया। उद्योगमंत्री विपुल गोयल और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, हरियाणा के राज्यपाल के सचिव विजय दहिया ने यूके के हाउस ऑफ कॉमंस परिसर में श्रद्धापूर्वक स्थापित करने के लिए यूके के संसद सदस्य वीरेंद्र शर्मा को भागवत गीता की प्रति सौंपी। कार्यक्रम में लंदन साउथ ऑल से एमपी नरेंद्र शर्मा, स्वामी धर्म देव जी महाराज, भारतीय उच्चायुक्त रूचि घनश्याम, बांग्लादेश की राजदूत सइदा मुना तसनीम, मारीशस के राजदूत गिरीश नानक, बाबा भूपेंद्र सिंह, नेपाल के राजदूत दुर्गा बहादुर समेत हरियाणा के कई अधिकारी भी मौजूद थे।

लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमंस परिसर में स्थापित करने के लिए साउथ ऑल के एमपी वीरेंद्र शर्मा को भगवद गीता सौंपते गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरियाणा के उद्योगमंत्री विपुल गोयल व अन्य। जागरण

अमेरिका में विमान हादसा भारतीय चिकित्सक दंपती और बेटी की मौत

विलो ग्रोव, एपी : अमेरिका के फिलाडेल्फिया इलाके में गुरुवार सुबह हुए हादसे में एक छोटे विमान में सवार भारतीय मूल जसवीर खुराना (60), उनकी पत्नी दिव्या (54) और बेटी किरण मौत के शिकार हो गए। विमान में यही तीन लोग सवार थे और वह कुछ ही देर पहले कोलंबस (ओहियो) जाने के लिए फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से उड़ा था।

जसवीर खुराना टेंपल यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी और लेबोरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर थे। जबकि पत्नी दिव्या ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर थीं। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है और न ही अन्य बड़ा नुकसान हुआ है। विमान पेड़ों से टकराता हुआ जमीन पर आ गिरा और उसमें आग लग गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया हैकि हादसे से पहले विमान से कोई आपात संदेश भी नहीं मिला जिससे पता चलता उसमें अचानक कोई तकनीक खराबी पैदा हुई थी। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।

दहशत भरा है तालिबान का ईद का संदेश : अफगान सरकार

▶ तालिबान सरगना ने संदेश में कहा, ईद पर लोग मुल्क की सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान

काबुल, आइएएनएस : ईद के मौके पर आए तालिबान के संदेश को अफगानिस्तान की सरकार ने युद्ध, आतंक और दहशत से भरा करार दिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने कहा, दुर्भाग्य से तालिबान अब भी युद्ध, आतंक और दहशत का संदेश दे रहा है। वह तबाही और नागरिकों की हत्या की मूल जड़ है।

सिद्दीकी ने गुरुवार को कहा कि अफगान लोग चाहते हैं कि तालिबान युद्ध और विनाश बंद कर दे। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों से विश्वासघात ना करे। इससे पहले तालिबान के सरगना मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा ने ईद के मौके पर अपने संदेश में कहा था, 'मेरी आप लोगों को हिदायत है कि आप ईद के दौरान अपने मुल्क की सुरक्षा, मदद और सुविधा का पूरा ध्यान रखें।

अपनी भलाई और हमवतनों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। शहीदों और कैदियों के परिवारों से मिलें और अपनी क्षमताओं के अनुसार उनकी सहायता करें।' तालिबान सरगना के इस बयान से एक दिन पहले बुधवार को काबुल के एक पुलिस स्टेशन के बाहर विस्फोटकों से भरी कार से आत्मघाती हमला किया गया था। इसमें 18 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी। मुल्ला हैबतुल्ला ने अपने संदेश में अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता पर भी संदेह जाहिर किया है।

बता दें कि अमेरिका और तालिबान के बीच गत वर्ष के आखिर से दोहा में शांति के लिए बातचीत चल रही है। इसके बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। इस वार्ता में तालिबान के विरोध के चलते अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया है। अफगानिस्तान में इस समय करीब 20 हजार विदेशी सैनिक तैनात हैं।

लॉर्ड्स की पिच गेंदबाजों के लिए मुफीद होगी। इंग्लैंड वापसी करना चाहेगी, लेकिन स्मिथ को आउट करना उनके लिए चुनौती होगी। — जोश हेजलवुड, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

लॉर्ड्स हंडरेड टीम के कोच बने शेन वार्न

लंदन, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वार्न को लॉर्ड्स स्थिति लंदन की टीम का कोच नियुक्त किया गया जो अगले साल द हंडरेड टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के पहले सत्र में वार्न राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और कोच दोनों थे। उस सत्र राजस्थान आइपीएल का खिताब जीतने में सफल रही थी। वार्न ने कहा कि मैं द हंडरेड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली लॉर्ड्स स्थिति लंदन टीम का कोच बन गर्व और सम्मान महसूस कर रहा हूं।

डोप का डंक ▶ इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में विदेशी खिलाड़ी आने से कर सकते हैं इन्कार, बढ़ी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें

नाडा के नियंत्रण से भारतीय क्रिकेट जगत परेशान

वेस्टइंडीज में मौजूद भारतीय टीम के खिलाड़ी भी हैरान

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के नेतृत्व काम कर रहे बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी और बीसीसीआइ के जीएम (क्रिकेट ऑपरेशंस) सबा करीम के खेल मंत्रालय के सामने घुटने टेकने से बीसीसीआइ के पदाधिकारी ही नहीं बल्कि अधिकारी भी नाराज हैं। भारतीय क्रिकेट पर नाडा के नियंत्रण ने भारतीय क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। वेस्टइंडीज में मौजूद भारतीय टीम में इस फैसले से हलचल मच गई है।

जौहरी और सबा के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को लिखित में आश्वासन देने के बाद अब यह एजेंसी भारतीय सरजमीं पर होने वाले टूर्नामेंट में डोप टेस्ट कर सकती है। बीसीसीआइ के एक पदाधिकारी ने कहा कि बोर्ड के ये दोनों अधिकारी क्या करके आएं हैं ये इनको पता ही नहीं है। हम इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) जैसे बड़ी लीग का आयोजन करते हैं जो घरेलू टूर्नामेंट के दायरे में आता है। आइपीएल में देश के साथ-साथ न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सहित कई देशों के क्रिकेटर खेलते हैं। आइपीएल हमारा घरेलू टूर्नामेंट है और ऐसे में नाडा को इन विदेशी क्रिकेटरों के भी डोप टेस्ट लेने का अधिकार होगा। ऐसे में वे क्रिकेटर आइपीएल में खेलने से इन्कार कर सकते हैं। जौहरी और सबा पृथ्वी शॉ के डोप टेस्ट मामले को भी सही तरह से हैंडल नहीं कर पाए और जिसका खामियाजा अब भारतीय क्रिकेट को भुगतना होगा।

नाडा के अंतर्गत आने के मायने

● **घरेलू टूर्नामेंट (दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अन्य आयु वर्ग टूर्नामेंट)**

–हां नाडा इन टूर्नामेंट में जाकर क्रिकेटरों के डोप नमूने ले सकती है। अगर विराट कोहली, रिषभ पंत, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, शिखर धवन जैसे बड़े नाम इस टूर्नामेंट में खेलते हैं तो नाडा के पास उनके टेस्ट लेने के अधिकार हैं।

● **आइसीसी के टूर्नामेंट (भारत में होने वाली 2021 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 में होने वाला विश्व कप)**

– नाडा यहां खुद टेस्ट नहीं ले सकती है। यह आइसीसी पर निर्भर होगा कि वह या तो आइडीटीएम या नाडा को सैंपल लेने के लिए निमंत्रण भेजे।

● **अब आगे क्या होगा?**

– बीसीसीआइ को अब अपने संविधान में डोपिंग धारा को भी जोड़ना होगा। नाडा को क्रिकेटरों का टेस्ट लेने की इजाजत देनी होगी। ऐसे ही आइपीएल संविधान में भी संशोधन करना होगा।

● **द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज (भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच देश में होनी है सीरीज)**

– नाडा खुद नहीं जा सकती और टेस्ट नहीं ले सकती क्योंकि यह सीरीज आइसीसी के भविष्य टूर प्रोग्राम का हिस्सा है और यह आइसीसी इवेंट है। ऐसे में विश्व संस्था यहां अंतरराष्ट्रीय डोप टेस्ट और मैनेजमेंट (आइडीटीएम) को सैंपल लेने भेज सकती है। अगर आइसीसी को खुद लगता है कि नाडा को क्रिकेटरों का टेस्ट लेना चाहिए, तब ही देश की संस्था इस मामले को देख सकती है। इस स्थिति में आइसीसी बीसीसीआइ से कहेगा और भारतीय बोर्ड नाडा को टेस्ट लेने के लिए निमंत्रण देगा। एक अन्य स्थिति भी हो सकती है। वाडा खुद आइसीसी को कह सकता है कि वह आइडीटीएम की जगह नाडा को सैंपल लेने की स्वीकृति दे। वाडा आइसीसी से सामंजस्य बैठाकर काम कर सकता है। इससे पहले जब बीसीसीसीइ वाडा के अंतर्गत नहीं आता था, तो विश्व संस्था को नाडा से टेस्ट कराने में मुश्किल आती थी।

● **इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे विदेशी खिलाड़ियों का क्या?**

हां, नाडा इन खिलाड़ियों का टेस्ट ले सकती है। ऐसे में आइपीएल की विभिन्न फ्रेंचाइजियों से जुड़े खिलाड़ी जब खेलने आएंगे तो उन्हें यह बात दिमाग में रखनी होगी कि नाडा टूर्नामेंट के दौरान या टूर्नामेंट के बाहर उनका टेस्ट ले सकती है। वह टेस्ट देने से इन्कार नहीं कर सकते हैं।

● **आइपीएल में अब क्या होगा**

–नाडा यहां जा सकती है और सैंपल ले सकती है। बीसीसीआइ के प्राइवेट और घरेलू टूर्नामेंट में नाडा के पास टेस्ट लेने के अधिकार हैं। नाडा के पास भारतीय और विदेशी क्रिकेटरों के टेस्ट लेने के अधिकार रहेगा।

● **व्हेयर एबॉउट का क्या होगा?**

– घरेलू क्रिकेट में क्रिकेटरों को अपनी जानकारी नाडा से साझा करनी होगी, जिससे नाडा के डोप कंट्रोल अधिकारी उनका टूर्नामेंट के दौरान और बाद में टेस्ट ले सकेंगे। आइसीसी प्रतियोगिताएं और द्विपक्षीय सीरीज में क्रिकेटरों को यह जानकारी साझा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आइसीसी नाडा की नियुक्ति ना करे।

● **एनएसएफ और आरटीआइ का क्या?**

अभी बीसीसीआइ एनएसएफ और आरटीआइ के अंतर्गत नहीं आया है। भविष्य में भी अगर मंत्रालय ने विदेशी टीम को भारत में खेलने की इजाजत नहीं दी तो बीसीसीआइ के लिए झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।

जहां चाहेंगे जब चाहेंगे टेस्ट ले सकेंगे : जुलानिया

नई दिल्ली : भारत के खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया ने शुक्रवार को कहा कि बीसीसीआइ नाडा के अंतर्गत आने के लिए तैयार हो गया है। अब सभी क्रिकेटरों का नाडा टेस्ट ले सकेगा। जुलानिया ने कहा कि स्वीडन की डोप टेस्टिंग मैनेजमेंट (आइडीटीएम) संस्था एक बाहरी एजेंसी है जिसे बीसीसीआइ ने सैंपल लेने के लिए नियुक्त किया था। अब यह एजेंसी नाडा होगी। मैंने बीसीसीआइ को विस्तार से बताया कि आप कानून से अलग नहीं हो सकते हैं। कानून सभी के लिए समान हैं। सभी खेल संघ एक कानून के अंतर्गत हैं। आपको एक करार पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। हम उन्हें बारी-बारी से बताते रहे हैं, इसके लिए एमओयू की जरूरत नहीं है, कानून सभी पर लागू होते हैं। डोपिंग की व्हेयर एबॉउट धारा पर खेल सचिव ने कहा कि हां, नाडा जब चाहेगी और जहां चाहेगी टेस्ट ले सकती है। विश्व डोपिंग रोधी संस्था (वाडा) की धारा 5.2 नाडा को यह इजाजत देती है कि वह अपनी धरती पर कभी भी अपने खिलाड़ियों का टेस्ट ले सकती है। भारतीय मूल के सभी खिलाड़ी और जिनके पास भारत की नागरिकता है। सभी नाडा के कानून के अंतर्गत आते हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के डोपिंग प्रोग्राम को लेकर काफी आलोचना की थी। वाडा के मुताबिक सिर्फ डोपिंग रोधी संस्था जिनके पास टेस्ट की स्वीकृति है, वहीं एथलीटों का टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन जब से बीसीसीआइ ने नाडा के साथ हाथ नहीं मिलाए थे, तो खेल मंत्रालय लगातार बीसीसीआइ से कहता रहा कि उन्हें डोप टेस्ट लेने का अधिकार नहीं है।

भारतीय कप्तान विराट कोहली। फाइल फोटो

नया बीसीसीआइ नहीं मानेगा नाडा

नई दिल्ली : हालिया घटनाक्रम से बीसीसीआइ के पदाधिकारी नाराज हैं और कुछ ने कहा कि यह फैसला सरकार के दबाव में लिया गया है। इसे बोर्ड अपनी स्वायत्तता का अधिकार खो देगा। एक वरिष्ठ बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा कि सीईओ राहुल जौहरी या सीओए को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस तरह का नीतिगत फैसला लें। बोर्ड के तीनों पदाधिकारियों अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को भी इस बारे में नहीं बताया गया। यह नीतिगत फैसला है और बीसीसीआइ की आम सभा से इसकी अनुमति नहीं ली गई इसलिए चुनाव के बाद जैसे ही नया बीसीसीआइ आएगा वह इस फैसले को पलटने का अधिकार रखता है।

बोर्ड के पदाधिकारी ने कहा कि सीओए और सीईओ को बीसीसीआइ चलाना नहीं आता है। इन लोगों ने देश के क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। बीसीसीआइ की वर्किंग कमेटी के एक पूर्व सदस्य ने कहा कि जिस तरह से युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का डोप मामला संभाला गया उससे बीसीसीआइ का संकट बढ़ गया। शॉ का अप्रैल में लिया गया टेस्ट फेल हो गया था, जिसके बाद वह आइपीएल में खेलते और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अभ्यास करते हुए देखा गया था। नाडा को दूर रखने के लिए आपका खुद का सिस्टम मजबूत होना चाहिए लेकिन इन लोगों ने हद ही कर दी। हमने देखा कि शॉ को डोप टेस्ट में फेल होने के बावजूद आइपीएल में खेलने की इजाजत दी गई और जब सब कुछ कागजों में था तो वह राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की सुविधाएं ले रहा था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सीईओ ने खुद की गलतियों को छिपाने के लिए सरकार को खुद पर हावी होने का मौका दिया। यह फैसला सीओए के क्षेत्र में नहीं आता था। यह फैसला बोर्ड के चुनाव के बाद आम सभा को लेना चाहिए था।

सुरेश रैना की हुई घुटने की सर्जरी

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के घुटने का ऑपरेशन शुक्रवार को नीदरलैंड्स के एम्सटर्डम में हुआ। डाक्टरों की मानें तो रैना चार से छह सप्ताह तक मैदान से दूर रहेंगे। रैना फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं लेकिन उनके उत्तर प्रदेश की तरफ से घरेलू क्रिकेट में खेलने की उम्मीद है।

रैना का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर वान डेर होएवन ने बताया कि भारतीय क्रिकेटर के घुटने की सर्जरी हुई है। वह कुछ महीनों से बायें घुटने में दर्द महसूस कर रहे थे। सर्जरी सफल रही है और रैना को पूरी तरह से ठीक होने में चार से छह सप्ताह का समय लगेगा। रैना ने दैनिक जागरण से कहा कि वह पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और सितंबर के अंत में मैदान पर उतरेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह पूरे घरेलू सत्र में बाहर रहेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। वह इस घरेलू सत्र में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

हालांकि उनकी सर्जरी का मतलब यह है कि वह आगामी घरेलू सत्र के कुछ मुकाबले नहीं खेल सकेंगे। बीसीसीआइ ने हाल ही में 2019-20 का घरेलू टूर्नामेंट का कैलेंडर जारी किया था। दलीप ट्रॉफी में सुरेश रैना को जगह नहीं मिली है, लेकिन वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 24 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में उनके विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश से खेलने की संभावना है। अगर समय पर पूरी तरह रीहैब नहीं होता है तो कुछ मुकाबले के बाद वह उतर सकते हैं। वहीं टी-20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी आठ नवंबर से लेकर एक दिसंबर तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में भी रैना खेल सकेंगे। रैना ने अपना पिछला मुकाबला आइपीएल फाइनल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला 12 मई को हैदराबाद में खेला था। रैना के नाम 222 वनडे में 35.31 के औसत से 5615 रन हैं, जिसमें पांच शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं।

सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बने शुभमन

त्रिनिनाद, एएनआइ : टीम इंडिया इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है जहां विराट कोहली की अगुआई में टीम का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया-ए भी वेस्टइंडीज के दौरे पर है। इंडिया-ए के खिलाड़ी भी यहां पर वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ कमाल कर रहे हैं। इंडिया-ए की तरफ से वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ अंतिम अनाधिकारिक टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया। शुभमन अपने इस दोहरे शतक की वजह से कैरेबियाई धरती पर वो कमाल कर गए जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने उनसे पहले नहीं किया था। इसके अलावा शुभमन ने पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

वेस्टइंडीज दौरे के लिए ऐसा माना जा रहा था कि शुभमन को भारतीय टीम में मौका दिया जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ। अब उन्होंने अपनी इस पारी के जरिये भारतीय चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया है। शुभमन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीरसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में 248 गेंदों पर नाबाद 204 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 19 चौके व दो छक्के जड़े। इस दोहरे शतक के बाद शुभमन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए।

उपलब्धि

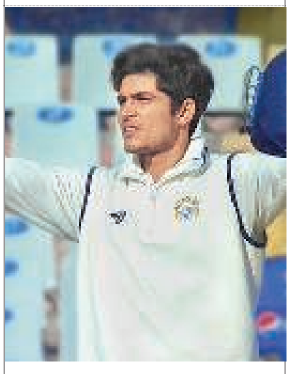

- 19 साल 334 दिन की उम्र में जड़ा दोहरा शतक
- 17 साल तक कायम रहा गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ा

शुभमन ने 19 साल 334 दिन की उम्र में दोहरा शतक लगाया और उन्होंने गंभीर को पीछे छोड़ दिया है। गंभीर ने 20 वर्ष 124 दिन की उम्र में जिंबाब्वे के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था। शुभमन ने 17 साल बाद गंभीर का यह रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा शुभमन भारत के बाहर विदेशी जमीन पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। कैरेबियाई धरती पर भी वह सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। गिल की यह पारी ऐतिहासिक रही। उन्होंने इस मैच की दूसरी पारी में हनुमा विहारी के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 315 रनों की अटूट साझेदारी भी की। हनुमा ने भी इस मैच में शतक लगाया और 221 गेंदों पर नाबाद 118 रन बनाए। विहारी ने अपनी पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया। हालांकि इस मैच की पहली पारी में शुभमन पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे।

शुभमन और हनुमा की पारियों और उनके बीच की साझेदारी की बदौलत इंडिया-ए ने दूसरी पारी चार विकेट पर 365 रन बनाकर घोषित की। दोनों के बीच साझेदारी उस समय शुरू हुई थी जब इंडिया-ए ने चार विकेट सिर्फ 50 रन पर गंवा दिए थे। इंडिया-ए की पहली पारी 201 रनों पर सिमटी थी, जिसके बाद वेस्टइंडीज-ए अपनी पहली पारी में सिर्फ 194 रन बनाकर ढेर हो गई। इंडिया-ए को पहली पारी के आधार पर सात रन की बढ़त मिली। 373 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज-ए ने मैच के चौथे और अंतिम दिन खबर लिखे जाने तक एक विकेट पर 113 रन बना लिए थे। जेरेमी सोलोजानो 52 और ब्रैंडन किंग 33 रन बनाकर नाबाद थे।

बारिश के कारण खेल रुकना सबसे खराब : कोहली

क्रिकेट डायरी

जॉर्जटाउन (गयाना), प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ बारिश के कारण रद हुए पहले वनडे मैच के बाद काफी निराश नजर आए। भारत और वेस्टइंडीज की टीमों के बीच गुरुवार को प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया पहला वनडे मैच बारिश के कारण रद कर दिया गया। कोहली ने मैच के बाद कहा कि यह शायद क्रिकेट का सबसे खराब हिस्सा है। ऐसे बारिश से बीच-बीच में खेल रुकना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है या तो पूरी तरह बारिश हो जाए या फिर पूरा खेल खेला जाए। जितनी बार खेल ऐसे रोककर शुरू किया जाता है, उतनी बार आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं खिलाड़ी चोटिल ना हो जाए।

तीन मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मैच था जो 13 ओवर ही चल सका और भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच में तीन बार बारिश ने खलल डाली और फिर मैच को आखिरकार रद ही करना पड़ा। कप्तान कोहली ने कहा कि वेस्टइंडीज की कुछ पिचें आपको अच्छे से टेस्ट करेंगी। कुछ पिचों पर अच्छा गति और उछाल होगा और कुछ धीमी होंगी, आपको धैर्य से काम लेना होगा।

डरबन हीट के कोच बने गैरी कर्स्टन

डरबन, एएफपी : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन मजांसी सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए डरबन हीट के मुख्य कोच बन गए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि 51 वर्षीय कर्स्टन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन सकते हैं, लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका के क्लब के साथ जुड़ गए। इंग्लैंड के मौजूदा मुख्य कोच ट्रेवर बेलिस सितंबर में अपने पद से इस्तीफा देंगे। कर्स्टन 2008 से 2011 के बीच भारतीय टीम के मुख्य कोच रहे थे। उनके मार्गदर्शन में ही भारत ने अपने घर पर 2011 में हुए विश्व कप का खिताब जीता था। आइपीएल में भी कर्स्टन दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर के लिए मुख्य कोच के रूप में काम कर चुके हैं। कर्स्टन नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के टी-20 फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच का पद संभालेंगे।

नाइटराइडर्स समूह के कोचिंग स्टाफ में शामिल होंगे मैकुलम

नई दिल्ली, आइएएनएस : न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) की टीम त्रिनिबागो नाइटराइडर्स के मुख्य कोच बनेंगे। वहीं, मैकुलम इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) की दो बार की विजेता कोलकाता नाइटराइडर्स के सहायक कोच की भी जिम्मेदारी निभाएंगे। इन दोनों फ्रेंचाइजियों में भारत के मशहूर अभिनेता शाह रुख खान का मालिकाना हक है। दोनों टीमें नाइटराइडर्स समूह के अंतर्गत आती हैं। मैकुलम को यूरो टी-20 स्लैम में हिस्सा लेना था, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही अपने फ्रीलांस क्रिकेटर के करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इसके पीछे वजह पांच सितंबर से शुरू हो रही सीपीएल है। कोलकाता की टीम ने हाल ही में बताया था कि वह अपने मुख्य कोच जैक कैलिस और सहायक कोच साइमन कैटिच से नाता तोड़ रही है। टीम ने मैकुलम को सहायक कोच नियुक्त किया है, लेकिन अपने मुख्य कोच को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं की है। मैकुलम आइपीएल के पहले सत्र में कोलकाता से खेले थे। उन्होंने आइपीएल के पहले ही मैच में कोलकाता की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर के खिलाफ 158 रनों की पारी खेली थी।

मिस्बाह हो सकते हैं पाकिस्तान के अगले कोच, हेसन भी दौड़ में

लाहौर, एएफपी : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक टीम के नए मुख्य कोच बन सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हाल में मुख्य कोच मिकी आर्थर के अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने जहां 45 वर्षीय मिस्बाह को मुख्य कोच के रूप में पेश किया है वहीं एक अन्य प्रमुख समाचार पत्र द नेशन में प्रकाशित खबर के मुताबिक न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन भी इस पद की दौड़ में शामिल हैं। इंग्लैंड एवं वेल्स में समाप्त हुए विश्व कप में पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्तर से ही बाहर हो गई थी जिसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्य कोच समेत पूरे कोचिंग स्टाफ के करार को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। पीसीबी ने आर्थर के साथ-साथ कोचिंग स्टाफ के किसी भी व्यक्ति के अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। कोचिंग स्टाफ में गेंदबाजी कोच अजहर महमूद, बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर और ट्रेनर ग्रांट लूडेन शामिल हैं। मिस्बाह ने 75 टेस्ट और 162 वनडे मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की है। उन्होंने 2010 में हुए स्पॉट फिक्सिंग के बाद टीम को आगे बढ़ाया और कई सफलताएं दिलाई। दूसरी ओर, हेसन ने गुरुवार को ट्विटर पर इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) की टीम किंग्स इलेवन पंजाब के मुख्य कोच से पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। वह केवल एक सत्र ही पंजाब के कोच रहे और इस्तीफा देने के कारण उनके नाम को भी इस रेस में शामिल हो गया है। हेसन न्यूजीलैंड की टीम के कोच भी रह चुके हैं। बीसीसीआइ ने भी टीम के मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन मांगे हैं और साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अंतिम तीन उम्मीदवारों में कथित तौर पर हेसन का नाम भी शामिल है।

अमला को शुभकामनाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की जिसके बाद कई दिग्गजों ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। 36 वर्षीय अमला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 124 टेस्ट, 181 वनडे और 44 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 9282, 8113 और 1277 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनका नाबाद 311 सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इसके अलावा वनडे में 159 और टी-20 में नाबाद 97 रन सर्वश्रेष्ठ बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपका अविश्वसनीय करियर रहा हाशिम अमला। शुरुआत में आप पर सभी ने शक किया, लेकिन आपकी संघर्ष की भावना, विनम्रता और अविश्वसनीय प्रतिभा आपको शीर्ष पर ले गई और अंततः दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बना दिया। एक अद्भुत करियर के लिए बधाई। शोएब अख्तर ने कहा कि महान हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के साथ दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है।

मनमुटाव की खबरें चलती रहेंगी : सुनील

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का कहना है कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा अगर छत पर चढ़कर चिल्ला-चिल्लाकर भी कहें कि टीम और खिलाड़ियों के बीच कोई मनमुटाव नहीं तो भी यह कहानी खत्म नहीं होगी, यह जारी रहेगी। कप्तान कोहली ने वेस्टइंडीज के साथ सीरीज के लिए अमेरिका रवाना होने से पहले टीम में मतभेद की किसी भी तरह की खबरों से इनकार किया था।

गावसकर ने स्पोर्ट्स स्टार पर अपने कॉलम में लिखा, 'विराट और रोहित छत पर खड़े होकर चिल्ला-चिल्लाकर भी कह दें तो यह कहानी यहां खत्म नहीं होगी। जब भी रोहित सस्ते में आउट होंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि क्या वह जानबूझकर आउट हो गए। जो भी ऐसी बातें फैला रहा है, वह भारतीय क्रिकेट का शुभचिंतक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टीम का कोई परेशान खिलाड़ी अफवाहों को हवा देता है। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ऐसी खबरों में राजनीति भी करते हैं।' पूर्व कप्तान गावस्कर ने इस मामले में मीडिया की भूमिका पर भी अपने विचार दिए। उन्होंने कहा, 'मीडिया के लिए तो ऐसी खबरें मानो स्वर्ग जैसी होती हैं। जब क्रिकेट चलता है तो ऐसी कहानियां शांत हो जाती हैं और बाकी दिनों में फिर से ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं।' उन्होंने साथ ही कहा, 'विराट और रोहित दोनों पेशेवर क्रिकेटर हैं। दोनों मैदान पर उतरेंगे और टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए खेलेंगे लेकिन ऐसी कहानियां 20 साल बाद भी रुकने वाली नहीं हैं।'

टेनिस डायरी मोंट्रियल मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची विलियम्स व नाओमी, पिछले साल यूएस ओपन फाइनल के बाद दोनों की पहली भिड़ंत होगी

एक बार फिर सेरेना के सामने होंगी ओसाका

रिटर्न करती सेरेना विलियम्स ● प्रेट्र

मोंट्रियल, एएफपी : पिछले साल यूएस ओपन के फाइनल में भिड़ने वाली अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स और जापान की नाओमी ओसाका ने सीधे सेटों में अपने-अपने मुकाबले जीतकर डब्ल्यूटीए मोंट्रियल मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां एक बार फिर दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी। मौजूदा यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन ओसाका ने एक घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में पोलैंड की किशोरी इगा स्वियातेक को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी।

विश्व की 10वें नंबर की खिलाड़ी विलियम्स ने दो बार सर्विस गंवाने और पहले 10 मिनट में शुरुआती तीन गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए 91 मिनट तक चले मुकाबले में 48वीं रैंकिंग पर काबिज रूस की एकेटरीना एलेक्सांद्रोवा को 7-5, 6-4 से पराजित किया।

37 साल की सेरेना अब अपने 24वें सिंगल्स ग्रैंडस्लैम के लक्ष्य के साथ खेल रही हैं, जो वह आगामी यूएस ओपन में हासिल करना चाहेंगी। पिछले साल यूएस ओपन फाइनल के विवादास्पद समापन के बीच प्रशंसकों को ओसाका और सेरेना दोनों के बीच एक बार फिर रोमांचक भिड़ंत की उम्मीद है। उस मुकाबले में जापानी खिलाड़ी ने अपने बचपन की आदर्श सेरेना को लगातार सेटों में 6-2, 6-4 से हराकर खिताब जीता था और उसके बाद से इन दोनों की यह पहली भिड़ंत होगी। अगले सप्ताह फिर से नंबर एक रैंकिंग पर पहुंचने के करीब ओसाका के खिलाफ मैच को लेकर सेरेना ने कहा, 'चाहे कोई भी जीते, लेकिन यह एक अच्छा मैच होगा। दोनों खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही हैं। इसलिए मैं उनके लिए तैयार हूं।'

ओसाका को हालांकि फिर से नंबर एक बनने के लिए तीसरी वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा से टक्कर मिल रही है। प्लिस्कोवा ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और वह भी नंबर एक बन सकती हैं। प्लिस्कोवा ने एस्तोनिया की एनेट कोंटावित को 6-3, 7-5 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में अब प्लिस्कोवा का सामना कनाडा की उभरती हुई स्टार बियांका एंड्रेस्क्यू से होगा, जिन्होंने पांचवीं वरीयता प्राप्त हॉलैंड की किकी बर्टेंस को 6-1, 6-7, 6-4 से पराजित किया। हालांकि, 27 साल की प्लिस्कोवा को अगले सप्ताह जारी होने वाली रैंकिंग में नंबर एक बनने के लिए फाइनल तक पहुंचना होगा, नहीं तो यह स्थान अपने आप ही ओसाका को मिल जाएगा। फ्रेंच ओपन चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी हालांकि टूर्नामेंट से मंगलवार को बाहर हो जाने के साथ ही नंबर एक बनने की होड़ से बाहर हो गई हैं। गत चैंपियन और चौथी वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप ने रूस की स्वेतलाना कुज्नेत्सोवा को 6-2, 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला चेक गणराज्य की क्वालीफायर मारी बुजोकोवा से होगा, जिन्होंने लात्विया की येलेना ओस्तापेंको को 6-2, 6-2 से शिकस्त दी।

राफेल नडाल और रोजर फेडरर ● फाइल फोटो, एएफपी

एटीपी की राजनीति में मिलकर उतरेंगे नडाल और फेडरर

मोंट्रियल, एएफपी : दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी राफेल नडाल ने कहा है कि उन्होंने और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी रोजर फेडरर ने मिलकर एटीपी खिलाड़ियों की परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। फेडरर और नडाल को साथी खिलाड़ियों ने चुना है। रॉबिन हासे, जैमी मरे और सर्जेइ स्टाखोवस्की के इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त हुए थे। नडाल ने कहा, 'हमने मिलकर जाने का फैसला किया है। ना वह अकेले होंगे और ना ही मैं। हम मिलकर खेल की भलाई के लिए काम कर सकेंगे।' मालूम हो कि पिछले कुछ महीनों से कई मसलों पर विवाद देखे गए हैं जिनमें एटीपी परिषद अध्यक्ष नोवाक जोकोविक, नडाल और फेडरर की राय अलग-अलग रही।

राफेल नडाल ने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा

मोंट्रियल : नंबर दो टेनिस खिलाड़ी स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में जीत दर्ज करने के मामले में स्विस दिग्गज रोजर फेडरर से आगे निकल गए हैं। मोंट्रियल मास्टर्स में गुरुवार को पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त नडाल ने अर्जेंटीना के गुइडो पेला को 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ 33 वर्षीय नडाल ने अपनी 379वीं जीत हासिल की और मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में सबसे अधिक जीत दर्ज करने के स्विट्जरलैंड के फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नडाल का सामना इटली के फेबियो फोग्निनी से होगा। 18 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता नडाल अब 35वीं बार 1000 मास्टर्स का खिताब जीतने के करीब हैं।

पेला को हराकर नडाल क्वार्टर फाइनल में

मोंट्रियल, रायटर : गत चैंपियन राफेल नडाल ने अपनी जीत की लय कायम रखते हुए यहां अर्जेंटीना के गुइडो पेला को 6-3, 6-4 से हराकर मोंट्रियल मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पिछले साल इस टूर्नामेंट को चौथी बार जीतने वाले नडाल ने तेज हवाओं के बीच पेला की सर्विस को चार बार तोड़ा और जीत हासिल की। पिछले महीने विंबलडन में रोजर फेडरर के हाथों हारने के बाद नडाल पहली बार टेनिस कोट पर उतरे हैं। स्पेन के 33 वर्षीय नडाल ने इससे पहले अपने शुरुआती मुकाबले में इंग्लैंड के डेनियल इवांस पर जीत दर्ज की थी। नडाल का सामना अक सातवीं वरीयता प्राप्त इटली के फैबियो फोग्निनी से होगा, जिन्होंने फ्रांस के एड्रियान मैन्नारिनो को 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। इससे पहले ऑस्ट्रिया के दूसरी वरीय डोमिनिक थिएम ने क्रोएशिया के मारिन सिलिक को 7-6, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। थिएम का सामना अब रूस के आठवीं वरीयता प्राप्त डेनियल मेडवेदेव से होगा, जिन्होंने चिली के क्रिस्टियन गारिन को 6-3, 6-3 से मात दी। रूस के कारेन खचानोव भी जॉर्जिया के निकोलोज बासिलाशविली को 7-5, 5-7, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्पेन के रोबर्टो बतिस्टा ने फ्रांस के रिचर्ड गास्कट को 7-5, 7-5 से और फ्रांस के के गाएल मोंफिल्स ने हबर्ट हुरकाज को 6-4, 6-0 से शिकस्त दी।

जीत के बाद खुश ओसाका ● एएफपी

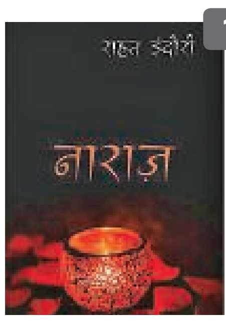

1 नाराज

लेखक : राहत इंदौरी
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस
राहत इंदौरी रंगों और रेखाओं के फनकार हैं। इस संग्रह में पाठकों का उनकी इस कला से परिचय होता है। राजनीतिक-सामाजिक विसंगतियों और कश्मकश पर उनका तंज पाठकों को सोचने पर विवश करता है। इस संग्रह में ऐसी शायरी की बहुतायत है।

2 दो कदम और सही

लेखक : राहत इंदौरी
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस
राजनीति और इश्क को अपनी शायरी का हिस्सा बनाने वाले राहत इंदौरी के इस संग्रह में जीवन और जगत के अलग-अलग पहलुओं को समेटा गया है। साथ ही बेबाकी से अपनी बात कहने की उनकी ताकत का अंदाजा भी होता है।

3 तुम मेरी जान हो रजिया बी

लेखक : पीयूष मिश्रा
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
अभिनेता-गीतकार पीयूष मिश्रा की इन कविताओं को एकाकीपन की कविताएं भी कहा जाता है। विपश्यना के दौरान पीयूष ने अपनी अब तक की जिंदगी पर नजर डाली तो उस अनुभव से ये कविताएं उपजीं। इनमें दर्शन भी है।

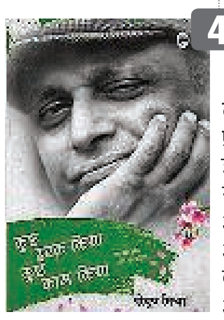

4 कुछ इश्क किया, कुछ काम किया

लेखक : पीयूष मिश्रा
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
इस संग्रह की कविताओं में पीयूष मिश्रा ने अपने सपनों, आकांक्षाओं, सफलता, असफलता और क्षोभ को वाणी दी है। अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले पीयूष की कविताएं भी पाठकों को अलग तरह का स्वाद देती है।

5 पाल ले इक रोग नादां

लेखक : गौतम राजऋषि
प्रकाशक : हिंद युग्म
हाल में जिन लेखकों ने अपनी रचनाओं से हिंदी जगत को चौंकाया है, उनमें गौतम का नाम प्रमुख है। उन्होंने अपनी गजलों में जिस तरह के बिंब प्रयोग में लाए हैं, वो रोचक हैं। जैसे-चांद सिगरेट पीता या धूप शॉवर में नहा रही होती।

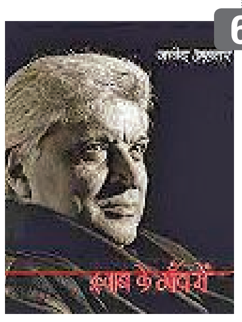

6 ख्वाब के गांव में

लेखक : जावेद अख्तर
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस
जावेद अख्तर के बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी की आपाधापी को फिल्म के सीन की तरह देखते और फिर उसे शब्दों में पिरो कर पेश करते हैं। इस किताब में गहराई से महसूस की गई उनकी अभिव्यक्तियां हैं।

7 चराग

लेखक : वसीम बरेलवी
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस
इस संग्रह में सिर्फ काल्पनिक दुनिया की बातें नहीं हैं बल्कि समकालीन समस्याओं और घटनाओं पर बारीक नजर रखते हुए उन्हें भी रचना में स्थान दिया गया है। आसान भाषा का इस्तेमाल कर वसीम बरेलवी अपनी शायरी को लोकप्रिय बनाते हैं।

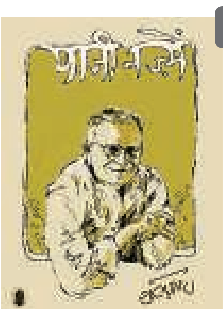

8 पाजी नज्में

लेखक : गुलजार
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
गुलजार की इन नज्मों में सीधे तौर पर तो सवाल नहीं हैं, लेकिन इनमें पाठकों को कवि की प्रश्नाकुलता दिखती है। इन नज्मों में गुस्सा भी है, हल्का तंज भी है। मंदिरों में तेल चढ़ाने को लेकर वह भक्तों पर तंज करते हैं।

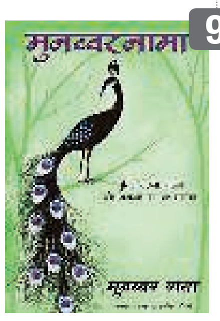

9 मुनव्वरनामा, चुनिंदा गजलें, नज्में और अशआर

लेखक : मुनव्वर राना
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस
मुनव्वर राना हमारे दौर के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित शायरों में हैं। यह उनकी चुनिंदा रचनाओं का संकलन है। इसमें इंसानी जज्बातों को बेहद सादगी और खूबसूरती के साथ गजल बनाकर पेश किया है।

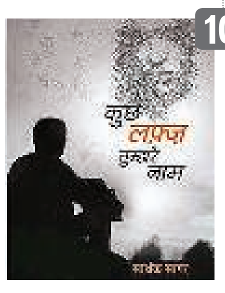

10 कुछ लफ्ज तुम्हारे नाम

लेखक : सार्थक सागर
प्रकाशक : हिंद युग्म
बिहार के मधुबनी में जन्मे और निफ्ट से पढ़ाई करनेवाले सार्थक के मन में एक कवि भी आकार ले रहा था। यह उनकी कविताओं का पहला संग्रह है। इसमें उन्होंने जिंदगी से जुड़ी बातों को शब्दों में पिरोया है।

कल पढ़ें कथा श्रेणी में बेस्ट 10 किताबें

गेंदा ने चंबल के डकैतों को बना दिया था क्रांति का सिपाही

नमन ▶ मातृवेदी के कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित का छद्म नाम था फूल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारी यह कोशिश इन अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता जताने के साथ नई पीढ़ी में वही देशभक्ति का भाव जगाने की है, जिसके वशीभूत होकर इन क्रांतिकारियों ने संघर्षों के बीहड़ में जीवन काट दिया। प्रस्तुत है शाह आलम की पुस्तक मातृवेदी से गुमनाम क्रांतिकारियों की एक और कहानी

शिक्षक की नौकरी छोड़कर चुनी क्रांति की राह, मुखबिरी से टूटा इस महानायक का सपना

आशुतोष मिश्र, लखनऊ

क्रांतिकारी संगठन मातृवेदी के कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित को संगठन में कई नामों से जाना जाता था। इनमें से फूल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। अंग्रेजों के खिलाफ इस फूल की खुशबू से उठी बगावत की बयार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैली। आगरा मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर मई में जन्मे गेंदालाल दीक्षित असल में क्रांतिकारियों के द्रोणाचार्य थे। लालच में पड़े अपनों ने उनकी मुखबिरी न की होती तो शायद बिस्मिल और आजाद जैसे कई क्रांतिकारी बलिवेदी पर बलिदान न होते।

शिक्षक की नौकरी छोड़कर क्रांति की राह चुनने वाले गेंदालाल दीक्षित बेमिसाल शख्सियत के धनी थे। इसीलिए तो उन्होंने मातृवेदी के पांच हजार लड़ाका सैनिक तैयार करने के साथ आजादी के संघर्ष के लिए राजस्थान की खारवा रियासत के 10 हजार सिपाहियों का प्रबंध कर लिया था, लेकिन एक मुखबिरी ने आजादी के इस महानायक का सपना तोड़ दिया। अगर ऐसा न हुआ होता तो सन 1918 में 1857 से बड़ी क्रांति हुई होती। वह क्रांतिकारी दल के लिए फंड जुटाने की खातिर सिरसागंज में अंग्रेजों के पिट्ठू सेठ ज्ञानचंद्र के यहां डकैती डालने पहुंचे थे। चंबल घाटी में मातृवेदी के संगठनकर्ता ब्रह्मचारी लक्ष्मणानंद, मन्नू राजा और अध्यक्ष दस्युराज पंचम सिंह के साथ भिंड के जंगलों में पहुंचे। दल थकान और भूख से बेजार था। इसी बीच, भारी धन के लालच में भेदिए हिंद सिंह ने तार पर स्पेशल ड्यूटी पुलिस कमिश्नर यंग को इनकी सूचना दे दी। इधर, इनके खाने में हिंद सिंह ने जहर मिला दिया। खाना खाने के दौरान ब्रह्मचारी लक्ष्मणानंद की जबान ऐंठने लगी तो हिंद सिंह पानी लाने के बहाने वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लक्ष्मणानंद ने बंदूक उठाकर फायर कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों की ओर से भी फायरिंग शुरू हो गई। ब्रह्मचारी को 18 गोलियां लगीं। गेंदालाल दीक्षित को जांघ में छर्रा लगा और आंख को छूते हुए गोली निकल गई।

इस संघर्ष में 50 अंग्रेजी सैनिक मारे गए और 36 क्रांतिकारी शहीद हुए। गेंदालाल को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया। बाकी को भिंड हवालात में बंद किया गया। उधर, मुखबिर दलपत सिंह ने मैनपुरी के जिला मजिस्ट्रेट के आगे मातृवेदी के राज (अगली कड़ी में विस्तार से) खोल दिए। 11 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें गेंदालाल दीक्षित का नाम सामने आया तो उन्हें मैनपुरी लाया गया। उन्होंने सारा दोष खुद पर लेकर कई क्रांतिकारियों को रिहा करा दिया। आरी से सींखचे काटकर दीक्षित जी हवालात से भाग निकले। भूमिगत होकर क्रांति के लिए कार्य करते हुए उन्हें क्षयरोग हुआ और 21 दिसंबर 1920 को दिल्ली के एक अस्पताल में लावारिस के रूप में निधन हो गया। बाद में रामप्रसाद बिस्मिल ने प्रभा मैगजीन में विस्तृत लेख लिखकर उनके बलिदानी जीवन का बखान किया।

डाकू दस्युराज पंचम सिंह (मध्य में), जिन्हें गेंदालाल ने साथ मिलाया था। जागरण आर्काइव

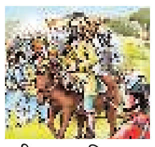

प्रतीकात्मक चित्रण। जागरण

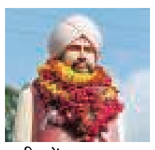

शहीद गेंदालाल दीक्षित की मूर्ति।

यादें नहीं संजोई

हद तो यह रही कि आजादी के इस मतवाले की सुध स्वतंत्रता के वर्षों बाद तक नहीं ली गई। शोधार्थी शाह आलम बताते हैं कि इनके गौरवशाली इतिहास का जिक्र कर औरैया नगर पालिका और दोस्तों का सहयोग लेकर 12 अगस्त 2015 को शहर में उनकी प्रतिमा स्थापित कराई। पैतृक गांव मई में उनकी निशानियों को संजोने का कोई सरकारी प्रयास नहीं हुआ।

डकैतों की बहादुरी और अनुभव का क्रांति में उठाया फायदा

पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1888 को उत्तर प्रदेश के आगरा के मई गांव में हुआ। घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होते हुए भी गेंदालाल ने दसवीं तक पढ़ाई की। घर के खर्चों में हाथ बंटाने के लिए उन्होंने उप्र में औरैया जिले के डीएवी स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार कर ली। इसी दौरान 1905 में हुए बंग-भंग के बाद चले स्वदेशी आंदोलन का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्रांति के इस दौर में गेंदालाल को एक ऐसी योजना सूझी, जो शायद ही किसी को सूझती! उस वक्त डकैतों का बड़ा प्रभाव था। ये डकैत बहादुर तो बहुत थे, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए लोगों को लूटते थे। ऐसे में गेंदालाल ने ऐसा उपाय सोचा, जिससे इन डकैतों की बहादुरी और अनुभव का फायदा स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उठाया जा सकता था। जल्द ही गेंदालाल की शिवाजी समिति के साथ बिस्मिल ने 'मातृवेदी' की स्थापना की।

मैंने आजादी की दुल्हन को अपना सिंदूर तक दे दिया...

सुदामा देवी के हाथ की मेंहदी भी नहीं सूखी थी, क्रांतिकारी पति अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए

संजय सिंह, भागलपुर

जश्न-ए-आजादी के गीतों संग तिरंगा 15 को फिर शान से फहराएगा। आइये, 1942 का रुख करते हैं। आजादी की दुल्हन को संवारने में सर्वस्व न्योछावर कर देने वाली सुदामा देवी की बूढ़ी आंखों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने आजादी की दुल्हन को अपनी मांग का सिंदूर तक दे दिया। वह पीड़ा सीने में ही दफन रही, आज जब हमने पूछा तो बूढ़ीं आंखें बिना कुछ कहे सबकुछ कह उठीं।

तब के रिवाज के मुताबिक सुदामा भी बहुत कम उम्र में दुल्हन बनकर भागलपुर (बिहार) के सोनवर्षा स्थित अपनी ससुराल पहुंच गईं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पति लड्डू कंवर तो आजादी की दुल्हन को घर लाने की जिद में सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। उनकी इसी दीवानगी ने घर आई दुल्हन सुदामा देवी का सब कुछ छीन लिया। 90 से अधिक की हो चुकीं सुदामा देवी को आज भी सन 1942 याद है, जब उन्हें पति की शहादत का संदेश मिला। बूढ़ी आंखों से अतीत छलक पड़ा। वे बताने लगीं- जब देखि लेलियै कि हुनकरो यही मन छै तो हमहुं संग हो गेलियै...(जब मैंने जान लिया कि उनकी यही इच्छा है तो हम भी साथ हो गए...)। साल-दो साल ही तो हुए थे शादी के। तब समझ भी कहां थी? वे बताती हैं, शादी के पहले इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके वाले पति लड्डू कंवर क्या करते हैं। यह सब शादी के बाद पता चला, जब देर रात कुछ लोगों को घर के दरवाजे पर देखा। वे तरह-तरह की बातें करते थे। इस संबंध में जब उनसे पूछती तो वे बातों को टाल जाते। कुछ दिनों बाद भनक लगी कि उनके पति अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ योजना बना रहे हैं। सरदार सिंह, द्वारिका कंवर, फौजी यादव, अर्जुन सिंह वगैरह उनके यहां आते रहते थे। कहती हैं, धीरे-धीरे मुझे सब पता चल गया। और जब उनकी यही इच्छा थी तो मैं भी साथ हो ली। आर्थिक स्थिति खराब थी। वे लोग भोजन और हथियार के लिए इधर-उधर से पैसे जुटाते थे। तब मैंने दहेज में मायके से मिला अपना गहना-जेवर और चांदी के सिक्के उन्हें सौंप दिए। सिर्फ मंगलसूत्र बच गया था। देश के लिए पति के जज्बे ने मुझमें भी देशप्रेम भर दिया था। मैं पति के कर्तव्य को भलीभांति समझते हुए इसे खुद भी आत्मसात कर चुकी थी।

▶ **सन 1942 का वह मंजर आज भी याद है, जब पति की शहादत का संदेश मिला**

भागलपुर, बिहार निवासी सुदामा देवी। जागरण

...और छलके आंखों से आंसू

अंग्रेजों का खौफ इतना था कि परिजनों ने भी पति के शव को पहचानने से इन्कार कर दिया। अंग्रेजों के सिपाही शव लेकर चले गए। इसके बाद मैंने अपने मायके बेनीपट्टी (मधुबनी) के पालीगांव में जाकर चोरी-छिपे कुश का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया। पति की कोई तस्वीर तक नहीं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। आज भी पेंशन का पैसा गरीबों में खर्च कर देती हैं। उनकी सगी बहन के पुत्र रामानंद कुंवर और पोता बमबम उनकी देखभाल करते हैं।

आजादी के दीवानों का गांव

भागलपुर जिला स्थित सोनवर्षा गांव गंगा तट पर है। 1921 में अंग्रेजों ने जबरन यहां के किसानों पर टैक्स लगा दिया। विरोध के स्वर तेज हुए तो उसे कुचलने को रांची से गोरखा फोर्स को बुलाया गया था। किसानों के साथ हुए संघर्ष में आठ गोरखा जवान मारे गए थे। इसका उल्लेख केंद्र सरकार के गृह विभाग के पॉलिटिकल फाइल नंबर 252 में दर्ज है। फिर यहां के किसानों का दूसरा विद्रोह 1942 में हुआ। इसमें 17 सिपाही मारे गए। इसी लड़ाई में इस गांव के लड्डू कंवर शहीद हुए थे।

शिक्षा, प्रण व प्रेरणा के बूते गरीबी को मात

गरीबी के खिलाफ दो गरीब परिवारों के संघर्ष की कहानी, जहां निर्धन माता-पिता ने सोच और श्रम के बूते अपने बच्चों को शिक्षा की सिद्धी दी और पीढ़ियों को समृद्धि का अक्षय उपहार। सड़क किनारे ट्रक सुधारने वाले साधारण मैकेनिक की बेटी एम्स में डॉक्टर बन चुकी है, तो दिव्यांग दूधवाले का बेटा आइआइटी दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा है। इन दो निर्धन परिवारों ने गरीबी को निर्णायक मात दे डाली है। बता दिया है कि गरीबी उन्मूलन कैसे संभव है। यह महज सरकारों के बूते संभव नहीं हो सकता है। सिद्धी से समृद्धि का संकल्प उन सभी को लेना होगा, जो गरीबी को पटखनी देना चाहते हैं। आइये, इन परिवारों की इस जीत का जश्न मनाएं और इन जैसे उन करोड़ों परिवारों को नए उत्साह से भर दें...

स्वतंत्रता के सारथी
समृद्धि की ओर

पिता ट्रक मिस्त्री, बेटी एम्स में डॉक्टर

▶ **रायबरेली में सड़क किनारे गुमटी लगा ट्रकों की मरम्मत करते हैं अबू सईद, बेटी अर्जुमंद ने एमबीबीएस, एमडी कर एम्स में पाई नौकरी**

रसिक द्विवेदी, रायबरेली

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक ट्रक मिस्त्री की बेटी ने सफलता की ऊंची उड़ान भरकर गरीबी के दलदल को सदा के लिए अलविदा कह दिया है। पिता की तरह वह भी काबिल मिस्त्री बन गई है, मगर किसी मशीन की नहीं बल्कि इंसानी शरीर की। उसने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स) में डॉक्टर होने का रुतबा पाया है।

डॉ. अर्जुमंद। जागरण

शहर के किला बाजार स्थित सैयद राजन मुहल्ला निवासी अबू सईद (52) पेशे से ट्रक मिस्त्री हैं। वे शहर के सिविल लाइंस स्थित प्रयागराज-लखनऊ राजमार्ग के किनारे गुमटी लगा ट्रक सुधारने का काम करते हैं। यही इनके परिवार के भरण पोषण का जरिया भी है। बेटी अर्जुमंद जहां और बेटा आमिर सुहैल, दो संताने हैं। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, लेकिन उसने बच्चों की शिक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कठिन श्रम कर अच्छी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया। मां शमीम जहां ने भी शौहर के प्रण को पूरा करने के लिए बच्चों को प्रेरणा से भरा। पति-पत्नी ने सपना सजाया कि बेटी डॉक्टर बने। बेटी ने भी लगन के साथ पढ़ाई की। प्रवेश परीक्षा में ऊंची रैंक लाने के बाद उसे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, जहां से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में एमडी के लिए प्रवेश मिला। जहां वह गोल्ड मेडलिस्ट बनी। अब रायबरेली स्थित एम्स नियुक्तियां निकलीं तो अर्जुमंद ने फार्म भरा और यहां नौकरी हासिल की।

मैं दुनिया का सबसे अमीर पिता...

बेटी जब-जब सफलता के झंडे गाड़ती, सम्मानित किए जाने के लिए उसके माता-पिता को समारोहों में बुलाया जाता। शहरवासी तो पिता को ट्रक मिस्त्री के रूप में ही जानते पहचानते थे। लेकिन जब-जब सम्मान होता, गरीब पिता रो देता। आज गर्व से कहते हैं, ये खुशी के अनमोल आंसू हैं, जो मुझे दुनिया का सबसे अमीर पिता बना देते हैं।

रायबरेली में ट्रक की मरम्मत करते डॉ. अर्जुमंद के पिता अबू सईद। जागरण

दिव्यांग पिता ने दूध बेच बेटे को पहुंचाया आइआइटी दिल्ली

मनीष कुमार, औरंगाबाद

▶ **पिता ने जिद पाली, बेटे ने जुनून, दे दी गरीबी को मात**

▶ **मेहनत और मेधा के आगे मुसीबतों ने टेके घुटने, दूसरों के लिए बने प्रेरणा**

यह कहानी भी प्रेरणा से भर देती है। दिव्यांग पिता की मेहनत और बेटे की मेधा ने गरीबी को मात दे दी। अब कामयाबी की राह निकल पड़ी है। बिहार के औरंगाबाद के एक छोटे से गांव में दूध बेचकर परिजनों का भरण-पोषण करने वाले वेंकटेश पांडेय का होनहार बेटा अंकित आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आइआइटी) दिल्ली में भविष्य की नई बुनियाद गढ़ रहा है। यह कहानी अब दूसरों को भी कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा दे रही।

औरंगाबाद जिले में नक्सल प्रभावित खुदवां थाना अंतर्गत एक गांव है- कलेन। यहां वेंकटेश पांडेय का मिट्टी का कच्चा मकान है। बीत्ता भर जमीन पर खेती-किसानी और आंगन में दो गाय। आजीविका का यही साधन है। खेत से कुछ धान-गेहूं मिल जाता और बाकी के खर्च के लिए दूध बेच लेते। वेंकटेश घर-घर दूध बेचते, फिर भी कमाई इतनी नहीं कि कोई सपना संजो सकें। प्रायः ऐसे ही मोड़ पर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन वेंकटेश ने एक जिद पाली थी। जिद यह कि बेटे को अपने जैसी जिंदगी और गरीबी के लिए अभिशप्त नहीं होने देंगे। बदहाली के इस दौर से निकालकर उसे समाज की अगली पंक्ति में लाएंगे।

कलेन में शिक्षा की सुविधा बेहतर नहीं। विद्यालय बहुत दूर। राह लंबी और बीच में पुनपुन नदी। इसी कारण कलेन के अधिसंख्य बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते। अंकित के भविष्य के लिए लिए वेंकटेश व्याकुल थे। अब निर्णय की बारी थी। जिला मुख्यालय स्थित एक निजी विद्यालय में अंकित का नामांकन कराने का निर्णय ले लिया। इसके लिए उन्हें अपनी थाली तक में कटौती करनी पड़ी। एक-एक कक्षा उत्तीर्ण करता अंकित भविष्य की एक-एक सीढ़ी चढ़ने का अहसास कराता रहा। वर्ष 2017 में वह सीबीएसई से हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद पटना से इंटर की पढ़ाई पूरी की। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंटर के बाद की पढ़ाई कुछ ज्यादा महंगी थी। एक क्षण तो वेंकटेश को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, लेकिन अंकित की मेधा ने आगे की राह आसान कर दी। वह पूर्व डीजीपी अभयानंद द्वारा संचालित सुपर-30 की परीक्षा में बाजी मारने में सफल हुआ। आज वह आइआइटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग का छात्र है।

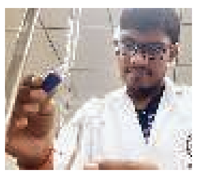

दिल्ली स्थित आइआइटी की प्रयोगशाला में अंकित। जागरण

औरंगाबाद, बिहार स्थित अपने घर के आंगन में माता-पिता के साथ अंकित। जागरण

समाज की एक छोटी सी पहल और मदर गरीबों के घर में खुशहाली ला सकती है। उनके बुझे अरमानों को रोशन कर सकती है। संघर्ष और हौसले की बदौलत अंकित को जीवन की मंजिल मिली है। उसमें गजब की मेधा है। वह अभी और उड़ान भरेगा।
-अभयानंद, पूर्व डीजीपी

अंकित की कामयाबी से मेरे जीवन का तूफान भी पस्त हो गया। मैं आश्वस्त हूं कि मेरी लड़खड़ाती गृहस्थी भविष्य में सम्मानजक पायदान पर पहुंचेगी। आने वाली पीढ़ियां गरीबी के दलदल से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगी।
-वेंकटेश पांडेय, अंकित के पिता

संरक्षण

एक साल में 11 धरोहरों को बनाया राष्ट्रीय स्मारक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कोशिशें रंग लाईं, स्मारकों चार मंदिर भी शामिल, देश में राष्ट्रीय स्मारकों की संख्या अब 3,697 हो गई है

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने एक साल में देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण 11 धरोहरों को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। खास बात यह है कि इन स्मारकों में चार मंदिर शामिल हैं। ये स्मारक उत्तराखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और जम्मू-कश्मीर में स्थित हैं। इन्हें मिलाकर देश में राष्ट्रीय स्मारकों की संख्या 3,586 से बढ़कर 3,697 हो गई है।

राष्ट्रीय स्मारक होने के नाते अब इन मंदिरों के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इन स्मारकों में ओडिशा के बोलंगीर स्थित रानीपुर झारियाल मंदिर समूह, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित कोटली का विष्णु मंदिर, केरल के वायनाद स्थित जनार्दन मंदिर, जम्मू कश्मीर के कठुआ स्थित त्रिलोचननाथ मंदिर शामिल है। देहरादून स्थित जगतग्राम का अश्वमेध यज्ञ स्थल को भी राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के वीरपुर खुर्द का वीरभद्र ऋषिकेश खोदाई स्थल को भी राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। किसी खोदाई स्थल को विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाता है। इसके लिए लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जिसमें सालों लग जाते हैं। मगर एएसआइ ने अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक इस कार्य का अंजाम दिया है।

बनाए गए स्मारकों की सूची
ओडिशा के बोलंगीर स्थित रानीपुर झारियाल मंदिर समूह
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित कोटली का विष्णु मंदिर
केरल के वायनाद स्थित जनार्दन मंदिर
जम्मू कश्मीर के कठुआ स्थित त्रिलोचननाथ मंदिर
उत्तराखंड के देहरादून स्थित जगतग्राम का अश्वमेध यज्ञ
उत्तराखंड के वीरपुर खुर्द का वीरभद्र ऋषिकेश स्मारक
नागपुर स्थित हाईकोर्ट की पुरानी इमारत
हाथी खाना, आगरा
आगा खां की हवेली, आगरा
राजस्थान के अलवर स्थित नीमराना की ऐतिहासिक बावली
लेह स्थित वालना का ऐतिहासिक गोपा कांप्लेक्स।

अश्वमेध यज्ञ स्थल स्मारक : विकासनगर से छह किलोमीटर दूर कालसी के समीप बाड़वाला नामक स्थान पर एक सघन आम के बाग के बीच अदृश्य और उपेक्षित किंतु अत्यधिक महत्व का ऐतिहासिक स्थल जगत ग्राम है। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सन 1952 से 1954 के बीच किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया। इस उत्खनन में पक्की ईंटों से निर्मित तीसरी शताब्दी की उड़ते हुए गरुण के आकार वाली तीन यज्ञ वेदिकाओं का अनावरण हुआ, जो आसपास के धरातल से तीन-चार फीट नीचे दबी पड़ी थीं। इन यज्ञ वेदिकाओं को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अखिल भारतीय संदर्भ में दुर्लभतम माना है। तीन वेदिकाओं में से एक वेदिका की ईंटों पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण सूचना के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आए, उनके अनुसार ईसा की पहली से पांचवीं सदी के बीच वर्तमान सरसावा, हरिपुर, विकासनगर और संभवतः लाखामंडल तक युग शैल नामक एक साम्राज्य था। जिसकी राजधानी हरिपुर थी। यह साम्राज्य बृषगण गौत्रीय वर्मन वंश द्वारा शासित था। इस साम्राज्य का उत्कर्ष काल तीसरी शताब्दी में शील वर्मन नामक परम शक्तिशाली राजा हुए, उन्होंने जगतग्राम पर चार अश्वमेध यज्ञ कर अपने उत्कर्ष का प्रदर्शन किया। इन्हीं अश्वमेध यज्ञों में से तीन यज्ञों की वेदिकाएं हैं और चौथा स्थल अभी खोजना बाकी है।

ऋषिकेश स्थित वीरभद्र खोदाई स्थल

वीरभद्र में 1973 से 1975 के बीच एएसआइ ने खोदाई कराई थी। जिसमें तीन सांस्कृतिक स्थल प्रकाश में आए। जिनका प्रारंभिक काल एक शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी, दूसरे भाग में खोदाई में चौथी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी और तीसरे भाग की खोदाई में 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के प्रमाण मिले हैं। यहां खोदाई में मिट्टी के घरों के निर्माण के अलावा शिव मंदिर के भी प्रमाण मिले हैं। माना जाता है कि कोई संपन्न सभ्यता के हिंदू लोग यहां रहते रहे होंगे।

चारधाम यात्रा मार्गों पर खुलेंगे मोबाइल पेट्रोल पंप

राज्य ब्यूरो, देहरादून : कोशिशें परवान चढ़ीं तो निकट भविष्य में चारधाम यात्रा मार्गों के साथ ही राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को पेट्रोल-डीजल की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके लिए मोबाइल पेट्रोल पंप (पेट्रोल-डीजल डिस्पेंसर) स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात के दौरान यह संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल पेट्रोल पंप के लिए नियमावली तैयार हो रही है। इसके बाद यहां भी चारधाम समेत दूरस्थ क्षेत्रों के मार्गों पर ये सुविधा मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।

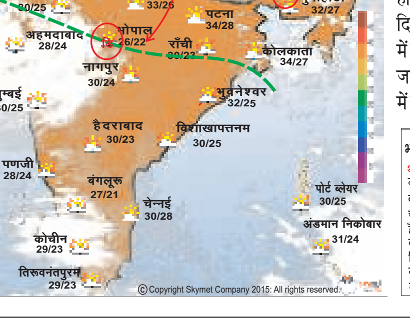

मौसम विशेष

दक्षिण राजस्थान में वर्षा में कमी आएगी लेकिन मध्यम वर्षा तेज हवाओं के साथ जारी रहेगी। पंजाब और सटे हुए हरियाणा में हल्की वर्षा होगी तथा राजस्थान के शेष भाग, दिल्ली और पश्चिमी हरियाणा में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	28/24/व	अहमदाबाद	32/25/आंबा
कोलकाता	35/28/व	बड़ौदा	32/25/व
चेन्नई	36/28/व	नागपुर	30/23/व
हैदराबाद	30/24/व	इन्दौर	28/23/व
बंगलूरू	27/20/व	रांची	32/26/व
त्रिवेन्द्रम	29/23/व	पटना	33/28/आंबा
गुवाहाटी	32/27/व	जमशेदपुर	33/26/व
गंगटोक	18/13/आंबा	पुणे	24/22/आंबा

दर्द निवारक दवा एस्पिरिन का आविष्कार किया

1897 में आज ही जर्मन केमिस्ट फेलिक्स हॉफमैन ने दर्द निवारक दवा एस्पिरिन का आविष्कार किया था। एस्पिरिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवाओं में से एक है। प्रति वर्ष इसकी 50 से 120 अरब गोलियों की खपत होती है।

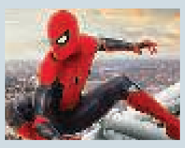

पहली बार कॉमिक्स में नजर आया स्पाइडर मैन

1962 में आज ही बच्चों का पसंदीदा कार्टून स्पाइडर मैन पहली बार अमेजिंग फैंटेसी नामक कॉमिक्स में नजर आया था। इस काल्पनिक सुपर हीरो को लेखक-संपादक स्टेन ली और लेखक-कलाकार स्टीव डिटको ने डिजायन किया था। स्पाइडर मैन पर कई सारी फिल्में और कार्टून सीरियल भी बन चुके हैं।

पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने दिलाई शास्त्रीय संगीत को नई पहचान

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 1860 में आज ही मुंबई में हुआ था। शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए भातखंडे ने संगीत-शास्त्र की रचना की तथा कई संस्थाएं तथा शिक्षा केंद्र स्थापित किए। उन्होंने संगीत पर संस्कृत, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में किताबें लिखीं। उनकी पहली किताब थी स्वर मालिका। उन्होंने इस संगीत पर प्रथम आधुनिक टीका लिखी। उन्होंने करीब दो हजार बंदिशें इकठ्ठा की थीं। इसके अलावा 200 राग तैयार किए। उनकी पुस्तकों को राग का खजाना भी कहा जाता है। 19 सितंबर, 1936 को उनका देहांत हो गया।

इधर-उधर की

म्यूजियम थेरेपी से ठीक हो रहे मरीज

ओटावा, एजेंसी : कनाडा में मरीजों को ठीक करने में म्यूजियम थेरेपी असर दिखा रही है। यहां डॉक्टर मरीजों को म्यूजियम के फ्री वाउचर देते हैं, ताकि वे आराम से घूम सकें। 19 महीने में 185 वाउचर पर 740 मरीज म्यूजियम घूम चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप सभी 740 मरीजों की हालत में काफी सुधार देखा गया। पिछले साल नवंबर में मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स की टीम ने मेडिसिंस फ्रांसोफोन्स डु कनाडा (एमएफडीसी) के साथ योजना बनाई थी। इसके तहत डॉक्टर मरीजों को म्यूजियम विजिट के फ्री वाउचर देते हैं, ताकि मरीजों में जीने का उत्साह बढ़े और वे जल्द ठीक हों। मॉन्ट्रियल म्यूजियम में एक व्यक्ति के टिकट का रेट 2,178 रुपये है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा दिये गए वाउचर पर चार लोगों को फ्री विजिट मिलती है।

पैंक्रियाज की बीमारी का पता लगाने वाली डिवाइस असुरक्षित

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : वैज्ञानिकों ने बीते दशकों में कई ऐसी तकनीक व डिवाइस विकसित की हैं, जिससे बीमारियों की पहचान व उनका इलाज आसान हुआ है। इन्हीं डिवाइसों में से एक डूयोडेनोस्कोप का इस्तेमाल पैंक्रियाज और बाइल डक्ट (लिवर से छोटी आंत तक जाने वाली नली) में होने वाली बीमारियों का पता लगाने में किया जाता है। दुनियाभर के अस्पतालों में इसका प्रयोग आम है। हर साल करीब पांच लाख लोगों के शरीर में इस डिवाइस को डाला जाता है। अब इस डिवाइस के पूरी तरह सुरक्षित ना होने का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसे पूरी तरह स्टरलाइज करना संभव नहीं है। इससे एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके रोगाणुओं के संक्रमण का खतरा हो सकता है।

किस तरह करता है काम? : डूयोडेनोस्कोप सांप की आकृति जैसा लचीला ट्यूब है जिसके एक सिरे पर फाइबर ऑप्टिक कैमरा लगा होता है। मरीज के मुंह के रास्ते इस डिवाइस को छोटी आंत के पहले हिस्से में भेजा जाता है। फिर इसके जरिये एंडोस्कोपी की जाती है, जिससे पैंक्रियाज, गॉल ब्लेडर आदि में होने वाली पथरी या ट्यूमर जैसी घातक बीमारियों का पता लगता है।

- डूयोडेनोस्कोप को पूरी तरह स्टरलाइज करना संभव नहीं, बढ़ जाता घातक संक्रमण का खतरा
- इसका इस्तेमाल बंद करने की हो रही है मांग

आंतों की बीमारियों का पता लगाने के लिए होता है डूयोडेनोस्कोप का प्रयोग।

स्टरलाइज करने पर भी बच जाता बैक्टीरिया : एंडोस्कोपी के दौरान इस डिवाइस को कई बार इस्तेमाल में लाया जाता है। दोबारा इस्तेमाल किए जाने से पहले डिशवाशर की तरह के मशीन में कई रसायनों की मदद से इस डिवाइस को स्टरलाइज किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना के विलियम ए. रुताला ने कहा, 'स्टरलाइज करने के बाद भी इस डिवाइस में 200 में से एक बैक्टीरिया बच जाता है। इससे मरीज को लाइलाज संक्रमण हो सकता है।' अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के मुताबिक, 20 में एक डूयोडेनोस्कोप पर ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। इस शोध के बाद डूयोडेनोस्कोप को पूरी तरह स्टरलाइज करने का तरीका निकालने या इसका इस्तेमाल बंद करने की मांग की जा रही है।

समस्याएं बढ़ने पर होता है कैंसर : पैंक्रियाज में होने वाली समस्याएं यदि बढ़ जाती हैं तो यह कैंसर का रूप ले लेती हैं और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते। ज्यादातर मामलों में उस समय लक्षण दिखाई पड़ते हैं जब या तो प्रभावित हुई कोशिकाओं का आकार काफी बढ़ जाता है या ये पैंक्रियाज के बाहर फैल चुके होते हैं। शुरुआती चरण में ही किसी भी समस्या का पता करने के लिए डॉक्टर डूयोडेनोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं।

वैज्ञानिकों ने बनाया सबसे छोटा स्टेंट

आविष्कार ▸ अब भ्रूण में ही हो सकता है यूरिन की सिकुड़ी हुई नलिकाओं का इलाज

एडवांस मैटेरियल टेक्नोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ अध्ययन

जेनेवा, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे छोटा स्टेंट बनाने में सफलता हासिल की है। यह वर्तमान में मौजूद अन्य स्टेंट्स की तुलना में अत्यंत छोटा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी मदद से भविष्य में भ्रूण में ही यूरिन की सिकुड़ी हुई नलिकाओं के उपचार संभव हो सकता है।

स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्थित फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ समय से स्टेंट का उपयोग अवरुद्ध हुई कोरोनरी वाहिकाओं (ब्लॉक कोरोनरी वेसल्स के उपचार के लिए किया जाता रहा है, लेकिन यूरिन (मूत्र) की सिकुड़ी हुई नलिकाओं के उपचार में स्टेंट का उपयोग करना बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाता। क्योंकि कई बार स्टेंट का आकार नलिकाओं की तुलना बहुत बड़ा होता है। ऐसे में सर्जरी के जरिये सिकुड़ी हुई नलिकाओं का हटाकर उन्हें दोबारा सिल दिया जाता है। यह प्रक्रिया खर्चीली तो है ही साथ ही इसमें जोखिम भी बहुत रहता है। ऐसे में नए स्टेंट यूरिन की नलिकाओं के उपचार में कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

कोरोनरी वेसल्स के ब्लॉकेज खोलने के लिए होता है स्टेंट का इस्तेमाल।

- 100 माइक्रोमीटर से कम है नए स्टेंट का व्यास
- यूरिन की नलिकाओं के सिकुड़ने से खराब हो जाती है किडनी
- नए स्टेंट से इलाज की नई राह खुलने की उम्मीद

हजार लोगों में मिलता है एक केस : शोधकर्ताओं ने कहा कि हजार लोगों में से एक मामला ऐसा मिलता है, जिसमें व्यक्ति के यूरिन की नलिकाएं सिकुड़ी हुई मिलती हैं। सामान्य तौर पर यह या तो गंभीर चोट लगने के कारण होता है या गर्भ में भ्रूण के विकास के दौरान यूरिन की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि जन्म के बाद इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ कई बार इस समस्या का समय रहते पता लग जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ढलती उम्र में इसका पता लग पता है।

किडनी हो सकती है खराब : यह अध्ययन 'एडवांस मैटेरियल टेक्नोलॉजी' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि यूरिन की नलिकाओं के सिकुड़ जाने से किडनी का काम प्रभावित होता है और यदि समय रहते उपचार नहीं किया गया है किडनी खराब तक हो जाती है। ऐसे में जांच के बाद यदि स्टेंट को गर्भ के भ्रूण में डाल कर उसकी यूरिन की नलिकाओं को चौड़ा कर दिया जाए तो किड़नी को खराब होने से बचाया जा सकता है।

'इनडायरेक्ट 4डी प्रिंटिंग' से बनाया स्टेंट : इस अध्ययन के लेखक कार्मेला डे मार्को ने कहा कि पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके इतना छोटा स्टेंट को बना पाना संभव नहीं है। इसके लिए आरगाउ कैंटोनल अस्पताल के बाल रोग सर्जन गैस्टन डी बर्नार्डिस ने ज्यूरिख की मल्टी-स्केल रोबोटिक्स लैब से संपर्क किया, जिसके बाद लैब के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक नई विधि विकसित की है। इसकी मदद से उन्होंने 100 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले स्टेंट का निर्माण किया। शोधकर्ताओं ने नई विधि को 'इनडायरेक्ट 4डी प्रिंटिंग' नाम दिया है।

परीक्षण होना बाकी : डी बर्नार्डिस ने कहा कि नया स्टेंट यूरिन की सिकुड़ी हुई नलिकाओं के उपचार के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसे प्रभावित हिस्से में धक्का देकर डाला जाता है। जहां यह स्वयं ही फैलकर संकुचित हिस्से को चौड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी इस स्टेंट का उपयोग उपचार के लिए नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पहले इसे कई परीक्षणों के दौर से गुजरना है। बर्नार्डिस ने उम्मीद जताई है कि नया स्टेंट अपने परीक्षण में भी खरा उतरेगा और इलाज की नई राह खोलेगा।

फिल्म रिव्यू

जबरिया जोड़ी

निर्देशक : प्रशांत सिंह
मुख्य कलाकार : सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, अपारशक्ति खुराना, चंदन रॉय सान्याल
अवधि : 2 घंटे 23 मिनट

सामाजिक संदेश के फेर में फिसली

यह फिल्म बिहार और उत्तर प्रदेश में बंदूक की नोंक पर जबरन विवाह (पकड़वा विवाह) कराने पर आधारित है। कुंवारे लड़के की नौकरी से उसका दहेज तय होता है। दहेज दे पाने में अक्षम माता-पिता दबंगों की मदद से पकड़वा विवाह को विवश होते हैं। फिल्म दहेजप्रथा की कुरीतियों पर प्रहार करने और सामाजिक संदेश देने के फेर में फिसलती नजर आती है।

कहानी का आरंभ अभय सिंह और बबली यादव के स्कूली दिनों से होता है। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। कहानी वर्तमान में पहुंचती है। बबली जवान हो चुकी है। वह अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए घर से भागती है। हालांकि उसका प्रेमी धोखा दे जाता है। वह उसकी सरेआम पिटाई करके सुर्खियों में छा जाती है और 'बबली बम' के तौर पर विख्यात हो जाती है। वह अपनी दोस्त की जबरिया शादी के दौरान बचपन के साथी और दबंग अभय सिंह से मिलती है। पटना निवासी अभय अपने पिता द्वारा संचालित पकड़वा विवाह कराने को समाज सेवा समझता है। उसके पिता का रसिकमिजाज स्वभाव है। उसे डर है कि पिता की तरह आगे चलकर वह भी बबली से बेवफाई न कर बैठे। दोनों की आपसी रस्साकशी के बीच बबली ही अभय का अपहरण करवा लेती है। दोनों की जिंदगी में क्या उतार-चढ़ाव आते हैं, कहानी यह बताती है।

हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्म 'जबरिया जोड़ी' में दहेज प्रथा और पकड़वा विवाह जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। लेखक संजीव झा ने संवादों के जरिए बताने का प्रयास किया है कि जबरन की गई शादी दहेज प्रथा से भी ज्यादा खतरनाक है। जबरन शादी के मामले लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। हालांकि कहानी सामाजिक मुद्दों के बजाय अन्य विषयों को समेटने के फेर में उलझ जाती है। मसलन फिल्म के एक दृश्य में किन्नर जब अभय को बेटा होने की दुआ देता है तो वह कहता है बेटी क्यों नहीं?

खैर, कहानी पटना की है, हालांकि शूटिंग लखनऊ में हुई है। वर्ष 2014 में रिलीज फिल्म 'हंसी तो फंसी' में साथ नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा करीब पांच साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर फिर साथ नजर आए हैं। बिहारी किरदारों को निभाने के बावजूद दोनों कलाकारों में मुंबइयापन साफ नजर आता है। लिट्टी-चोखा खाने का उनका तौर-तरीका और बबली बनी परिणीति का पहनावा कहीं से भी बिहारी परिवेश का चित्रण नहीं करते। अभय की भूमिका में सिद्धार्थ रंगबिरंगी शर्ट, चटक गमछा और स्टाइलिश चश्मा पहनने के बावजूद मुंबइया ही लगते हैं। परिणीति का बबली बम से बेचारी लड़की बनना अटपटा है। वह भावनात्मक दृश्यों में कमजोर लगती हैं। सहयोगी कलाकारों की भूमिका में आए कलाकार अपनी दमदार अदायगी से रोचकता बनाए रख पाते हैं। बबली के पिता की भूमिका में नींद में चलने वाले संजय मिश्रा और पारिवारिक दोस्त नीरज सूद की जुगलबंदी और डायलॉग हास्य पैदा करते हैं। राज शांडिल्य द्वारा लिखे संवाद में कुछ बॉलीवुड की हस्तियों के नामों का उपयोग कर की गई कॉमेडी दिलचस्प है। वहीं सिद्धार्थ के पिता की भूमिका में जावेद जाफरी अपनी कॉमेडी, आचार-विचार और व्यवहार से छाप छोड़ते हैं। अपारशक्ति की अपार प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाया है। उनके किरदार को समुचित तरीके से गढ़ा नहीं गया। हालांकि उनका शायरी का अंदाज लुभावना है। बाकी अब फिल्मों में परिवेश के मुताबिक गीत-संगीत कम ही बनाया जाता है। यहां भी वही हाल है। एडिटर देव राव जाधव कुछ अनावश्यक दृश्यों पर कैंची चलाकर उसकी अवधि कम कर सकते थे।

-स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

शोध अनुसंधान

किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है फ्लोराइड

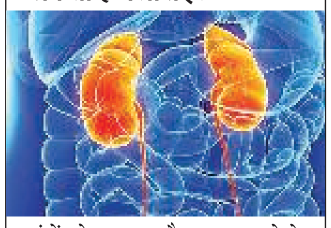

दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए फ्लोराइड काफी फायदेमंद है। इसी के चलते शहरों में पीने का पानी सप्लाई करने वाली कई संस्थाएं पानी में अलग से भी फ्लोराइड मिलाती हैं। हालिया शोध में सामने आया है कि फ्लोराइड दांतों के लिए भले ही अच्छा हो लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। फ्लोराइड से युवाओं को किडनी और लिवर की कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस शोध के लिए 1,983 लोगों के रक्त और 1,742 घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा का पता लगाया गया। इनके तुलनात्मक अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों के लिवर और किडनी पहले से ही कमजोर हैं उनका शरीर अन्य के मुकाबले अधिक मात्रा में फ्लोराइड का अवशोषण करता है। शोधकर्ता एश्ले जे मालिन ने कहा, 'जो व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में फ्लोराइड का ग्रहण करता है, उसके लिवर और किडनी को नुकसान होने का खतरा उतना अधिक रहता है।' (एएनआइ)

पौधों से मिलने वाले आहार से स्वस्थ रहता है हृदय

हृदय के स्वास्थ्य के लिए जानवरों से प्राप्त किए जाने वाले खाद्य पदार्थ मीट आदि की अपेक्षा शाकाहार अधिक फायदेमंद है। एक शोध के अनुसार, पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक आदि का खतरा कम हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में छपे शोध से जुड़े केसी एम रेबोल्ज ने कहा, 'हम मीट आदि त्यागने की नहीं बल्कि अधिक से अधिक शाकाहारी भोजन खाने की सलाह दे रहे हैं।' हृदय के स्वास्थ्य पर शाकाहार के फायदे का पता लगाने के लिए 1987 से 2016 के बीच करीब दस हजार लोगों पर शोध किया गया। शोध शुरू होने से पहले कोई भी प्रतिभागी हृदय रोग से ग्रसित नहीं था। शोधकर्ताओं का कहना है कि पौधों से प्राप्त होने वाले आहार में हार्ट फेल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 16 फीसद कम हो जाता है। (एएनआइ)

मॉस्को की आकर्षक फूलों की घड़ी

मॉस्को की पोकलोनया पहाड़ पर बनी फूलों की घड़ी इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी फूलों की घड़ियों में से एक है। हर सीजन में इसका रंग रूप बदलता है। साल 2001 से हर वर्ष इसे सजाने के लिए सात हजार किस्म के फूल लगाए जाते हैं। इसका व्यास दस मीटर है और मिनट वाली सुई का वजन तीस किलोग्राम से अधिक है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

तैमूर को क्रिकेटर बनाने की दबी ख्वाहिश रखती हैं करीना

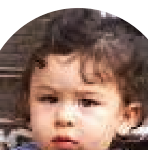

सैफ अली खान और करीना कपूर के साहबजादे तैमूर से उम्मीद की जा रही है कि बड़े होकर वह अपने माता-पिता की तरह अभिनय में नाम रोशन करेंगे। अभी इसमें वक्त है, फिर भी बच्चों के करियर को लेकर हर माता-पिता के दिल में हसरतें होती हैं। करीना की भी दबी ख्वाहिश है कि उनका बेटा अपने दादा मंसूर अली खान पटौदी की तरह क्रिकेटर बने। उन्होंने यह ख्वाहिश जीटीवी के डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस : बैटल ऑफ द चैंपियंस' में व्यक्त की। शो में करीना बतौर जज शिरकत कर रही हैं। शो में 73वें स्वतंत्रता दिवस को हैप्पी बर्ड थे इंडिया थीम के तहत मनाया जा रहा है। शो में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और गजल गायक शैलेंद्र सिंह बतौर अतिथि शामिल हुए थे। कपिल देव को निकट पाकर करीना अपनी ख्वाहिश व्यक्त करने में चूकीं नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े होने पर तैमूर जो भी करना चाहेगा, उसमें उन्हें खुशी होगी। हालांकि उनकी दबी हुई ख्वाहिश यह है कि वह क्रिकेटर बने।

प्रेग्नेंसी की वजह से गालियां देना मुश्किल था : सुरवीन चावला

नेहा धूपिया, करीना कपूर खान जैसी कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं, जो गर्भावस्था के दौरान भी काम करती रहीं। अभिनेत्री सुरवीन चावला भी उन्हीं महिलाओं में से हैं। इसी वर्ष 15 अप्रैल को एक बेटी की मां बनीं सुरवीन जब गर्भवती थीं, तब वह 'सेक्रेड गेम्स सीजन 2' की शूटिंग कर रही थीं। फिल्म में उनका जोजो का किरदार पहले सीजन में कई सवाल छोड़ जाता है। दूसरे सीजन में सुरवीन का ट्रैक सभी सवालों के जवाब देगा। उनका किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार गणेश गायतोंडे के काफी करीब है। ट्रेलर में सुरवीन भी गालियां देती नजर आ रही हैं। ऐसे में जब सुरवीन से पूछा गया कि उन्हें महिला होने के नाते गालियां देने में किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? जवाब में सुरवीन ने कहा कि गाली-गलौज की वजह से यह किरदार निभाना मुश्किल नहीं था। यह किरदार दूसरे कारणों की वजह से मुश्किल रहा, क्योंकि जब मैं यह किरदार निभा रही थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी। सुरवीन कहती हैं कि वह कलाकार हैं और यह उनका काम है। बकौल सुरवीन, 'मुझे फिल्म में किसी से प्यार करना है तो मैं वह भी शिद्दत से करूंगी। एक एक्टर होने के नाते यह हमारा काम है। पुरुष या महिला में फर्क करना कि यह महिला है तो गालियां देने में दिक्कत होगी तो यह असमानता वाली बात हो जाएगी।'

जब मिल बैठे देसी ब्वॉयज

जब मिले देसी ब्वायज, तो धमाल होना तो तय था। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम दोनों ने 'हाउसफुल 2', 'गरम मसाला' और 'देसी ब्वॉयज' जैसी फिल्में साथ की हैं। दोनों का याराना भी दमदार है, लेकिन इस बार दोनों बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने हैं। अक्षय की 'मिशन मंगल' और जॉन की 'बटला हाउस' 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। खास बात यह है कि दोनों ही फिल्मों का पीआर भी एक ही कंपनी कर रही है। ऐसे में दोनों एक ही जगह मीडिया इंटरव्यू दे रहे थे। अक्षय ने जॉन के साथ प्रमोशन के दौरान एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह जॉन के कंधे पर सवार हैं। अक्षय ने अपनी फिल्म के गाने की लाइनें लिखने के साथ लिखा हैं, 'एक साथ हम हमेशा बवाल करते हैं।' हैशटैग के साथ अक्षय ने लिखा है 'ब्रदर फ्रॉम एनॉदर मदर।'

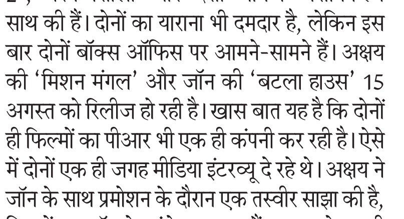

शाहिद कपूर की 'डिंको सिंह' रुकी

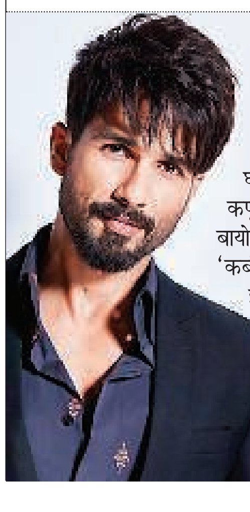

करीब छह महीने पहले यह घोषणा की गई थी कि शाहिद कपूर मुक्केबाज डिंको सिंह की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाएंगे। 'कबीर सिंह' फेम अभिनेता ने भी इस फिल्म के प्रति अपनी उत्सुकता जाहिर की थी। फिल्म की घोषणा के साथ यह भी जानकारी दी गई थी कि इस फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। हालांकि अब ताजा खबर यह है कि फिल्म को लेकर कोई काम पूरा नहीं हुआ है और इस वजह से मेकर्स ने इसे होल्ड पर रख दिया है। फिल्म के निर्देशक राजा कृष्ण मेनन ने बताया कि पिछले दो-तीन सप्ताह से फिल्म के हीरो देश से बाहर हैं और उन्हें अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले कुछ वक्त चाहिए। मेनन ने कहा कि हालांकि फिल्म काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन न तो शाहिद कपूर के पास समय है और न ही मेरे पास। उन्होंने यह भी कहा कि शाहिद की पिछली फिल्म 'कबीर सिंह' की अप्रत्याशित सफलता के कारण परिस्थितियां बदल गई हैं। वैसे खबर यह भी है कि निर्देशक ने भी फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है और कहा है कि जब शाहिद तैयार हो जाएंगे, तब इस फिल्म की सभी चीजें तैयार मिलेंगी।

जलवायु परिवर्तन का असर

दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं जोशुआ के पेड़, कैलिफोर्निया में कोलोराडो से मोजावे रेगिस्तान तक फैला है जोशुआ ट्री पार्क

इस सदी के अंत तक खत्म हो सकते हैं जोशुआ

लॉस एंजिलिस, एएफपी : जलवायु परिवर्तन के कारण न सिर्फ हिमालय पिघल रहे हैं बल्कि इसका असर पृथ्वी पर मौजूद पेड़-पौधों पर भी पड़ रहा है। एक नए अध्ययन के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले जोशुआ के पेड़ों की प्रजाति इस सदी के अंत तक पूरी तरह से गायब हो सकती है।

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी शोधकर्ताओं की एक टीम ने जोशुआ ट्री पार्क में पेड़ों पर बढ़ती गर्मी के प्रभाव का आकलन किया है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन पर एक सरकारी पैनल द्वारा एकत्र किए गए डाटा का उपयोग किया। यह पार्क दक्षिणी कैलिफोर्निया में कोलोराडो से मोजावे रेगिस्तान तक फैला है। जोशुआ युक्का ब्रेविफोलिया नामक एक पौधे की प्रजाति है। यह वास्तविकता में पेड़ नहीं है, लेकिन कभी-कभी पेड़ की तरह ही दिखाई देते हैं।

शोधकर्ताओं ने कहा कि जोशुआ पूरी मानव प्रजाति के लिए एक आशा की किरण है। क्योंकि यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है। लेकिन शायद जलवायु परिवर्तन के कारण इस सदी के अंत तक 80 फीसद जोशुआ के पेड़ समाप्त हो जाएंगे, जो कि एक चिंता का विषय है।

अमेरिका में पाए जाते हैं जोशुआ के पेड़। फाइल

- ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करते हैं जोशुआ
- इन पेड़ों के समाप्त होने से बढ़ सकता है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान
- तीन से सात इंच तक बारिश में कमी की जा सकती है दर्ज

शोधकर्ताओं ने कहा कि यदि हम व्यापारिक नजरिये से देखें तो अध्ययन इस बात की ओर संकेत देता है कि इस सदी के अंत तक प्लाइस्टोसीन युग के इस पौधों (पेड़ों) की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो सकती है।

नौ डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान : इस अध्ययन के मुख्य लेखक लिन स्वीट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का जोशुआ के पेड़ों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके कारण गर्मियों में औसतन पांच से नौ डिग्री फॉरेनहाइट (2.8 से 5 डिग्री सेल्सियस) की वृद्धि हो सकती है और बारिश में तीन से सात इंच तक की कमी दर्ज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि जोशुआ के पेड़ ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं तो इसका मतलब है कि वह पहले से ही ऐसी परिस्थिति में रहने योग्य हैं।

मॉर्मन यात्रियों ने दिया था दूसरा नाम : जोशुआ के पेड़ों का दूसरा नाम सेमिनल यू 2 भी है। यह नाम मॉर्मन यात्रियों के एक समूह ने रखा है, जिन्होंने 19 वीं शताब्दी में मोजावे रेगिस्तान को पार किया था। उन्होंने इसे यह नाम इसलिए दिया क्योंकि इन पड़ों ने उन्हें यह याद दिलाया कि बाइबिल की जोशुआ ने प्रार्थना के दौरान अपने हाथों को ठीक उसी प्रकार आसमान की तरफ उठाया था जैसे इन पेड़ों की शाखाएं आसमान की ओर उठी रहती हैं।